राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन से गांगुली नाराज

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 45

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 25 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सैनिक बनाने के बाद ही इकलौते बेटे को पहनाया सेहरा

तरनतारन : शहीद बलविंदर सिंह की पत्नी बलजीत कौर बताती हैं कि उन्होंने पति के अंतिम संस्कार के समय मन में ठान लिया था कि बेटे सिमरजीत सिंह के सिर पर तभी सेहरा सजाएंगी, जब वह फौजी बन जाएगा...। (पेज-13)

सरोकार

स्मार्ट खेती : 50 फीसद पानी, 20 फीसद लागत कम

करनाल : क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल के तहत सब-सर्फेस ड्रिप इरीगेशन से धान, मक्का और गेहूं की फसल लेने का सफल प्रयोग केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में हो रहा है। पानी की खपत में 50 फीसद और लागत में 20 फीसद की कमी दर्ज की गई है। (पेज-13)

जागरण विशेष

उखाड़े गए पेड़ों से फूटीं उम्मीद की कोपलें

मेरठ : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक ऐसी चुनौती पूरी की है, जो नजीर बन गई है। एक्सप्रेस-वे निर्माण की राह में बाधक सैकड़ों पेड़ों को सिर्फ जड़ समेत स्थानांतरित ही नहीं किया गया, बल्कि गर्मी से बचाकर उन्हें नया जीवन भी दे दिया। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अवैध रेत खनन मामले में केंद्र और पांच राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर रोक लगाने और अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और पांच राज्यों तथा सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पांच राज्यों में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ये नोटिस बुधवार को न्यायाधीश एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता एम अलागरसामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए।

कारोबार ▶ पृष्ठ 10

एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को चुकाने होंगे 3,050 करोड़

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च निर्णायक संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने बुधवार को भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के ट्राई के फैसले को मंजूरी दे दी। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, 'डीसीसी ने एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने की टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब डीसीसी अपनी यही सिफारिश सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।'

शाहबेरी के दोषी बिल्डरों पर लगेगा रासुका

बोले योगी ▶ अवैध कालोनियां विकसित होने के मामले में लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्रवाई

जागरण ब्यूरो, लखनऊ

आम्रपाली मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि शाहबेरी, यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अब अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शाहबेरी में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जेल भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जमीन के मामलों में संलिप्त अधिकारियों की सूची तैयार की जाए, ताकि उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आम्रपाली समेत अन्य बिल्डरों के मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकभवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और शाहबेरी से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोर्ट से स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण कैसे हो गए, इसकी जांच कराएं। जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2014 के बाद जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाई जाए।

मुख्यमंत्री का सख्त रुख

- नोएडा, ग्रेनो, यमुना एक्सप्रेस-वे व शाहबेरी से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों संग बैठक
- विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
- 2007-2014 तक भूमि मामलों में संलिप्त अफसरों की सूची तैयार करें

लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक करते योगी आदित्यनाथ। जागरण

अफसरों की जिम्मेदारी तय हो

योगी ने कहा है कि 2007 से लेकर 2010 तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कौन-कौन अधिकारी तैनात थे और किन अधिकारियों ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाया, इसकी जांच की जाए। जिन अधिकारियों ने अराजकता और अव्यवस्था फैलाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

भवनों का हो सुरक्षा ऑडिट

सीएम ने शाहबेरी में सभी निर्माणों के सुरक्षा ऑडिट कराने और असुरक्षित निर्माण गिराने का निर्देश दिया है। जिन घरों में लोग रह रहे हैं, उनकी भी जांच होगी, ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं और बिल्डरों से इन्होंने कैसे भवन खरीदे?

मंत्री, सांसद और विधायक मौके पर जाकर लोगों से संवाद कायम करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से कहा है कि शाहबेरी मामले को लेकर वह स्थानीय सांसद, विधायक और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जाकर वहां के लोगों से संवाद कायम करें, जिससे समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शाहबेरी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है।

आवास विकास और एलडीए के बनाए भवनों की भी जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आवासों की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि, इनके आवासों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय को निर्देश दिया है कि आवास और एलडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा की जाए। (पेज-2 भी देखें)

आम्रपाली ने धौनी की फर्म से संदिग्ध समझौता किया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : आम्रपाली समूह ने रिति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरएसएमपीएल) के साथ संदिग्ध समझौता किया था। यह फर्म क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी के ब्रांड को प्रमोट करती है। आम्रपाली ने फ्लैट खरीदारों का पैसा गैरकानूनी रूप से दूसरी जगह मोड़ने के लिए यह कदम उठाया था। कोर्ट की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल और रवि भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि आम्रपाली सफारी डेवलपर्स प्रा. लि. ने आरएसएमपीएल को 2009-2015 के दौरान 42.22 करोड़ रुपये में से 6.52 करोड़ का भुगतान किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 नवंबर 2009 में किए गए एक समझौते सहित आरएसएमपीएल के साथ आम्रपाली समूह ने कई समझौते किए थे। इसके तहत धौनी आरएसएमपीएल के एक प्रतिनिधि के साथ तीन दिनों के लिए चेयरमैन के रूप में उपलब्ध रहते। 'यह शर्त पूरी करने के लिए कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है। यह दर्शाता है कि ये समझौते सिर्फ रिति स्पोर्ट्स प्रबंधन प्रा. लि. कंपनी को राशि का भुगतान करने के लिए किए गए थे।

पाकिस्तान में 30-40 हजार आतंकी

कुबूलनामा ▶ पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना, पूर्व की सरकारों ने सच छिपाया

कहा, उनके देश में ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में हमले करते हैं आतंकी

वाशिंगटन, प्रेट्र : सीमा पार के आतंकवाद को लेकर अब तक जो भारत कहता आ रहा था, उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी स्वीकार कर लिया है। तीन दिन के अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन इमरान ने कहा कि उनके देश में 40 आतंकी संगठन और 30-40 हजार आतंकवादी मौजूद हैं, जो कश्मीर और अफगानिस्तान में हमले करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद को लेकर दुनिया से सच छिपाए रखा।

भारत के साथ ही अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान पर अपने यहां अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मुहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक 'यूएस इंस्टीट्यूट फॉर पीस' (यूएसआइपी) के सामने इमरान ने कहा कि उनसे पहले, खासकर पिछले 15 साल के दौरान सरकारों में आतंकवादियों से लड़ने की मजबूत इच्छाशक्ति नहीं थी। उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उनकी सरकार ने आतंकी गुटों के मदरसों और संगठनों को अपने नियंत्रण में लिया है, वहां अपने प्रशासक नियुक्त किए हैं।

अमेरिकी सरकार, वहां के सांसदों और संगठनों के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर खुद को पाक-साफ बताने की कोशिश करने वाले इमरान से जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद पर सवाल पूछा गया तो उनकी असलियत सामने आ गई। उन्होंने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक यूएसआइपी की अध्यक्ष नैंसी लिंडबोर्ग ने इमरान खान से पूछा कि क्या उनकी सरकार द्वारा गिरफ्तार हाफिज सईद इस बार सलाखों के पीछे रहेगा या पहले की तरह फिर से आजाद हो जाएगा? इस पर इमरान ने कहा, 'पहले तो हम स्वतंत्र न्याय व्यवस्था चाहते हैं और आप मुझसे चाहती हैं कि न्याय प्रणाली में क्या होगा उसकी मैं भविष्यवाणी कर दूं।'

अमेरिकी संसद से जुड़े एक संगठन के कार्यक्रम में इमरान ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के बाद भी अमेरिका के साथ रिश्ते इसलिए खराब हो गए क्योंकि हमारे यहां की पूर्व की सरकारों ने अमेरिका से सच नहीं बताया। पाकिस्तान में हालात यह थे कि आतंकवादियों के खिलाफ हम खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे।

शांति स्थापना के लिए तालिबान से बात करेंगे इमरान : इमरान खान ने कहा कि वह अफगानिस्तान में 18 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत तालिबान के साथ मुलाकात करेंगे और उन्हें अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने की खातिर राजी करने का प्रयास करेंगे।

वाशिंगटन में 'यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस' के समक्ष अपनी बात रखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। एएफपी

14 दिन बढ़ी हाफिज सईद की हिरासत अवधि

लाहौर : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी सईद को गुजरांवाला स्थित आतंक रोधी न्यायालय ने 17 जुलाई को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। यह अवधि बुधवार को पूरी हो गई। इस पर हाफिज को फिर कोर्ट में पेश किया गया। (पेज-11)

लोकसभा में तत्काल तीन तलाक पर चर्चा आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा ने जारी किया व्हिप, आज ही पारित कराने में जुटी सरकार
- तीन तलाक समेत सात विधेयकों पर सरकार को रोकेगा विपक्ष

लोकसभा में गुरुवार को तत्काल तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने की संभावना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। विपक्ष ने तत्काल तीन तलाक समेत सात विधेयकों पर सरकार को रोकने की रणनीति बनाई है।

सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। विधेयक में तत्काल तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

विपक्ष ने अहम विधेयकों को विधायी कसौटी पर परखे बिना धुंआधार गति से पारित कराने को लेकर सरकार को आगाह किया है। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की घेरेबंदी के लिए हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मनमाने तरीके से विधेयकों को पारित कराने के सरकार के प्रयासों का जोरदार विरोध किया जाएगा। विपक्ष ने इसी रणनीति के तहत सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक समेत सात विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने के अपने इरादों की सूची बुधवार को सरकार को थमा दी। सरकार को विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े तीन तलाक विधेयक पारित कराने में भी जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है।

संसद के मौजूदा सत्र को दस दिनों के लिए बढ़ाने की सरकार की पूरी तैयारी को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने इसी अनुरूप अपनी साझा रणनीति बनाई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेताओं की अलग-अलग बैठक में अहम मुद्दों पर अपने दलों की एकजुटता और समन्वय पर जोर दिया गया। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने सुबह लोकसभा में विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें अहम मुद्दों पर विपक्षी दलों की चर्चा की मांग की अनदेखी किए जाने से लेकर लोकसभा में बहुमत की ताकत के सहारे संसदीय नियमों-परंपराओं को दरकिनार किए जाने के खिलाफ एकजुटता की जरूरत बताई गई। कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बोल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग फिलहाल जारी रखने पर भी सहमति बनी। इस बैठक में सपा और तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए।

हालांकि राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में तृणमूल कांग्रेस और सपा के नेता शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद की अगुआई में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में नेताओं का मानना था कि कई खामियों के साथ पारित हो रहे बिल के कानून बनने के बाद दूरगामी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए जल्दबाजी करने की बजाय विधायी कसौटी पर विधेयकों का अध्ययन कर इन्हें पारित कराया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर विपक्षी पार्टियों ने सूचना का अधिकार संशोधन बिल को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सदन में इसे पेश करने का मजमून तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं विपक्ष ने आरटीआइ समेत सात विधेयकों की सूची अनौपचारिक तौर पर सरकार को थमा दी है कि इन विधेयकों को राज्यसभा में जबरन पारित कराने के प्रयास हुए तो फिर हंगामा के साथ विरोध होगा।

आरटीआइ,तत्काल तीन तलाक बिल के अलावा वेतन संहिता बिल, कार्यगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता विधेयक, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, डीएनए संशोधन विधेयक और गैरकानूनी गतिविधि निषेध विधेयक को भी प्रवर समिति में भेजने की विपक्ष की रणनीति है। विपक्षी दलों ने सरकार के रणनीतिकारों से साफ कह दिया है कि वह चाहे तो खुद ही इन विधेयक को विधायी कसौटी पर परखने के लिए संसदीय समिति को भेज दे। सरकार ऐसा नहीं करेगी तो विपक्ष आसानी से विधेयकों को पारित नहीं होने देगा। ध्यान रहे कि तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार के सहयोगी दल जदयू ने भी आपत्ति जताई है।

मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा झटका, दो विधायक कमलनाथ सरकार के पक्ष में

नईदुनिया, भोपाल

- भाजपा नेता बयानबाजी करते रहे, कमलनाथ ने कर दिया खेल
- संशोधन विधेयक शून्य के मुकाबले 122 से करा दिया पारित

कर्नाटक में गठबंधन सरकार के गिर जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय मध्य प्रदेश की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को दिनभर चली सियासी बयानबाजी के बाद शाम को भाजपा को जबर्दस्त झटका दिया। उन्होंने विधानसभा में विधि संशोधन विधेयक को शून्य के मुकाबले 122 वोट से पारित करा दिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उनकी सरकार को न केवल कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलीयों का समर्थन हासिल हुआ बल्कि भाजपा के दो विधायकों का भी साथ मिला। इससे उन्होंने अपनी सरकार की मजबूती का सभी को एहसास करा दिया।

गौरतलब है कि कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई थी। इसी कड़ी में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिन में ट्वीट कर कहा कि लंगड़ी सरकारों का कोई भविष्य नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही बयान दिया कि अगर हमारे नंबर एक और नंबर दो नेता इशारा करें तो चौबीस घंटे में कमलनाथ सरकार गिर देंगे।

इसके जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विपक्ष को कभी भी फ्लोर टेस्ट करा लेने की चुनौती दी और कहा कि सरकार पूरे पांच साल चलेगी। इस दौरान बार-बार अल्पमत की सरकार के कटाक्ष से आहत कमलनाथ ने बड़ी चतुराई से भाजपा के न चाहते हुए भी सहयोगी दल बसपा के माध्यम से एक संशोधन विधेयक पर मतदान करवाकर एक बार फिर बहुमत साबित कर दिया। इस दौरान भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से भाजपा भौचक रह गई। इस दौरान सदन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे।

छह माह में चौथी बार साबित किया बहुमत पेज>>5

मत विभाजन

कुल सदस्य	229 (एक रिक्त)
बहुमत के लिए आवश्यक	115
सरकार के पक्ष में वोट पड़े	122
स्पीकर समेत कांग्रेस विधायक	114
निर्दलीय	04
बसपा	02
सपा	01
भाजपा	02

स्पीकर के वोट न डालने की स्थिति में विधेयक के पक्ष में 122 वोट।

आंध्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75 फीसद नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबंधित कानून 'आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिटेट इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2019' को विधानसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी।

बिल के प्रावधानों को बताते हुए श्रम मंत्री गुमानुर जयराम ने बताया कि नए कानून के मुताबिक प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रही सभी परियोजनाओं में 75 फीसद नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होंगी। यह काम उन्हें तीन साल में पूरा करना होगा। यदि कंपनियों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवा नहीं मिलते हैं तो वे सरकार के साथ मिलकर ऐसे लोगों को तीन साल में प्रशिक्षण देकर नौकरी के लायक बनाएंगी। श्रम मंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

उछाल

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पांच अंकों की छलांग, पाया 52वां स्थान, पीयूष गोयल ने ग्रामीण इनोवेशन को भी रैंकिंग का आधार बनाने का किया आग्रह, प्रति व्यक्ति जीडीपी के मुकाबले इनोवेशन में भी भारत लगातार नौवें वर्ष अव्वल

इनोवेशन में दक्षिण एशिया पर हमारी बादशाहत कायम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। साल 2019 में भारत इस सूची में पांच अंकों की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष की सूची में भारत 57वें स्थान पर था। मध्य और दक्षिण एशिया पर भारत ने इनोवेशन में अपनी बादशाहत कायम रखी है। पूरी सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन का स्थान है।

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग जारी की। इस रिपोर्ट का प्रकाशन यूएन वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आइएनएसईएडी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलकर करती हैं। इसके तहत 80 संकेतकों के आधार पर 129 देशों की रैंकिंग हर साल की जाती है।

रिपोर्ट जारी करने के बाद गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत में इनोवेशन की संस्कृति तेजी से फैल रही है। उन्होंने कहा, भारत इस सूची में भी शीर्ष 50 देशों में आने का प्रयास करता रहेगा। गोयल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लक्ष्य तय किया है। इस सूची में शीर्ष 25 देशों में जल्द से जल्द शामिल होने की हम हरसंभव कोशिश करेंगे।

प्रतीकात्मक

गोयल ने शोध व विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र से देश को इनवेशन हब में तब्दील करने के प्रयासों पर जोर देने को कहा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने यूएन संस्था से इंडेक्स में ग्रामीण इनोवेशन को भी शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार से समाज के निचले और कमजोर तबके के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उन्होंने अनुसंधान व विकास के जरिए देश की समस्याओं के सतत निदान ढूंढने पर बल दिया।

बात पते की

- दुनियाभर में आइटी सेवा के शीर्ष निर्यातक का रुतबा बरकरार
- बेंगलुरु, मुंबई व नई दिल्ली दुनिया के शीर्ष 100 साइंस व टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल
- इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 देशों में फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी व इजरायल भी
- भारत में संस्थाओं, मानव संसाधन और रिसर्च क्षेत्रों में हुआ बड़ा सुधार
- राजनीतिक और परिचालन स्थायित्व से भी सूचकांक पर मजबूत हुआ स्थान
- लॉजिस्टिक्स और महिलाओं को नौकरी देने के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कमजोर
- साइंस व टेक्नोलॉजी क्लस्टर में अमेरिका, चीन व जर्मनी ने मारी बाजी

शहरी नक्सलियों के प्रति कोई दया नहीं : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- यूएपीए संशोधन बिल लोकसभा से पारित

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) में संशोधनों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि शहरी नक्सलियों के लिए सरकार के दिल में कोई दया नहीं है और सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी। यूएपीए में संशोधनों को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को आतंकियों से चार कदम आगे रखने और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान जरूरी हैं। संशोधनों के विरोध में कांग्रेस के वॉकआउट के बीच लोकसभा ने इस पर मुहर लगा दी।

इन संशोधनों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा एजेंसी का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी आतंकवादी घटनाओं की जांच कर सकेगा। एनआइए को किसी भी राज्य में जांच के लिए वहां के डीजीपी से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही एनआइए डीजी को आतंकवाद से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा।

नई दिल्ली में बुधवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह इस अंदाज में दिखे। एएनआइ

विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए शाह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त है तो निश्चित रूप से एनआइए को उसका कंप्यूटर जब्त कर जांच करने का हक होना चाहिए। संशोधनों को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताने के तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा व अन्य नेताओं के आरोपों पर शाह ने कहा, सबसे पहले यूएपीए इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया था और संप्रग सरकार के दौरान भी इसमें संशोधन किए गए। जिन लोगों ने संप्रग सरकार के दौरान संशोधनों का समर्थन किया था, वही लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सतत प्रक्रिया है और सभी सरकारें कानून में संशोधन करती रही हैं। संप्रग काल में किया गया संशोधन भी सही था और अब हो रहा संशोधन भी सही है। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले की आशंका को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि देश में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है, लेकिन विचाराधारा की आड़ में गरीबों को गुमराह कर हिंसा के लिए प्रोत्साहित करने वाले नक्सलियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि इस बिल में प्रावधान हैं कि किसी व्यक्ति को कब आतंकी घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि प्रचार और उन्माद से पैदा होता है। यह किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज होता है। ऐसे व्यक्ति को आतंकी घोषित करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो संगठन को प्रतिबंधित करने से कुछ नहीं होगा। वह नया संगठन बना लेगा। इस वजह से व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान लाना जरूरी है।

दोहराया संकल्प ▶ मुख्यमंत्री ने कहा– मेरा मकसद लोगों को पक्की सड़कें और पक्की रजिस्ट्री दिलवाना

दो चरणों में नियमित होंगी अनधिकृत कॉलोनियां

2011 के बाद जीपीए के तहत खरीदी गईं जमीनों की स्टांप ड्यूटी होगी माफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि इस समय हमारा केवल एक ही मकसद है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किस तरह से पक्की सड़कें और पक्की रजिस्ट्री दिलवाई जाए। जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में हम पक्की सड़कें, नाली, सीवर और पानी का काम करवा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का निर्णय ले लिया है। पूरा मसौदा बनकर तैयार हो गया है। केंद्र सरकार भी तेजी दिखा रही है और हम लोग भी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार फरवरी 2015 में बनी थी। उसके चंद महीने बाद नवंबर 2015 में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके 12 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने हमारी टिप्पणी के लिए फाइनल प्रस्ताव हमारे पास भेजा है। हमें 15 दिन का वक्त दिया गया था। हमने सात दिन के अंदर अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। मोटे तौर पर हमने केंद्र सरकार की सारी बातें मान ली हैं। हमने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पहले चरण में 1797 कॉलोनियों को पक्का किया जा रहा है। इनको तीन श्रेणियों में बांटा जा रहा है। पहली श्रेणी सरकारी जमीन, दूसरी श्रेणी खेती वाली

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य। प्रेट्र

जमीन व तीसरी श्रेणी निजी जमीन पर बसीं कॉलानियों की है। पहली और दूसरी श्रेणी में मालिकाना हक उसको दिया जाएगा, जिनमें लोग अभी रह रहे हैं। उन्हें जमीन का कुछ पैसा और जुर्माना देना होगा। निजी जमीन पर बसी कॉलोनियों में रहने वालों को जमीन का पैसा नहीं देना होगा। केवल जुर्माना देना होगा।

पूर्व में हुई खरीद-फरोख्त की स्टांप ड्यूटी माफ होगी : केजरीवाल ने कहा कि एक अड़चन यह आ रही थी कि 11 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि अब जीपीए (जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी), एग्रीमेंट टू सेल इत्यादि मान्य नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू किया जाए तो 2011 के बाद जिन लोगों ने जीपीए के जरिये जमीनें खरीदीं, उन पर ये लागू नहीं हो पाएगा। इस शर्त को माफ किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2011 के बाद भी जो जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल हुई हैं, इनके लिए एक तारीख तय कर ली जाएगी। उसी के आधार पर मालिकाना हक चिह्नित किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में जितने लोगों ने घर ले रखे हैं, प्लॉट ले रखे हैं, सब बार-बार जीपीए पर बिके हैं। एक ने लिया, फिर दूसरे ने लिया, फिर तीसरे ने लिया। अब दिल्ली सरकार बीच में जितनी भी खरीद-फरोख्त हुई, उन सबकी स्टांप ड्यूटी माफ कर देगी। अब जिसके पास है, उनसे स्टांप ड्यूटी लेकर मालिकाना हक दे दिया जाएगा।

अनधिकृत कॉलोनियां दो चरणों में नियमित होंगी। पहले चरण में 1797 कॉलोनियां हैं। केंद्र सरकार ने लिखा है कि 1 जनवरी 2015 तक 1797 के अलावा भी अगर कोई कॉलोनी बच गई है तो दिल्ली सरकार उसकी लिस्ट बना ले। केजरीवाल ने कहा कि हमारा सुझाव है कि 1 जुलाई, 2019 तक 1797 कॉलोनियों के अलावा जितनी कॉलोनियां बच जाती हैं, उनकी भी लिस्ट बना ली जाए और उनको दूसरे चरण में नियमित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि एक महीने के अंदर केंद्र सरकार इसका आदेश जारी कर देगी। जिस दिन केंद्र सरकार आदेश जारी करेगी, उसके बाद तीन महीने के अंदर डीडीए उसके नियम पास कर देगा।

केजरीवाल ने केंद्र को भेजे 12 सुझाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर इन कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 सुझाव केंद्र सरकार के पास भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को सुझाव भेजे हैं। केंद्र सरकार जो सुझाव मानना चाहे वे माने, जो न मानना चाहे न माने, मगर हम चाहते हैं कि यह स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि दिल्ली के लोगों को उनका हक मिल सके।

- केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 तक रखी गई 50 फीसद बिल्डअप एरिया वाली शर्त को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया जाए।
- 30 जून 2019 तक जितने लोगों ने अपनी जीपीए (जनरल पॉवर आफ अटार्नी) करा ली है, उन सभी जीपीए को वैध माना जाए और उसी के आधार पर मालिकाना हक दिया जाए।
- 1 जुलाई 2019 तक जितनी अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली में बन चुकी हैं, उनकी एक सूची बनाकर दूसरे चरण में उन सभी को पक्का घोषित किया जाए।
- भविष्य में दिल्ली में कोई नई अनधिकृत कॉलोनी बनती है तो संबंधित एसडीएम, एसएचओ एवं एमसीडी अधिकारी को बर्खास्त किया जाए।
- तीन कॉलोनियों सैनिक फार्म, महेंद्रू एंक्लेव तथा अनंत राम डेरी केंद्र सरकार ने पक्का करने के दायरे से बाहर रखी हैं, यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसलिए इन तीनों कॉलोनियों को भी अन्य कॉलोनियों के साथ नियमित किया जाए।
- इन कॉलोनियों को नियमित करते समय जो जमीन की और जुर्माना की कीमत अदा करनी होगी, उसके लिए बैंक से ऋण की सुविधा दी जाए ताकि गरीब लोग आसानी से इस राशि को जमा करा सकें।
- डीडीए के नक्शे बनाने का इंतजार करने के बजाय, विभिन्न आरडब्ल्यू और दिल्ली सरकार के जीएसडीएल विभाग द्वारा सेटेलाइट से बनाए गए मौजूदा नक्शों के आधार पर तुरंत रजिस्ट्रियां खोल दी जाएं।
- यमुना बांध के अंदर जो कॉलोनियां आ रही हैं, उन्हें नियमित न किया जाए। यमुना बांध के बाहर वाली कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाए।
- इन अनधिकृत कॉलोनियों में जो सरकारी जमीनें हैं, वे दिल्ली सरकार को द्वितीय श्रेणी के मूल्य पर स्कूल, अस्पताल एवं अन्य सुविधा के लिए हस्तांतरित कर दी जाएं।
- अनधिकृत कॉलोनियों को नजदीकी कॉलोनियों में जो सबसे निम्न स्तर की श्रेणी की कॉलोनी है, उससे भी नीचे माना जाए।
- जिन कॉलोनियों में वन विभाग, एएसआइ की जमीन है, उन्हें छोड़कर बाकी कॉलोनी को नियमित कर दिया जाए।
- जिन कॉलोनियों में लोगों ने दुकानें भी खोल रखी हैं, उन कॉलोनियों की जमीन को मिक्स यूज लैंड घोषित किया जाए।

अनधिकृत कॉलोनी में महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री नि :शुल्क हो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका श्रेय लेने को दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें झूठा श्रेय लेने के बजाय इन कॉलोनियों में महिलाओं की संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा ने केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सम्मानित करने का भी फैसला किया है। वहीं, पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने भाजपा सांसदों के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना देने का एलान किया है।

तिवारी ने कहा कि पुरी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार को लगातार पत्र लिखते रहे हैं। उन पत्रों के अनुरूप लोगों के हित में कदम उठाने के बजाय केजरीवाल दिल्ली में भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं कि मोदी सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ है। वह दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1757 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार के पास न तो कोई प्रस्ताव भेजा और न ही अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने के लिए काम किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने के लिए पहले भी समय मांग चुकी है। अब फिर से दिल्ली सरकार ने इसके लिए वर्ष 2021 तक का समय मांगा है। दिल्ली सरकार के नकारात्मक रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में मार्च 2019 में एक कमेटी बनाई,

प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जागरण

जिसने 11 जुलाई को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने और उसके निवासियों को मालिकाना हक देने का काम स्वयं करेगी। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी पक्षों को दस दिनों में अपने सुझाव देने को कहा है और एक माह में अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल का कहना है कि केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में बाधा डालती रही है। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों में दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। अब मुख्यमंत्री इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस रवैये के खिलाफ गुरुवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा व हंसराज हंस भी शामिल होंगे।

न्यूज गैलरी

सीबीएसई ने सीटेट की उत्तर पुस्तिका जारी की

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीईटीईटी) की उत्तर पुस्तिका जारी कर दी हैं। बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार इसे 26 जुलाई दोपहर 11 बजकर 59 मिनट तक देख सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र की आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं तो सीटेट की वेबसाइट में मौजूद एक लिंक पर क्लिक करके चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न एक हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। शुल्क डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिये जमा किया जा सकता है। सीटेट के निदेशक और सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अगर उम्मीदवार की चुनौती को सही पाया जाता है तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी व उत्तर पुस्तिका को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों को फीस वापस की जाएगी। रिफंड संबंधित खाते में ही ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। (जासं)

सिख विरोधी दंगे के दोषियों को जमानत मिलने पर सियासत शुरू

नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगे के दोषियों को जमानत मिलने के बाद दिल्ली की सिख सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) ने इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) को जिम्मेदार ठहराया है। शिअद दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना का कहना है कि कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की गई। इस वजह से दोषियों को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 1984 में त्रिलोकपुरी में सिखों की हत्या के नौ आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके खिलाफ भी कमेटी ने अपील दायर नहीं की। अब त्रिलोकपुरी में कत्लेआम के अन्य दोषियों को जमानत मिल गई है। चुनाव से ठीक पहले शिअद बादल को 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की याद आने लगती है। वहीं, कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बरी किए गए आरोपितों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। आरोपितों व जमानत पर बाहर आने वालों को फिर से जेल भेजने के लिए कमेटी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। (जासं)

पहले प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर मिलेगा मुफ्त वाई–फाई

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी वर्ष में हर हाल में मुफ्त वाई-फाई का वादा पूरा करना चाहती है। सरकार की मंशा इस सुविधा को विधानसभा चुनाव से पहले जनता को उपलब्ध करा देने की है। जल्द वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने अब नया प्रस्ताव तैयार कराया है।

नए प्रस्ताव के तहत अब 4000 सार्वजनिक स्थानों और 7000 पार्कों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सभी बस स्टॉप, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख स्थान शामिल होंगे। इस सुविधा के तहत लोग एक बार मुफ्त वाई-फाई की सुविधा को शुरू कर लेंगे तो अगली बार जब वाई फाई की रेंज में पहुंचेंगे तो यह सुविधा स्वयं काम करना शुरू कर देगी। लोक निर्माण विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग में भेज दिया है। वित्त विभाग से जल्द ही अनुमति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

वाई-फाई की सुविधा के लिए यह नया प्रस्ताव है। अब नए प्रस्ताव में टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उनकी फाइबर की लाइनें शहर के कितने भागों में बिछी हुई हैं।

बता दें कि लोगों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा देने का आप का चुनावी वादा है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद अब फिर से हॉट स्पॉट के जरिए इंटरनेट सुविधा देने पर सहमति बन गई है। प्रत्येक यूजर को महीने में 45 जीबी डाटा मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए दिल्ली भर में दो हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इस प्रस्ताव के तहत तीन वर्षों में करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

अंग्रेजी में भी डेल्ही नहीं दिल्ली लिखा जाए : विजय गोयल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने राजधानी दिल्ली की स्पेलिंग में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में यह मामला उठाया है। उनका कहना है कि दिल्ली को अंग्रेजी में डेल्ही लिखा जाता है। इसमें बदलाव किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजधानी का नाम दिल्ली कैसे पड़ा इस बारे में तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का नाम मौर्य राजवंश के शासक राजा दिल्लू के नाम पर है। वहीं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली का नाम देहलीज शब्द से मिला। उन्होंने कहा कि राजधानी के नाम में शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक हो और डेल्ही शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग वैसे भी दिल्ली के नाम को लेकर भ्रमित हैं।

गोयल ने कहा कि कुछ लोग इसे डेल्ही कहते हैं तो कुछ दिल्ली कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर रखे जाने की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है। इस समय वह इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ दिल्ली की स्पेलिंग को सही कराना चाहते हैं।

आम्रपाली ने 521 करोड़ खर्च कर हासिल की सवा पांच लाख वर्ग मीटर जमीन

कुंदन तिवारी, नोएडा

- **2002 में बिहार से दिल्ली आए अनिल शर्मा ने मायावती सरकार के दौरान एनसीआर में पसारे पैर**
- **45 हजार निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये डकारे, प्राधिकरण का 22 सौ करोड़ रुपये से अधिक का है बकाया**

आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट का अधूरा पड़ा निर्माण। जागरण

निवेशकों की पूंजी से अरबपति बने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा ने महज 521 करोड़ रुपये खर्च कर नोएडा में बेशकीमती 536000 वर्ग मीटर जमीन हासिल की थी। 2002 में बिहार से दिल्ली आए अनिल ने पहले दिल्ली में नौकरी की और फिर रियल एस्टेट में पैर पसारने शुरू किए। मेरा घर मेरा अधिकार स्लोगन के साथ आम्रपाली एक्जाटिका नाम से पहला प्रोजेक्ट नोएडा में लांच किया।

तत्कालीन बसपा सरकार में नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात बिहार कैडर के कई आइएएस अधिकारियों से नजदीकी का फायदा उठाकर उसने प्राधिकरण में पैठ बनाई और फिर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीद ली। आज भी नोएडा विकास प्राधिकरण का करीब 2200 करोड़ रुपये आम्रपाली ग्रुप पर बकाया है। अब आनंद प्रकरण के बाद प्राधिकरण में हुए भूखंड आवंटन घोटाले की परतें खुल रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली ग्रुप की फाइलें भी बाहर आ गई हैं।

2007 में हुआ आम्रपाली का प्राधिकरण में प्रवेश : आम्रपाली ग्रुप ने नोएडा विकास प्राधिकरण में 2007 में प्रवेश किया। तीन साल बाद 2010 में आम्रपाली समूह को नोएडा में नौ परियोजनाओं के लिए भूखंड आवंटन हुआ। भूखंड आवंटन के नाम पर प्राधिकरण को महज 521 करोड़ रुपये की रकम हासिल हुई, लेकिन सरकार की मेहरबानी से उसे 5,36000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी गई। सेक्टर-119 में पटेल प्लेटिनम प्रोजेक्ट लेकर आया। करीब 55 हजार वर्गमीटर जमीन पर प्रोजेक्ट बनाया गया। इस परियोजना पर प्राधिकरण का 200 करोड़ रुपये बकाया है। आज दस वर्ष बाद जहां 45 हजार निवेशक सड़क पर अपना आशियाना हासिल करने के लिए भटक रहे हैं, वहीं नोएडा प्राधिकरण भी अपना करीब 22 सौ करोड़ रुपये से अधिक का बकाया वसूलने की जुगत लगाने में जुटा है।

बसपा सरकार के समय ही हुआ सभी भूखंडों का आवंटन : आम्रपाली की सभी परियोजनाओं के लिए जमीन का आवंटन बसपा शासन काल में किया गया। बसपा शासन काल में ही भू-आवंटन की नीतियों में बदलाव किया गया। बसपा शासनकाल से पहले भूखंड आवंटन के दौरान आवंटी को जमीन की कुल लागत का 30 प्रतिशत देना होता था। इस नियम को बदल दिया गया। तत्कालीन बसपा सरकार ने भू-आवंटन की रकम को 30 से घटाकर 10 फीसद कर बिल्डरों को लाभ पहुंचाया। इसका फायदा आम्रपाली समूह ने उठाया। महज तीन साल के अंदर नौ परियोजनाओं को लांच कर बुकिंग के नाम पर कई हजार करोड़ रुपये डकार लिए। कुछ किस्तें जमा करने के बाद प्राधिकरण को भू-आवंटन की बकाया राशि भी जमा करना बंद कर दिया।

जाम से राजधानी में फूला वाहनों का दम

राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। एक से तीन किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहन चालकों को डेढ़ से दो घंटे का समय लगा। विकास मार्ग, आइटीओ के आसपास और यमुना पुल पर भीषण जाम के चलते वाहन चालकों के पसीने छूट गए। जागरण

बिहार के अफसरों की काली कमाई खपाई जा रही थी

राज्य ब्यूरो, पटना : करीब 35-36 साल पहले बिहार के हाजीपुर नगरपालिका में सहायक अभियंता के पद की नौकरी करने वाले अनिल शर्मा अब आम्रपाली समूह के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में अपनी ठगी के लिए चर्चित हो रहे हैं। दिल्ली के आसपास घर का सपना संजोए लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल रहा, नहीं तो अनिल शर्मा की कंपनी ने उन लगभग 45 हजार लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा था। आम्रपाली हाउसिंग के अनिल शर्मा और कंपनी के दो अन्य निदेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद है। पटना के पंडारक के साधारण परिवार के रहने वाले अनिल शर्मा ने 1981-82 में हाजीपुर नगर पालिका में सहायक अभियंता के तौर पर करियर की शुरुआत की। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने लिए एक कार भी खरीद सकें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हाजीपुर जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष जगन्नाथ राय ने अपनी एंबेसडर गाड़ी उन्हें दे दी। नगरपालिका की नौकरी अनिल शर्मा को रास नहीं आ रही थी। नौकरी से इस्तीफा देकर वह रियल एस्टेट के क्षेत्र में दांव आजमाने नोएडा आ गए। बिहार के आइएएस, आइपीएस और अन्य विभागों के अफसरों की काली कमाई को खपाने का यह ठिकाना बन गया।

2014 के लोस चुनाव में जनता दल यू ने उन्हें जहानाबाद से प्रत्याशी बना दिया। हालांकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अरुण कुमार के मुकाबले चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना था। नेतृत्व से नाराजगी के कारण जदयू के एक दर्जन से अधिक बागी विधायकों के समर्थन से वह राज्यसभा के प्रत्याशी बन गए, लेकिन यहां भी हार ही मिली।

... तो विदेश भाग जाता आम्रपाली ग्रुप का चेयरमैन अनिल शर्मा

आशुतोष अग्निहोत्री, नोएडा

शराब कारोबारी विजय माल्या और डायमंड कारोबारी नीरव मोदी की तर्ज पर 42 हजार निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये हजम करने वाले आम्रपाली समूह के चेयरमैन अनिल शर्मा ने भी विदेश भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह एक ओर निवेशकों को उनके फ्लैट समय से देने का वायदा कर रहा था। वहीं गुपचुप तरीके से मॉरीशस की बड़ी कंपनी सहित करीब 250 कंपनियों में रुपये भी ट्रांसफर करा चुका था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता के बाद अक्टूबर 2018 में उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। चार माह तक नजरबंद कर उससे पूछताछ हुई और इसी साल मार्च में उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

निवेशकों के हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कराया ऑडिट : वर्षों से फ्लैट के लिए मांग कर रहे आम्रपाली समूह में निवेश करने वाले सैकड़ों लोगों ने वर्ष 2017 में आम्रपाली समूह के सेक्टर-62 स्थित कारपोरेट ऑफिस पर 45 दिनों तक लगातार धरना दिया। कंपनी की ओर से उचित जवाब न मिलने पर निवेशकों ने समूह के तीनों निदेशकों अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना और फिर जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यू ललित की पीठ को मामला सौंप दिया। पीठ ने दो फोरेंसिक ऑडिटर पवन अग्रवाल और रवि भाटिया से आम्रपाली ग्रुप का ऑडिट कराया।

चार माह तक नजरबंद रहे तीनों निदेशक : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अक्टूबर 2018 में नोएडा की सेक्टर-58 कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय कुमार को हिरासत में लेकर आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया। आर्थिक अपराध शाखा ने इसी थाना क्षेत्र के एक तीन सितारा होटल में स्थित इन निदेशकों के सुइट में ही इन्हें नजरबंद कर दिया। 28 जनवरी 2019 तक दोनों ऑडिटरों ने तीनों निदेशकों से नजरबंदी के दौरान ही अलग-अलग पूछताछ की। पूछताछ में ही यह निकलकर सामने आया कि आरोपितों ने 250 से अधिक कंपनियों में रुपये ट्रांसफर किए। ग्रुप की कई नई कंपनियों के बारे में भी जानकारी सामने आई। एक कंपनी तो ऐसी थी जिसकी महीने की आय मात्र 50 हजार रुपये थी, जबकि टैक्स दो करोड़ रुपये भरा जा रहा था। जांच में प्रमोटर, सीएफओ और कंपनी के ऑडिटरों के रिश्तेदारों के नाम से पंजीकृत कई कंपनियों के नाम भी उजागर हुए थे।

निदेशकों को ही पता थे 36 कंप्यूटरों के पासवर्ड : जांच के दौरान ऑडिटरों को आम्रपाली समूह ने 117 कंप्यूटर उपलब्ध कराए, लेकिन इनमें से 36 के पासवर्ड नहीं बताए। ऑडिटरों ने कई दिन तक यह जानने का प्रयास किया कि कौन सा कंप्यूटर किस कंपनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बावजूद इसके उन्हें यह नहीं बताया गया। बाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में निदेशकों को इसके लिए भी फटकार लगी। ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहीं से तीनों निदेशकों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

जिले की पांच कोतवाली में दर्ज हैं 23 मुकदमे : आम्रपाली समूह के निदेशकों के खिलाफ नोएडा व ग्रेटर नोएडा की पांच कोतवालियों बिसरख, फेस तीन, सेक्टर 49, सेक्टर 39 और सेक्टर 58 में धोखाधड़ी के 23 केस दर्ज हैं। सबसे अधिक मुकदमे बिसरख कोतवाली में हैं। तीन मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। अन्य जांच चल रही है।

पहल

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (सतर्कता विभाग) ने जारी किया आदेश, स्क्रीनिंग में भ्रष्टाचार और लापरवाही साबित होने पर किए जाएंगे जबरन सेवानिवृत्त

वर्दी में मिले दाग तो घर की राह दिखाएगा विभाग

लोकेश चौहान, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की छवि को साफ-सुथरा बनाने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत अब विभाग ने भ्रष्ट और लापरवाह पुलिसकर्मियों को घर का रास्ता दिखाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट में यदि किसी पुलिसकर्मी पर भ्रष्टाचार या लापरवाही का आरोप साबित होता है, तो विभाग उसे जबरन सेवानिवृत्त करेगा।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (सतर्कता विभाग) सुमन गोयल ने ऐसे पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। साथ ही सभी जिलों के डीसीपी को पत्र भेजकर पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए कहा गया है। इसमें दागी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर नियम 56 (जे) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त किया जाएगा।

इस जांच में डीसीपी कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करेंगे। वहीं इंस्पेक्टर की स्क्रीनिंग संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा की जाएगी। आने वाले दिनों में एसीपी स्तर के अधिकारियों को भी इस जांच के दायरे में लिया जा सकता है।

दस से 15 फीसद पुलिसकर्मियों पर गिर सकती है गाज : दिल्ली पुलिस की छवि सुधारने की कवायद पर यदि गंभीरता से कार्य किया गया तो करीब दस से 15 फीसद पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। वहीं ईमानदार पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भ्रष्ट और लापरवाह पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त करने के फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है।

स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे यह अधिकारी : दागी पुलिसकर्मियों की जांच करने के लिए जिलास्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों की जांच कमेटी में डीसीपी चेयरमैन होंगे। इसके अलावा एसीपी हेडक्वार्टर, एसीपी विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे। इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों के मामलों की स्क्रीनिंग के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में बनी कमेटी में जिले के डीसीपी और विजिलेंस के डीसीपी शामिल किए गए हैं।

इन बिंदुओं पर होगी स्क्रीनिंग

- भ्रष्टाचार, रिश्वत
- दुराचार, दुष्कर्म व दुष्कर्म का प्रयास
- अनुपस्थिति की आदत
- शराब या ड्रग्स की लत
- अनुशासनहीनता
- कर्तव्यों की अनदेखी
- जानबूझकर नागरिक को नुकसान पहुंचाना

क्या है नियम 56 (जे)

नियम 56 (जे) सार्वजनिक हित को देखते हुए प्रयोग में लाया जाता है। इसके माध्यम से नौकरशाहों के कार्यकाल को खत्म किया जाता है। यह ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामले में प्रयोग में आता है। इसमें 25 साल का कार्यकाल और 50 की उम्र को पार करने वालों का कार्यकाल खत्म कर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। नियम 56 (जे) के तहत जनहित में किसी भी सरकारी अधिकारी को तीन माह का नोटिस देकर सेवामुक्त किया जा सकता है।

23 लाख 80 हजार राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड में सस्ती दरों पर मिलेगी दो किलो दाल। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसके साथ 12 अन्य बिंदुओं पर भी फैसले लिए गए।

देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में आई कमी

जवाब ▶ संसद में सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने दिखाया आईना

कहा– 2014 में 820 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं, जबकि 2018 में 708 मामले सामने आए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सांप्रदायिक तनाव और उन्मादी हिंसा पर घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष को सरकार ने बुधवार को आईना दिखाया है। साथ ही बताया है कि इनमें पहले के मुकाबले कमी आई है। 2014 में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी 820 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं। 2018 में 708 घटनाएं रिपोर्ट हुई है। इसके साथ ही वह यह भी बताने से सरकार नहीं चूकी कि यह राज्य का विषय है और राज्यों को लगातार जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. कृष्णा रेड्डी बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 से सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने का काम शुरू किया। 2017 तक रिकॉर्ड करने के बाद इसे बंद कर दिया। बावजूद इसके उनके पास आइबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के रिकॉर्ड के तहत जो जानकारी है, उनमें देश में सांप्रदायिक तनाव में लगातार कमी आ रही है। राज्यों को ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से उन्मादी हिंसा को लेकर किए गए सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ऐसी घटनाओं की कोई एक प्रकृति नहीं है। यह सभी राज्यों में अलग-अलग तरीके से देखने को मिलती है। इसमें कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल हैं। मेरे पास जो डाटा है, उसमें साफ है कि त्रिपुरा में जब माकपा की सरकार थी, तब भी उन्मादी हिंसा की घटनाएं हुई थीं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, वहां भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में इसका सिर्फ भाजपा या एनडीए से संबंध ठीक नहीं है। वैसे भी ऐसी घटनाएं ठीक नहीं हैं। केंद्र लगातार इस दिशा में एयवाइजरी जारी करता रहता है।

उन्मादी भीड़ की हिंसा के पीछे आरएसएस : तेजप्रताप

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बजरंग दल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को इसे देखना चाहिए। तेजप्रताप ने बुधवार को महुआ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं।

असहिष्णुता पर बुद्धिजीवियों ने पीएम को लिखा खुला पत्र

जागरण संवाददाता, कोलकाता

अभिनेता-अभिनेत्री, फिल्मकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, समेत विभिन्न क्षेत्रों के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम असहिष्णुता को लेकर खुला पत्र लिखा है, जिसमें दलित व अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती हिंसा पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र में मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया-'अफसोस की बात है कि जय श्रीराम का आज उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक भड़काऊ नारा बन गया है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को राम के नाम पर डराया जा रहा है। राम की अवमानना करने पर रोक लगाने की जरूरत है।' पत्र में दावा किया गया कि 29 अक्टूबर, 2018 से जनवरी, 2019 के दौरान देश में 254 से ज्यादा धार्मिक पहचान पर आधारित नफरत वाले अपराध दर्ज किए गए हैं। पत्र में पूछा गया है कि इन मामलों के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?'

हालात को देखते हुए पत्र लिखा गया : इस मुद्दे पर फिल्मकार व अभिनेत्री अपर्णा सेन ने कहा कि देश में दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को जय श्रीराम के नाम पर जारी हिंसा व सामूहिक पिटाई का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर समय रहते इस तरह की अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आगे स्थिति और भयावह हो सकती है। कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने वालों को अगर देशद्रोही करार दिया जाता है तो यह संविधान के विपरीत है।

पत्र को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने सवाल उठाया है। सवाल किया कि जब 'जय श्रीराम' कहने पर बंगाल में सामूहिक पिटाई कर हत्या की गई, तब वे लोग कहां थे? पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा नेता सायंतन बसु ने भी इस पत्र को लेकर बुद्धिजीवियों पर निशाना साधा और कहा कि इनमें से अधिकांश बुद्धिजीवी ममता बनर्जी के गुलाम हैं। उन्होंने भी सवाल किया कि जब 'जय श्रीराम' कहने पर बंगाल में लोगों को मारा जाता है, तब ये लोग पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? 'जय श्रीराम' कहने पर जो हत्याएं हुई हैं, इसका पत्र में उल्लेख क्यों नहीं है?

पत्र में इनके हैं नाम

पत्र में मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, इतिहासकार रामचंद्र गुह्य, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, विनायक सेन, सौमित्र चटर्जी, गौतम घोष, कौशिक सेन, कोंकणा सेनशर्मा समेत कुल 49 हस्तियों के नाम हैं।

असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद बुधवार को कोलकाता में फिल्मकार अपर्णा सेन ने मामले पर प्रेसवार्ता की। प्रेट्र

संसद सत्र

फ्लेक्सी किरायों से रेलवे को फायदा, नहीं हटेंगे : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **जून, 2019 तक इस योजना से रेलवे को 2426 करोड़ की अतिरिक्त कमाई**

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों के फ्लेक्सी किरायों को समाप्त करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जून, 2019 तक इस स्कीम की बदौलत रेलवे को 2426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो चुकी थी।

लोकसभा में बढ़ते रेल किरायों पर पूछे गए सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि रेलवे द्वारा संचालित 13,452 ट्रेनों में से केवल 141 राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों के लिए ही फ्लेक्सी किरायों का प्रावधान है। इनमें से भी महज 32 ट्रेनों में ही इसे वास्तव में लागू किया गया है। इन ट्रेनों के लिए फ्लेक्सी किराया स्कीम को सितंबर, 2016 में शुरू किया गया था। तब से इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए फिलहाल इस स्कीम को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल किरायों की तुलना हवाई किरायों से करने पर गोयल ने कहा कि रेलवे और एयरलाइन यातायात के दो अलग-अलग माध्यम हैं। आकार, संपर्क क्षमता तथा सुविधा के लिहाज से इनके बीच तुलना नहीं की जा सकती। हवाई किरायों की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। जबकि रेलवे ने पूरे वर्ष के लिए न्यूनतम किराये निर्धारित कर रखे हैं। रेलवे के किराये श्रेणी तथा सुस्त या व्यस्त मौसम के अनुसार हवाई किरायों से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में ये ग्राहकों पर निर्भर है कि वे अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से रेलवे को चुनते हैं या एयरलाइन को। गोयल के मुताबिक वर्ष 2015-16 में फ्लेक्सी किराये वाले मार्गों समेत सभी प्रकार के मार्गों में आरक्षित श्रेणियों में क्षमता से अधिक सीटें भरी रहती थीं, लेकिन फ्लेक्सी किराया लागू होने के बाद 2017-18 में इसमें और बढ़ोतरी हो गई।

सभी ब्राड गेज रेल मार्गों का होगा विद्युतीकरण : गोयल के मुताबिक रेलवे सभी ब्राड गेज रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर रही है। रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि रेलवे पूरे देश की बिजली का 1.27 फीसद (20.44 अरब यूनिट) का उपयोग करती है जबकि तीन फीसद (31. अरब लीटर) हाई स्पीड डीजल का प्रयोग करती है।

बाल यौन उत्पीड़न में मृत्युदंड के प्रावधान पर राज्यसभा की मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **बच्चियों के अलावा बालकों (सभी बच्चों) से यौन उत्पीड़न पर भी किया गया है दंड का प्रावधान**

दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर राज्यसभा ने बच्चों के साथ गंभीर यौन दुर्व्यवहार के दोषियों को मौत की सजा के प्रावधान पर मुहर लगा दी। राज्यसभा ने बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित कर दिया है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान के अलावा बच्चों के यौन उत्पीड़न के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं। अब इसे लोकसभा से पारित कराया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में पोक्सो विधेयक पेश किया था और सभी से समर्थन मांगा था। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाल्यकाल में बस में उनके साथ हुई छेड़छाड़ को याद किया और कहा कि कई मामलों में शिकायतें ही नहीं होती हैं। सरकार को सख्ती से निपटना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि वह विधेयक का स्वागत करते हैं लेकिन कड़े प्रावधान भी ऐसी घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास भी 2016 के बाद का बच्चों के यौन उत्पीड़न के अपराधों का आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा ऐसे अपराधों में सजा की दर भी बहुत कम है।

अन्नाद्रमुक की नेता विजिला सत्यनाथन ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए इन घिनौने अपराध के दोषियों का कैमिकल कैस्ट्रेशन करने की भी मांग की। सपा सांसद जया बच्चन ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून में संशोधन से समस्या का हल नहीं निकलेगा इसके लिए तय समय में जांच और सजा होना भी जरूरी है। साथ ही उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद कानून सख्त किया गया लेकिन ऐसी घटनाएं फिर भी नहीं रुकीं। अन्य दलों के नेताओं ने भी विधेयक का समर्थन किया।

स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती और तेजी से निपटने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि विभिन्न अदालतों में ऐसे 1.66 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने बताया कि दो महीनों के अंदर जांच और एक साल के अंदर सजा का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो कानून में संशोधन कर बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान किया है। दोषियों को 20 साल से लेकर उम्रकैद और मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है ताकि सिर्फ बच्चियों को ही नहीं बल्कि बालकों को भी यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसके अलावा कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फोटो, वीडियो, कार्टून या फिर कंप्यूटर जेनेरेटड इमेज को इसके तहत दंडनीय अपराध की जद मे लाया गया है। ऐसी सामग्री रखने तक को 5000 से लेकर 10000 तक के जुर्माने के दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसी सामग्री का व्यवसायिक इस्तेमाल करता है तो उसे जेल की सख्त सजा भुगतनी होगी। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन आदि देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है जिसमें पांच साल तक की कैद का प्रावधान है।

नौकरशाही में भारी फेरबदल भल्ला होंगे गृह सचिव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

असम- मेघालय कैडर के आइएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला नये गृह सचिव होंगे। भल्ला को फिलहाल गृह मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। सितंबर में मौजूदा गृह सचिव राजीव गौबा की सेवानिवृति के बाद भल्ला उनकी जगह लेंगे। भल्ला फिलहाल ऊर्जा सचिव हैं। नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने भल्ला समेत एक दर्जन आइएएस अफसरों के तबादले और नियुक्तियों को हरी झंडी दी। साथ ही एक दर्जन आइएएस अधिकारियों को उन्हीं के विभागों में प्रोन्नति भी दी गई है।

अजय भल्ला 1984 बैच के आइएएस अधिकारी हैं और 2017 में ऊर्जा सचिव बनने के पहले महानिदेशक विदेश व्यापार थे। ऊर्जा मंत्रालय में इनके स्थान पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है। जबकि विनिवेश देखने वाले दीपम विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती को वित्त मंत्रालय में गर्ग की जगह भेजा गया है। 1986 बैच के आइएएस अधिकारी अनिल कुमार खच्ची को दीपम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

इधर-उधर

- **नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी ने तबादलों को दी हरी झंडी**
- **एक दर्जन आइएएस अधिकारियों का हुआ तबादला**

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरु प्रसाद महापात्रा को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) का सचिव नियुक्त किया गया है। वह रमेश अभिषेक की जगह लेंगे जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इसी महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहीं दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन की जगह इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव अंशु प्रकाश को प्रोन्नति देकर सचिव बनाया गया है। अंशु प्रकाश दिल्ली के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। डीपीआइआइटी में अतिरिक्त सचिव अतुल चतुर्वेदी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव बनाया गया है। गुजरात कैडर के पीडी वघेला को फार्मास्यूटिकल सचिव नियुक्त किया गया है।

रूस के पास नहीं हैं नेताजी से जुड़े दस्तावेज : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सूचना हासिल करने के लिए 2014 के बाद से भारत ने रूस से कई बार आग्रह किया, लेकिन मास्को की तरफ से हर बार यही कहा गया कि बोस से संबंधित दस्तावेज उसे रूसी अभिलेखागार में नहीं हैं।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत ने सूचना मांगी थी कि क्या अगस्त, 1945 से पहले या बाद में किसी समय बोस रूस में मौजूद थे। अगस्त, 1945 या इसके बाद वह रूस से बाहर चले गए थे, जैसा कि कुछ शोधकर्ताओंकी ओर से दावा किया गया था। जवाब में रूस ने यही कहा कि उसे नेताजी के बारे में कोई दस्तावेज उसके अभिलेखागार में नहीं मिले हैं।

शास्त्री, मुखर्जी, उपाध्याय की मौत की जांच को आयोग नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की 'संदिग्ध मौत' की जांच के लिए कोई आयोग गठित करने पर विचार नहीं कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। रेड्डी ने बताया कि हाल ही में इस संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की मांग की। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में बुधवार को सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उधर, तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। फिलहाल इस मामले में संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।' राय ने कहा कि बंग्ला नाम पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरह है। राज्यसभा में वह उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला किए जाने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने क्यों अस्वीकृत कर दिया। मंत्री ने कहा, 'गांव, शहर या रेलवे स्टेशन आदि का नाम बदलने के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश तय हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में बदलाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति जरूरी है।' उन्होंने बताया कि जब भी गांव, शहर, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के नाम में बदलाव का प्रस्ताव आता है, मंत्रालय संबंधित विभागों से राय लेता है और उसके अनुरूप निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 26 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने तीन प्रचलित भाषाओं बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष भेजा था।

एएनआइ के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की मांग की।

राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को मिला तीन साल का सेवा विस्तार

संजय कोठारी फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव संजय कोठारी के सेवा विस्तार को सरकार ने बुधवार को हरी झंडी दे दी। आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने 1978 बैच (हरियाणा कैडर) के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी कोठारी के सेवा विस्तार को हरी झंडे दी दी। उनका सेवा विस्तार राष्ट्रपति कार्यकाल के समानांतर या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके कोठारी को राष्ट्रपति ने अपना सचिव नियुक्त किया था। अब वह राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल (25 जुलाई 2022) खत्म होने तक उनके सचिव बने रहेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोठारी लोक सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई थी, जिसकी अवधि बुधवार को खत्म हो गई।

हिंदी गानों के शौकीन द्रमुक सांसद मैत्रेयन समेत पांच सांसदों की विदाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **राज्यसभा से डी राजा सहित एक साथ पांच सदस्य हुए सेवानिवृत्त**
- **पेशे से डॉक्टर मैत्रेयन राज्यसभा में रहे साढ़े चौदह साल**
- **गुलाम नबी आजाद ने मैत्रेयन और डी राजा दोनों की जमकर तारीफ की**

नई दिल्ली में बुधवार को राज्यसभा में अन्नाद्रमुक नेता डॉ वी. मैत्रेयन अपने विदाई भाषण के दौरान भावुक हो गए। एएनआइ

राज्यसभा में बुधवार को बेहद भावुक माहौल था। सदन में जीवन का एक लंबा वक्त गुजारने के बाद कई सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे थे। इनमें जो बेहद खास नाम था वह अन्नाद्रमुक नेता डॉ वी. मैत्रेयन और भाकपा नेता डी राजा का था। इस बीच सदन में साढ़े चौदह साल गुजारने वाले डॉ. मैत्रेयन तो भावुक भी हो उठे। उन्होंने कहा कि वह सदन में भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी आवाज को लोग जरूर याद रखेंगे। उन्होंने इस दौरान एक गीत भी गुनगुनाया। वहीं डी राजा ने कहा कि वह जहां भी रहेंगे, आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। डी राजा को भाकपा ने पार्टी का महासचिव बनाया है।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे सभी पांच सदस्यों को विदाई दी गई। इनमें मैत्रेयन, डी राजा, केआर अर्जुनन, डॉ. आर लक्ष्मणन, टी. रथीनवेल थे। डी राजा को छोड़कर इनमें सभी अन्नाद्रमुक पार्टी के सासंद थे।

विदाई भाषण के दौरान मैत्रेयन की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है। सपा सासंद रामगोपाल ने उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वह हिंदी गानों के काफी शौकीन थे। जब भी उन्हें हिंदी गाने सुनने की इच्छा होती थी, वह मैत्रेयन के पास जाकर सिर्फ एक लाइन गुनगुनाते थे। फिर तो वह पूरा गाना सुनाते थे।

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी मैत्रेयन और डी राजा दोनों की जमकर तारीफ की। कहा कि डी राजा अब पहले ज्यादा सक्रिय दिखेंगे। उन्हें उनकी पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। जबकि मैत्रेयन जो कि पेशे से डॉक्टर है, वह भी अपने पेशे में कुछ बेहतर करेंगे। वैसे भी वह समाज सेवा के चलते राजनीति में आए थे, जहां उन्हें प्रतिदिन सिर्फ दो हजार रुपये ही भत्ता मिलता है, जबकि वह करोड़ों कमा सकते हैं। वह जनहित के लिए ही राजनीति में सक्रिय हैं।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी डॉ मैत्रेयन की जमकर तारीफ की और कहा कि वह सदन को बताना चाहते हैं कि मैत्रेयन जी हिंदी गाने ही नहीं गाते हैं बल्कि वह मराठी गाने भी गाते हैं। उनका मराठी से भी गहरा जुड़ाव है। वह लंबे समय तक नागपुर में रहे हैं। इस दौरान सदन के और भी कई सदस्यों ने सेवानिवृत्त हो रहे पांचों सदस्यों के काम-काज की तारीफ की। इस दौरान माहौल बेहद भावकतापूर्ण हो गया।

केवल पाक से बातचीत गुलाम कश्मीर समेत हर मुद्दे पर होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर संबंधी बयान को लेकर जहां विपक्षी दलों का तेवर गर्म है, वहीं बुधवार को सरकार ने चर्चा को थोड़ा मोड़ते हुए कहा कि कश्मीर पर मध्यस्थता तो दूर की बात है, अगर पाकिस्तान से भी बात होगी तो वह गुलाम कश्मीर तक जाएगी।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार 'प्रधानमंत्री सदन में आओ' के नारे लगाते रहे विपक्ष ने शून्यकाल में अवसर मिलने पर कहा कि चूंकि अब तक ट्रंप की ओर से बयान पर सफाई नहीं आई है इसीलिए जरूरी है पीएम बताएं कि ट्रंप ने जो कुछ कहा था वह सच है या नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि भारत के पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। हालांकि खुद अमेरिका ने इस बयान को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते इससे पहले ही विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। राजनाथ ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। शिमला समझौते में तय हुआ था कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और उससे डिगने का सवाल ही नहीं है।

सख्त रुख

अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने मांगा जवाब

अवैध रेत खनन में केंद्र और पांच राज्यों को नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन का मामला**
- **अवैध खनन की जांच और खनन पट्टे निरस्त करने की मांग की गई है**

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर रोक लगाने और अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे रद करने की मांग पर केंद्र और पांच राज्यों तथा सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पांच राज्यों में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

ये नोटिस बुधवार को न्यायाधीश एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता एम अलागरसामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। शुरुआत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेवा से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को देखने का मौका मिलता। इस पर भूषण ने कहा कि पूरे देश में नदियों और समुद्र के किनारों पर अवैध रेत खनन हो रहा है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे खनन को नियमित करें, लेकिन राज्य ऐसा कर पाने में नाकाम हैं।

उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए और उनके पट्टे रद किए जाएं। पर्यावरण प्रभाव आकलन और नियमों के सख्त अनुपालन के बगैर रेत खनन की इजाजत न दी जाए। याचिका में अवैध रेत खनन मामलों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग करते हुए तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन के बाबत आई रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन और जन परामर्श व पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना 2006 के आकलन के बगैर रेत खनन की पर्यावरण मंजूरी नहीं देंगी।

उन्होंने कहा कि रेत खनन का पट्टा रखने वाले सभी पट्टाधारकों को आदेश दिया जाए कि वे पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन और अधिसूचना 2006 के लिए आवेदन करें। केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह उस क्षेत्र में रेत खनन के पर्यावरण प्रभाव का आंकलन किए बगैर कोई मंजूरी नहीं देगी। इसके अलावा एमएमडीआर कानून-1957 के तहत खनन प्लान मंजूर कराना जरूरी किया जाए। कहा गया है कि रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 को कड़ाई से लागू किया जाए। मांग है कि याचिका में अवैध रेत खनन घोटाले के जो प्रकरण उठाए गए हैं उनकी सीबीआइ से जांच कराई जाए। इसके साथ ही जो खनन पट्टा धारक अवैध खनन के दोषी पाए जाते हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए और उनके पट्टे निरस्त किए जाएं। अवैध खनन पर सख्त कदम उठाया जाए।

राज्य की योजनाओं में भी आधार के इस्तेमाल के संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कैबिनेट ने बुधवार को आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक-2019 में बदलावों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें राज्य की योजनाओं और सब्सिडी के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल को मंजूरी देने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, राज्यों ने (इसकी) मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आधार का इस्तेमाल वहीं हो सकता है जहां कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन सीधे केंद्र से मिलता हो।

इस संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में भी आधार का इस्तेमाल हो सकेगा। इस माह की शुरुआत में संसद ने इस कानून में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी। जिसमें सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने में आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि संसद में उक्त संशोधन विधेयक पेश होने के बाद उसमें राज्य योजनाओं में इसके इस्तेमाल संबंधी प्रावधान जोड़ दिया गया था, इसलिए कैबिनेट द्वारा बुधवार को दी गई मंजूरी सिर्फ औपचारिकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

5906 मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान बिजली की जर्जर लाइनों के कारण। सपा की विधायक लीलावती कुशवाहा के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने यह जानकारी दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 25 जुलाई 2019

उप्र की अर्थव्यवस्था एक लाख करोड़ डॉलर की बनाएंगे : योगी

दावा ▶ विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा– लक्ष्य मुश्किल नहीं है

पर्यटन संवर्द्धन योजना की घोषणा, प्रत्येक जिले में होगा पर्यटन स्थल का विकास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरूआत करते हुए यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डॉलर की बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल नहीं क्योंकि प्रदेश में संसाधन कम नहीं और यहीं सबसे ज्यादा युवा ऊर्जा भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना की घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने दो घंटे से अधिक लंबे संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना, पंचायती राज, नगर विकास, खाद्य एवं आपूर्ति और सिंचाई जैसे विभागों की पीठ भी थपथपाई। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, गन्ना मूल्य भुगतान व इथेनाल उत्पादन में प्रदेश के अव्वल आने के साथ वित्तीय अनुशासन को भी सराहा। उन्होंने प्रदेश का बजट पांच लाख करोड़ रुपये के निकट होने का जिक्र करते हुए बताया कि

लखनऊ में बुधवार को सदन को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

अधिकतर धनराशि को खर्च कर लिया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की खैरात बांटने की प्रवृत्ति पर तंज करते हुए कहा कि जनता ने झूठी घोषणाएं करके बरगलाने वालों को ठुकरा दिया और विकास की लाज रखी। अब प्रदेश सही रास्ते पर है और माहौल बदला है।

कुंभ मेला, प्रवासी भारतीय दिवस और लोकसभा चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों व प्रशासनिक मशीनरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि सात चरणों में ही पश्चिमी बंगाल में भी चुनाव था, लेकिन वहां प्रत्येक चरण में भारी हिंसा व नरसंहार हुआ। प्रदेश में कहीं हिंसा नहीं हुई। योगी ने विभिन्न योजनाओं से लोगों की जिंदगी में बदलाव की जानकारी भी दी।

मोदी सरकार कर रही लोहिया का सपना साकार : मुख्यमंत्री का कहना था कि अब चेहरा, जाति और धर्म देखकर विकास नहीं होता। डा. राममनोहर लोहिया की इच्छा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लोहिया चाहते थे कि हर गरीब के घर में शौचालय हो और उसे ईलाज मिले। लोहिया के नाम पर राजनीति करने व विरासत भुनाने वालों ने इस ओर कभी नहीं सोचा। मोदी सरकार डा. लोहिया का सपना साकार कर रही है। दो करोड़ 90 लाख शौचालयों का निर्माण कराने के अलावा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मुहैया कराए जा रहें हैं। आयुष्मान योजना में बिना भेदभाव इलाज हो रहा है। वहीं एक करोड़ 31 लाख घरों में गैस सिलेंडर और एक करोड़ आठ लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

योगी ने किसान हित में किए कार्य गिनाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा उकसाने के बावजूद किसानों ने कोई भी आंदोलन नहीं किया। उपज उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने और सरकारी खरीद की व्यवस्था बेहतर बनाए जाने का किसानों को लाभ मिला है। पूंजी निवेश में अप्रत्याशित वृद्धि का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि जो उद्यमी प्रदेश छोड़ कर भाग रहे थे अब अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने निवेश से दो वर्ष में 28 लाख रोजगार सृजन की जानकारी भी दी। स्वच्छता अभियान का अच्छा परिणाम आने का जिक्र करते हुए जेई व एई जैसी गंभीर बीमारियों में कमी आने की बात भी कही।

पर्यटन स्थल विकास में विधायक निधि भी लगेगी : मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एक पर्यटन स्थल को विकसित करने की योजना में स्थानीय विधायकों से निधि का प्रयोग करने का भी आग्रह किया। जिलों में पर्यटन स्थल चिन्हित करने का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने 17 नगर निगमों को स्मार्ट बनाने की जानकारी देते हुए कहा कि दस नगर निगम केंद्रीय योजना में आ गए है और शेष सात नगर निगमों का भी उसी तरह विकास किया जाएगा।

मंत्रीजी! आपका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र बना कि नहीं?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ **17 अति पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर सपा ने विधान परिषद में सरकार को घेरा**

▶ **कहा, उपचुनाव देख सरकार ने जारी किया झूठा शासनादेश**

सत्रह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बुधवार को विधान परिषद में सरकार को घेरा और काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की। सपा सदस्यों ने सरकार से जानना चाहा कि इन अति पिछड़ी जातियों के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनाने का जो शासनादेश योगी सरकार ने जारी किया है, उसके तहत अब तक कितने प्रमाणपत्र बने? सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर था।

सपा के राजपाल कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2017 को आदेश दिया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनाया जाए। भाजपा सरकार ने सवा दो साल तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए उसने इन अति पिछड़ी जातियों के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनाने का झूठा शासनादेश जारी कर दिया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल राजभर से पूछा 'मंत्रीजी, आप भी तो इन 17 अति पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। बताइये आपका अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बना कि नहीं?' मंत्री लाजवाब हो गए। सपा के राम सुंदर दास, रामजतन राजभर ने भी सरकार पर हमले किए।

नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य की भाजपा सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर विपक्षी दलों ने 'शेम-शेम' कहा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने दलील दी कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा उचित नहीं। अधिष्ठाता के कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर सपा सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की और फिर विरोधस्वरूप सदन से बाहर चले गए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय बताने वाले समूह में शाह

अमित शाह फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं और कानून को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय मंत्री समूह का पुनर्गठन किया गया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं।

पुरानी सरकार के कार्यकाल में इस मंत्री समूह में पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो अब रक्षा मंत्री हैं। इस समूह में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी शामिल थीं।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा मामले में फैसला देते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। वर्ष 2018 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का कानून बना और लागू हुआ। इसके तहत हर दफ्तर में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए जांच समिति का होना जरूरी है।

हाई कोर्ट ने नरबीर से पूछा, क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस चलाया जाए

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

नामांकन के समय शपथ पत्र में गलत व विरोधाभासी जानकारी देने के मामले में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राव को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक व धोखाधड़ी का मामला चलाया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस एएस ग्रेवाल ने राव को 27 अगस्त तक इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।

गुरुग्राम के आरटीआइ कार्यकर्ता हरिंदर ढींगरा ने हाई कोर्ट में रीविजन याचिका दायर करते हुए गुरुग्राम कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की, जिसमें राव नरबीर के खिलाफ फर्जी शैक्षिक योग्यता दर्शाने संबंधी उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था। यह याचिका पिछले सप्ताह भी हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। उस समय हाई कोर्ट ने याची को कहा था कि वह पहले कोर्ट को इस बाबत संतुष्ट करें कि यह याचिका हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है। बुधवार को याची के वकील ने इस बाबत अपना पक्ष रखा। हाई

राव नरबीर फाइल फोटो

▶ **चुनाव के दौरान शपथ पत्र में हरियाणा के मंत्री द्वारा गलत व विरोधाभासी जानकारी देने का मामला**

▶ **गुरुग्राम कोर्ट ने राव नरबीर को राहत देते हुए इस मामले को कर दिया था खारिज**

कोर्ट ने उस पर संतुष्टि जताते हुए राव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

याचिका के अनुसार हरिंदर ढींगरा ने राव नरबीर की शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। दिसंबर 2018 को उन्हें नरबीर के शपथ पत्रों और शैक्षिक योग्यता की जानकारी मिली। ढींगरा का आरोप है कि नरबीर ने वर्ष 2005, 2009 और 2014 में चुनाव लड़ा और शपथ पत्र दाखिल किया। उन्होंने वर्ष 2005 में शपथपत्र दाखिल किया कि 10वीं की पढ़ाई 1976 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से पास की है। 2009 के चुनाव में शपथ पत्र दाखिल किया कि उन्होंने 10वीं बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से की है। वहीं वर्ष 1986 में राव नरबीर ने हिंदी साहित्य में स्नातक करने की बात कही है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि नरबीर ने चुनाव में झूठे शैक्षिक पत्र दाखिल किए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में राजस्थान प्रदेश बनाम सरदार शहर एवं अन्य की सुनवाई करते हुए कहा था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन को विश्वविद्यालय या बोर्ड की मान्यता नहीं है। 1997 में रामभगत शर्मा बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि यह विश्वविद्यालय अमान्य है। इससे डिग्री लेकर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को हटाया जाए। इस बाबत उन्होंने चुनाव आयोग को भी शिकायत भेजी थी जिसमें आयोग की तरफ से उन्हें अधिकार क्षेत्र की अदालत में शिकायत करने की सलाह दी थी गई थी। इसी आधार पर उन्होंने पहले गुरुग्राम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज कर दी गई थी।

अब 25 एकड़ में भी बन सकेंगे निजी विश्वविद्यालय

पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला, 35 एकड़ की शर्त में की कटौती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ **रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी के पास पहुंची**

▶ **राज्य में फिलहाल करीब 23 निजी विश्वविद्यालय हैं**

पंजाब कैबिनेट ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए 35 एकड़ जमीन की शर्त में कटौती कर इसे 25 एकड़ कर दिया है। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। राज्य में पहले ही करीब 23 निजी विश्वविद्यालय स्थापित है। मंत्रिमंडल ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी-2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार का मानना है कि इससे निजी विश्वविद्यालयों में निवेश बढ़ेगा और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब के युवा विदेश जा रहे हैं और राज्य में जो भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उनमें दूसरे राज्यों से विद्यार्थी आ दाखिला ले रहे हैं।

वहीं, इन विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रह रही हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ निजी विश्वविद्यालय ऐसे कोर्स करवा रहे हैं, जिनका कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है और वे छात्रों को रोजगार देने में विफल साबित हो रहे है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को बताया कि विशेषज्ञ

चंडीगढ़ में बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते सीएम कै. अमरिंदर सिंह। जागरण

कमेटी की रिपोर्ट सब कमेटी के पास पहुंच गई है। अभी इसका आकलन किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया था। निजी विश्वविद्यालयों के लिए जमीन की सीमा को घटाने के पीछे पंजाब कैबिनेट का तर्क यह भी है कि पंजाब में जमीन का मूल्य काफी है। वहीं, इससे कृषि वाली जमीन भी बचेगी।

राज्यों में अलग-अलग शर्तें : सभी राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए जमीन से संबंधित अलग-अलग शर्तें हैं। हरियाणा में यह नगरपालिका सीमा के बाहर 20 एकड़ और नगरपालिका सीमा के भीतर 10 एकड़ है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम सीमा 10 एकड़ है, जबकि राजस्थान मे 30, मध्य प्रदेश 20 एकड़ है। महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 50 एकड़, तहसील या जिला मुख्यालय में 25 एकड़, मंडल मुख्यालय में 15 एकड़ और मुंबई महानगर में 10 एकड़ जमीन की शर्त है।

गुणवत्ता पर काम हो

अकाली दल के विधायक पवन टीनू का कहना है कि पंजाब कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय के लिए जमीन की सीमा को घटाने से उच्च शिक्षा पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। पहले ही राज्य में काफी निजी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। इनका शिक्षा स्तर बेहद औसत है। कुछ को छोड़ कर बाकी विश्वविद्यालयों को पूर्ण विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में और विश्वविद्यालय आने से कोई लाभ नहीं होगा। जरूरत शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र दो से छह अगस्त तक

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र दो से छह अगस्त तक होगा। यह फैसला बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया। दो अगस्त को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि तीन और चार को अवकाश रहेगा। पांच और छह अगस्त को क्रमशः सुबह 10 बजे कामकाज शुरू होगा।

नड्डा, शाह और मोदी रखेंगे भाजपा के मिशन 75 की नींव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ **6 अगस्त को हिसार और 16 अगस्त को जींद में गरजेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह**

▶ **मुख्यमंत्री की रथयात्रा के बाद विजय संकल्प रैली, मोदी आएंगे रोहतक में**

भाजपा ने मिशन 75 प्लस को हासिल करने के लिए सत्ता व संगठन के स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम लगभग तय हैं। केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला इसे देख रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों के लिए हाईकमान की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रथ यात्रा कालका से शुरू होकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।

–राजीव जैन, मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री हरियाणा

हरियाणा में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। भाजपा के लिए चुनावी माहौल तैयार करने को भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह दो बार हरियाणा आने वाले हैं। 6 अगस्त को हिसार आएंगे और 16 अगस्त को राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र सिंह के बुलावे पर जींद पहुंचेंगे।

भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार हरियाणा आ रहे हैं। 27 व 28 जुलाई के रोहतक प्रवास के दौरान नड्डा 13 बैठकों व कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के लिए पार्टी ने अलग-अलग प्रमुख नियुक्त कर दिए हैं। नड्डा रोहतक प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से अलग-अलग बैठकें करेंगे और 4200 शक्ति केंद्र प्रमुखों व पालकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस बैठक के प्रमुख जवाहर सैनी होंगे। जेपी नड्डा के दौरे के दौरान दो अहम बैठकें होंगी। एक बैठक भाजपा कोर ग्रुप की रहेगी और दूसरी बैठक में विधायकों तथा सांसदों के साथ संवाद किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी करनाल के सांसद एवं प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया को सौंपी गई है। जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन और सदस्यता प्रमुखों की बैठक के कार्यक्रम प्रमुख सत्यवान शेरा होंगे। मीडिया विभाग की बैठक रणदीप घनघस और अरुण यादव की देखरेख में होगी। प्रेस आयोजन की जिम्मेदारी गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल को दी गई है। इन कार्यक्रमों के प्रभारी प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी होंगे।

जेपी नड्डा के कार्यकमों के बाद छह अगस्त को भाजपा अध्यक्ष एवं गृहमंत्री अमित शाह हिसार के अग्रोहा मेडिकल कालेज का दौरा करेंगे। यहां वह नई इमारत का उदघाटन करेंगे। अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। शाह के दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल रथ पर सवार होकर पूरा हरियाणा मापेंगे। मुख्यमंत्री 18 अगस्त को कालका से अपनी 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू करेंगे।

सप्ताह में तीन दिन रथ पर 18 हलके कवर करेंगे सीएम : मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रथयात्रा सप्ताह में तीन दिन चलेगी। सीएम रोजाना छह विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र, दस लोकसभा क्षेत्र तथा 22 जिलों को कवर करेंगे। मुख्यमंत्री की 'जन आशीर्वाद यात्रा' का समापन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृहक्षेत्र रोहतक में होगा। यात्रा का समापन आठ या दस सितंबर को रोहतक में किया जाएगा।

हुड्डा के गृह जिले रोहतक में मोदी की विजय संकल्प रैली : भाजपा की रोहतक में होने वाली विजय संकल्प रैली का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अभी रैली की तिथि फाइनल नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में भी मोदी व शाह की जोड़ी हुड्डा तथा चौटाला के गढ़ में सक्रिय रही थी।

मोदी की रोहतक रैली से बड़ा संदेश देगी भाजपा : भाजपा ने रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन करके विपक्षी राजनीतिक दलों को बड़ा संदेश देने की योजना बनाई है। दूसरी बार सत्ता हासिल करने समय भाजपा के निशाने पर रोहतक व सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हैं। पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस को इसी क्षेत्र से जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया लेकिन भाजपा की परीक्षा विधानसभा में होगी।

झारखंड विधानसभा में गूंजे जय श्रीराम के नारे

राज्य ब्यूरो, रांची

आदिवासी हितों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के मंजर तो सदन में अक्सर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बुधवार को झारखंड विधानसभा में इसमें जय श्रीराम का नारा भी जुड़ गया। भारतीय वन कानून 1927 में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर झामुमो विधायकों के हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। सदन के अंदर लगे नारे पर बाहर भी दोनों पक्षों की ओर से तल्खी देखी गई। हो-हंगामे की वजह से सदन की पहली और दूसरी पाली में कोई कामकाज नहीं हुआ, प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा। शोरगुल के बीच स्पीकर दिनेश उरांव ने कुछ विधायी कार्यों की औपचारिकता जरूर पूरी की।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही झामुमो विधायक कुणाल षाडंगी ने भारतीय वन कानून 1927 में संशोधन पर राज्य सरकार से मांगे गए जवाब पर मंतव्य स्पष्ट करने की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने अमान्य करार दिया।

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर मंत्री अमर बाउरी और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान हाथ में बंधा धागा दिखाते इरफान। जागरण

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन समेत झामुमो के वरिष्ठ विधायक इस मसले पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करने की मांग करने लगे। स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बाद भी वह नहीं माने और वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर प्रश्नकाल बाधित करने का आरोप लगाया गया।

इधर, सत्ता पक्ष के कुछ विधायक खड़े होकर झामुमो नेताओं के रुख को अनुचित ठहराने लगे। इस बीच झामुमो विधायकों का वेल में प्रदर्शन जारी रहा। मंत्री सीपी सिंह ने झामुमो विधायकों की चुटकी भी ली। कहा ... इनके मर्ज की दवा क्या है। इस बीच भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने भारत माता की जय और जय श्रीराम का नारा लगा दिया। झामुमो विधायक पौलुस सुरीन बोल उठे, श्रीराम नहीं चलेगा। वह जय सरना बोलते सुने गए। इसपर सत्ता पक्ष के कई विधायक खड़े हो गए और जय श्रीराम के नारे लगाने लगे। स्पीकर दिनेश उरांव ने सदन के माहौल को देखते हुए कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

चिंता की बात

मिलक पिछौड़ा गांव के हिंदुओं ने मंदिर में पूजा न करने देने का आरोप लगाया, अधिकारियों ने कहा कि खुराफात करने वालों पर होगी कार्रवाई

अब बरेली में दी गई पलायन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बरेली

उत्तर प्रदेश के शामली स्थित कैराना के बाद मेरठ से पलायन का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब बरेली में हिंदुओं ने पलायन की चेतावनी दी है। बहेड़ी के मिलक पिछौड़ा गांव में रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि उन्हें पूजा-पाठ तक नहीं करने दिया जा रहा। गांव में संप्रदाय विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा है, जो उन्हें मंदिर जाने से रोकते हैं। कुछ महिलाओं ने धमकी दी है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो यहां से पलायन कर कोई दूसरी सुरक्षित जगह तलाश लेंगे। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो कहा जा रहा कि किसी भी समुदाय पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं लगा सकता। जो खुराफात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी।

बहेड़ी तहसील के गांव मिलक पिछौड़ा में नौ सौ परिवार रहते हैं। इनमें करीब 150 परिवार हिंदुओं के हैं। हिंदू समुदाय की महिलाओं का आरोप है कि संप्रदाय विशेष के लोग मंदिर में घंटा बजाने, जल चढ़ाने तक तक से उन्हें रोकते हैं। यदि कोई उनका विरोध करता है तो बेटियों को घर से खींच ले जाने की धमकी देते हैं। गांव की नन्ही देवी, सरस्वती ने

बरेली स्थित बहेड़ी के मिलक पिछौड़ा गांव में पूजा नहीं करने का गंभीर आरोप लगाती महिलाएं। (सौ. वीडियो ग्रैब)

बताया कि पिछले सप्ताह मंदिर की साफ-सफाई करनी चाही तो संप्रदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध किया। सभी अधिकारियों से शिकायत की मगर, समाधान नहीं निकला। क्षेत्रीय विधायक छत्रपाल सिंह को भी इस बाबत बताया था, मगर सहयोग नहीं मिला। इस संबंध में विधायक छत्रपाल सिंह ने कहा कि 'मैं लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही में हूं। मुझे मामले की कोई जानकारी नहीं है। न ही मुझसे किसी गांव वाले ने इस बाबत अब तक संपर्क किया है।'

हिंदू पक्ष की महिलाओं ने इस बाबत एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वह कह रही हैं कि गांव से कांवड़ियों को जल लेने के लिए जाना था। इसके लिए पुलिस को सूचना दी तो आवेदन मांगा गया, फॉर्म भराए गए। इसके बाद अचानक पुलिस वालों ने कह दिया कि न तो कोई कांवड़ लेकर जाएगा और न ही मंदिर में जलाभिषेक होगा। महिलाओं ने यहां तक कह दिया कि इस तरह घुटकर और धार्मिक भावनाएं आहत कर जीने से क्या फायदा?

एसडीएम ममता मालवीय का कहना है कि अगर कोई पूजा-अर्चना करने से रोकने की कोशिश करेगा तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। कुछ लोग जानबूझकर मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में मंदिर मरम्मत पर फिलहाल रोक लगाई गई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद सर्वमान्य फैसला लिया जाएगा।

मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 74 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 74 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति दे दी है। गृह व न्याय विभाग ने इन मुकदमों को वापस लिए जाने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब वे मुकदमे कोर्ट के हवाले हो गए हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री व विधायक भी आरोपित थे।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के बाद दंगा भड़क गया था। हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। इस मामले में 500 से अधिक आरोपितों के खिलाफ हत्या, बलवा, धार्मिक उन्माद फैलाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बताया गया है कि मुजफ्फरनगर दंगे के चिह्नित 92 मुकदमों को वापस किए जाने की कसरत शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव से पूर्व शासन में इसे लेकर हुई बैठकों में अहम निर्णय किए गए थे। सरकार ने इनमें से 74 मुकदमों को वापस लेने की प्रकिया शुरू कर दी थी।

ओडिशा की पाटकुरा विस सीट पर बीजद का कब्जा कायम

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

▶ **उपचुनाव में सावित्री अग्रवाल ने भाजपा के विजय महापात्र को 17, 655 वोट से हराया**

▶ **कांग्रेस के जयंत महांती को मिले कुल 2090 मत**

केंद्रपाड़ा संसदीय क्षेत्र के पाटकुरा विधानसभा सीट पर बीजू जनता दल (बीजद) ने अपना दबदबा कायम रखा है। बुधवार को हुई मतगणना में बीजद की उम्मीदवार सावित्री अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के विजय महापात्र को 17,655 मतों से पराजित कर दिया। सावित्री अग्रवाल को 95,162 वोट मिले हैं जबकि भाजपा के विजय महापात्र को 77,507 एवं कांग्रेस के जयंत महांती को 2,090 वोट पर संतोष करना पड़ा है।

इसके साथ ही विधानसभा में जाने के लिए लंबे अर्से से इंतजार करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय महापात्र को अब और इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को हुई मतगणना के पहले ही राउंड से बीजद उम्मीदवार सावित्री अग्रवाल ने बढ़त बनाए रखी और इस सिलसिले को जीत दर्ज कर ही खत्म किया। इसी के साथ एक बार फिर पाटकुरा में बीजद सुप्रीमो सह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जादू भी कायम रहा। चुनाव जीतने के बाद सावित्री अग्रवाल ने नवीन पटनायक को धन्यवाद देने समेत जीत का श्रेय पाटकुरा के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि अपनी जीत को लेकर मुझे पूरा विश्वास था। यहां पर किसी स्वाभिमान या सम्मान की जीत नहीं हुई है, बल्कि कर्म की जीत हुई है, जिस कर्म को मैं पिछले 10 साल से करती आ रही हूं। उन्होंने कहा लोग चाहते हैं कि उनका जो नेता हो वह उनके सुख-दुख में शामिल हो।

उल्लेखनीय है कि आम चुनाव के समय बीजू जनता दल उम्मीदवार वेद प्रकाश अग्रवाल के निधन के कारण पाटकुरा विस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

स्पेस वार में धमक दिखाने को भारत बेकरार

भविष्य के युद्ध मैदानों में नहीं होंगे और न ही इनमें बंदूक और तोपों का इस्तेमाल होगा। आने-वाले दिनों की इन जंगों को अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। विशुद्ध तकनीक और उपग्रह आधारित इस जंग में जो विजेता होगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। स्पेस वार (अंतरिक्ष में जंग) के लिए खुद को तैयार करने के लिए तमाम देश तेजी से जुटे हैं। इस तैयारी में भारत भी पीछे नहीं है। भारत इस आशय का 'इंडियास्पेसएक्स' नामक दो दिवसीय युद्धाभ्यास आज यानी 25 जुलाई से शुरू कर रहा है जिसमें देश की तीनों सेनाएं और मशहूर वैज्ञानिक शामिल होंगे।

ऑपरेशन शक्ति का मतलब

इसी साल 27 मार्च को भारत ने अपने एक सक्रिय सेटेलाइट को धरती से मिसाइल दाग कर मार गिराया था। इसे एंटी सेटेलाइट वीपन (ए-सैट) कहा गया। इस सफल ऑपरेशन ने भारत को स्पेस वार में सक्षम देशों के बरक्स खड़ा कर दिया था।

सिर्फ चार देश ही सक्षम

अंतरिक्ष में मौजूद किसी सेटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भारत समेत चार देशों के पास ही है। अमेरिका, रूस और चीन के पास यह तकनीक मौजूद है।

सेटेलाइट के साथ आया विचार

कोई भी नई तकनीक की खोज के साथ उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, यह बात भी वैज्ञानिकों के दिमाग में आती है। लिहाजा अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे किसी सेटेलाइट को नष्ट करने का विचार

अमेरिकी वैज्ञानिकों के पास स्पुतनिक को छोड़ने के एक साल बाद यानी 1958 में आ गया था। तभी इसने पहला ए-सैट परीक्षण किया, लेकिन विफलता हाथ लगी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने यह तकनीक विकसित की।

अमेरिका बहुत आगे

अमेरिका ने तो ऐसे एंटी सेटेलाइट वीपन या मिसाइल तैयार कर लिए हैं जिसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल हैं। चीन ने अपना पहला ए-सैट परीक्षण 2007 में अंजाम दिया।

अनुशासन बरकरार

चार देशों के पास ही यह क्षमता है कि वे अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे किसी देश के सेटेलाइट को पल में तबाह कर दें। लेकिन अब तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चारों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। अगर भूल से भी ऐसी घटना होती है तो दुनिया के सामने बहुत भयावह स्थिति होगी।

बड़े काम के सेटेलाइट

हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम आज सेटेलाइट के बूते चल रहे हैं। आवागमन हो, संचार हो, मौसम या मनोरंजन। सैन्य गतिविधियां भी इसी सेटेलाइट पर आश्रित हैं। ऐसे में दुश्मन देश के सेटेलाइट को निशाना बनाकर उसे घुटने टेकने पर विवश किया जा सकता है। उसके लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल जखीरा सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। उसका वह इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा।

पूर्व प्रधानमंत्रियों का पहला म्यूजियम दिल्ली में बनेगा

मोदी का एलान ▶ राजनीतिक छुआछूत से परे और तथ्यपरक होगा

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब का किया विमोचन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्रियों का पहला म्यूजियम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन करने के बाद यह एलान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि म्यूजियम राजनीतिक छुआछूत से परे होगा।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की लिखी किताब का विमोचन करते हुए मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने गांव, गरीब और किसान के जीवनस्तर को उठाने और उन्हें जानने के लिए सबसे लंबी पदयात्रा कर डाली। मोदी ने क्षोभ प्रकट करते हुए कहा, 'दुर्भाग्य यह है कि उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि को चंदे और भ्रष्टाचार (डोनेशन व करप्शन) के इर्दगिर्द ही रखा गया। यह किसी सोची समझी सोच का हिस्सा है। यह बहुत अखरता है।' मालूम हो कि चंद्रशेखर ने छह जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक कन्याकुमारी से दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट तक 4,260 किलोमीटर की पदयात्रा की थी।

मोदी ने कहा कि यह हरिवंश की हिम्मत है।

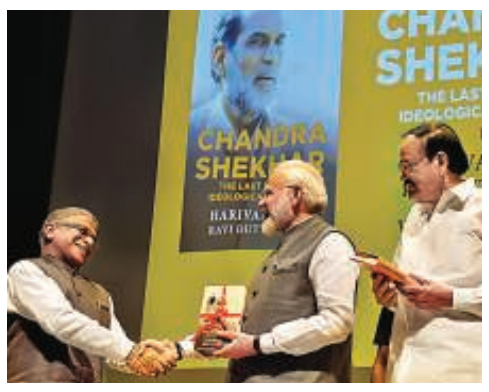

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू भी मौजूद रहे। एएनआइ

नहीं तो एक जमात है जिसने आंबेडकर और सरदार पटेल की छवि धूमिल की है। चुटकी लेने के अंदाज में उन्होंने कहा, 'लाल बहादुर शास्त्री जीवित लौटे (ताशकंद से) होते तो उन्हें न जाने किन रूपों में पेश किया जाता।' मोरारजी और देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्रियों को भी ऐसे ही पेश किया गया है। मोदी ने जोर देकर कहा, 'मैंने भी ठान ली है।' थोड़ा ठिठकने के बाद अपने अंदाज में उन्होंने एलान किया कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का आधुनिक म्यूजियम बनेगा। इसमें उनसे जुड़ी सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी। यह म्यूजियम राजनीतिक छुआछूत से परे होगा।

मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। उन्हें तो युवा तुर्क ही कहा जाता था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन से विदाई के बाद लोग भूल जाते हैं। इतिहास के कोने में कहीं खो जाते हैं। लेकिन विदाई के 12 बरस बाद भी चंद्रशेखर जी हमारे बीच वैसे ही हैं। हरिवंश के बारे में उन्होंने कहा कि कल तक हरवंश पत्रकार थे और अब राज्यसभा में निष्पक्ष उपसभापति, लेकिन चंद्रशेखर पर किताब लिखने के बाद न जाने उनके ऊपर कौन-कौन से लेबल लगेंगे।

इससे पूर्व उनके पड़ोसी रहे गुलाम नबी आजाद ने चंद्रशेखर के बारे में कहा कि समाजवाद उनकी बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन, पहनावे और आचार-विचार सबमें था, लेकिन वर्तमान राजनीति में इसका अभाव है। उसकी जगह शक्ति, धन और सत्ता ने ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी जबर्दस्त याददाश्त के बारे में बताया। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने चंद्रशेखर की समाजवादी सोच के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी।

छह माह में चौथी बार साबित किया बहुमत

प्रथम पृष्ठ से आगे

पिछले छह माह में यह चौथा मौका था, जब कमलनाथ सरकार ने सदन में बहुमत साबित किया है। हैरत की बात तो यह है कि सतना के मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी और शहडोल के ब्यौहारी से भाजपा विधायक शरद कौल सरकार के साथ आ गए और विपक्ष को भनक तक नहीं लगी। इस शक्ति परीक्षण के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। हम राज्यपाल के पास जाएंगे और बताएंगे कि मतदान के दौरान आठ से दस विधायकों ने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं।

विधानसभा में शाम चार बजकर 47 मिनट पर अचानक माहौल बदला। दंड विधि में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा के दौरान बसपा विधायक संजीव सिंह संजू ने मत विभाजन की मांग रख दी। अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मांग पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन विधायक सिंह अड़े रहे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने खड़े होकर कहा कि विपक्ष इस विधेयक के पक्ष में है और सर्वसम्मति से इसे पारित किया जा रहा है, तब मत विभाजन की क्या आवश्यकता। इस पर लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा ने कहा कि एक भी विधायक यदि मत विभाजन की मांग कर रहा है तो इसे करना पड़ेगा। इस बीच अध्यक्ष ने दोबारा विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पढ़ा और संजीव ने फिर से मत विभाजन की मांग रख दी। आखिर अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान का एलान कर दिया।

पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-2

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत के दूसरे मून मिशन पर निकला चंद्रयान-2 धीरे-धीरे और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि पृथ्वी की कक्षा में 22 जुलाई को पहुंचने वाले चंद्रयान-2 की बुधवार को पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली गई है। चंद्रयान-2 को पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंचा दिया गया है। कक्षा परिवर्तन के दौरान अंतरिक्षयान को दूसरी ऊंची कक्षा में स्थापित किया जाता है।

इसरो ने बताया कि कक्षा परिवर्तन की यह प्रक्रिया बुधवार को दिन के 2:52 बजे पूरी हुई। अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि चंद्रमा की तरफ रवाना होने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगा रहा चंद्रयान-2 छह अगस्त तक चार बार अपनी कक्षा बदलेगा। अब 26 जुलाई को तड़के 1:09 बजे चंद्रयान-2 की कक्षा दूसरी बार बदली जाएगी। इसरो ने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 अगस्त तक चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। जबकि, 7 सितंबर को रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।

इसरो ने बताया कि लांच के बाद चंद्रयान-2 को पृथ्वी से कम दूरी वाले कक्ष में170 किलोमीटर पर स्थापित किया गया था। बुधवार को सफलतापूर्वक इसकी कक्षा बढ़ाई गई और उसे पृथ्वी की कक्षा में 230 किलोमीटर पर स्थापित कर दिया गया। 14 अगस्त तक चंद्रयान-2 चंद्रमा के करीब वाले कक्ष में पहुंच जाएगा। जहां से उसे 20 अगस्त तक चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा।

20 अगस्त तक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा चंद्रयान

07 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा रोवर प्रज्ञान

पृथ्वी से अपनी रवानगी के 48 दिन बाद चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। 3,850 किलोग्राम के चंद्रयान-2 के तीन हिस्से ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान हैं। ऑर्बिटर एक साल तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा जबकि लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। इसके बाद 7 सितंबर को विक्रम से रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस दौरान रोवर चंद्रमा की सतह पर परीक्षण और जांच करेगा।

2008 में भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था। यह आर्बिटर मिशन था, जिसने 10 महीने तक चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज इसी अभियान के दौरान हुई थी। चंद्रयान-2 इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए वहां पानी और अन्य खनिजों के प्रमाण जुटाएगा।

कोर्ट ने पूछा, गूगल को भारत के नक्शे अपलोड करने से रोक सकते हैं या नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट का गेट फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह जांच करने का निर्देश दिया कि गूगल को उसकी वेब सेवा पर रक्षा प्रतिष्ठानों समेत भारत के नक्शे अपलोड किए जाने से रोका जा सकता है या नहीं।

किसालय शुक्ला की ओर से दायर याचिका के अनुसार गूगल अर्थ पर अपलोड की गई या उपग्रह से ली गई तस्वीरों के जरिये उन भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों तक आम लोगों के साथ ही दुश्मनों की पहुंच आसान हो गई है, जो प्रतिबंधित हैं। भारत का विस्तृत नक्शा मुहैया कराने का अधिकार केवल भारत सरकार के पास है। इसलिए कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वह अपने नागरिकों को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली उपलब्ध कराए।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह विचार करे कि गूगल इंडिया को भारत के विस्तृत नक्शों को प्रकाशित करने से रोकना आवश्यक है या नहीं। याची ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गूगल को अपनी स्ट्रीट-व्यू-सर्विस उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सटी नियंत्रण रेखा के पास के भारतीय शहरों एवं इलाकों के चित्र गूगल अपलोड कर रहा है। याची ने दावा किया कि 2008 के मुंबई हमलों में शामिल एक आतंकी के अनुसार उन्होंने शहर संबंधी जानकारी लेने के लिए गूगल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था।

पश्चिम बंगाल में न्याय की उम्मीद नहीं : सुषमा स्वराज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने पश्चिम बंगाल के बिगड़े सुरक्षा हालातों पर राज्य की मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। वह पश्चिम बंगाल में हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बुधवार को दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन और कॉल फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचीं थी। यहां पश्चिम बंगाल के उन पीड़ित परिवारों को बुलाया था जिन्होंने अपने किसी करीबी को हिंसा में खोया है। आंकड़े बताते है कि इस राजनीतिक हिंसा से करीब 150 परिवार पीड़ित है, जिनमें 72 परिवार भाजपा कार्यकर्ताओं के है। इनमें से 23 परिवार बुधवार को दिल्ली न्याय पाने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कुछ दिनों पहले राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी कर सवाल भी पूछा था।

बदल गई है ममता : कार्यक्रम में सुषमा ने उस दौर को याद किया जब खुद ममता बनर्जी वामपंथी दलों के कार्यकाल में हिंसा का शिकार थी और हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाया करती थी। परिवारों का दर्द सुनकर स्वराज ने कहा कि यह वह ममता बनर्जी नहीं है जिन्हें वह सालों से जानती थी। हिंसा का शिकार हुए परिवार वालों की पीड़ा सुन स्वराज ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि कोई व्यक्ति इतना बर्बर और क्रूर कैसे हो सकता है। पूर्व विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो

▶ राजनीतिक हिंसा के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं के 23 परिवारों से मिलीं पूर्व विदेश मंत्री

सुषमा स्वराज फाइल फोटो

चुकी है। तृणमूल राज में किसी को भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

सिर्फ सत्ता के लिए यह सब : सुषमा ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का दोष सिर्फ इतना ही था कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े। सुष्मा ने कहा कि 'हम इंसाफ की उम्मीद करें अब किससे, जब मुंसिफ का हाथ ही खून से रंगा है।' स्वराज ने कहा कि ममता अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राज्य में यह सब होने दे रही हैं। पीड़ितों को उनके राज में न्याय नहीं मिल सकता। इस कार्यक्रम में मंच पर बुद्धिजीवियों का एक पैनल बनाया गया था, जिन्होंने पीड़ितों पर हुए अत्याचार और हिंसा के हालातों के बारे में जाना। यह पैनल एक रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपेगा।

'वंदे भारत' को लेकर प्रभुत्व की लड़ाई इलेक्ट्रिकल विभाग की बढ़ी शक्तियां

दीपक बहल, अंबाला

▶ इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स विभाग में अफसरशाही की जिम्मेदारियों को लेकर एक बार फिर किया बदलाव

▶ वंदे भारत और ईएमयू की मरम्मत अब इलेक्ट्रिकल विभाग के जिम्मे, पहले मेकेनिकल इंजीनियरों के थी हवाले

देश की महत्वाकांक्षी पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस और ईएमयू को लेकर प्रभुत्व की लड़ाई में फिर इलेक्ट्रिक विभाग की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। पहले जहां इन ट्रेनों की मरम्मत का काम मेकेनिकल विभाग के इंजीनियर के जिम्मे था, अब इलेक्ट्रिकल विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गेनाइजेशन) लखनऊ और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) चेन्नई में भी जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव किया जा रहा है। यहां पर भी मेकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल विभाग रुतबा बढ़ा दिया है। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस की मरम्मत का काम शकूरबस्ती में किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिकल विभाग चाहेगा कि इस ट्रेन की मरम्मत का काम गाजियाबाद शेड में ही किया जाए।

बता दें कि भारतीय रेल में प्रभुत्व के लिए अधिकारियों में खींचतान बढ़ गई थी। देशभर में दौड़ रही ईएमयू (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट) और एमईएमयू (मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) के कार शेड मेकेनिकल इंजीनियर्स के हवाले कर दिए गए थे। शताब्दी, राजधानी, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों में लाइट, पंखे और एसी की मरम्मत का काम मेकेनिकल इंजीनियर्स के अधीन कर दिया था।

इलेक्ट्रिकल विभाग का तर्क था कि 25 हजार वोल्ट से ईएमयू, एमईएमयू दौड़ती हैं, यदि इनका संचालन में कोताही बरती गई तो हादसा हो सकता है। दोनों विभाग में खींचतान इतनी बढ़ गई है कि इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारी बचाव में आ गए और कागजी जंग आरंभ हो गई।

इलेक्ट्रिकल के एचओडी मेकेनिकल विभाग के बना दिए गए। यहां तक कि रेलवे बोर्ड ने 3 अगस्त 2016 को इलेक्ट्रिकल की रिपोर्टिंग मेकेनिकल विभाग के आला अधिकारियों के अधीन कर दी थी। ऐसे हालात में दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता गौतम बनर्जी ने रेलवे के मेंबर इलेक्ट्रिकल को दो पेज का पत्र लिख इलेक्ट्रिकल विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मेकेनिकल विभाग को देने का विरोध किया था। इसे इलेक्ट्रिकल रूल्स 1956 का उल्लंघन भी बताया और दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड का भी जिक्र किया था, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी इंडियन रेलवे सर्विस आफ मेकेनिकल इंजीनियर्स (आइआरएसएमइ) कैडर के अधिकारी थे, इसलिए चर्चाएं थीं कि इसी वजह से मेकेनिकल इंजीनियर्स को अधिक दायित्व सौंपे जा रहे हैं।

लोहानी के रिटायर होने के बाद इंडियन रेलवे सर्विस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (आइआरएसइइ) के अधिकारी वीके यादव हैं। ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर यही माना जा रहा है कि कैडर बदलते ही बदलाव भी होते हैं।

यहां है ईएमयू/एमईएमयू कार शेड

रेलवे में ईएमयू और एमईएमयू कार शेड की बात करें तो गाजियाबाद, सहारनपुर, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, बड़ोदा आदि में है। यहां पर भले ही अभी इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारी कामकाज संभाल रहे हैं लेकिन इनकी रिपोर्टिंग अब मेकेनिकल विभाग को कर दी गई है।

छह दिन पहले शक्तियों में किया गया बदलाव

रेलवे बोर्ड ने 18 जुलाई 2019 को मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल विभाग की जिम्मेदारियों को लेकर आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में सन 2016 में जारी किए गए आदेशों का भी हवाला दिया गया।

कर्नाटक भाजपा को सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में 14 महीने पुरानी एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के एक दिन बाद बुधवार को प्रदेश भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। पार्टी इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है।

कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग माने जा रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, 'मैं दिल्ली से निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं। मैं किसी भी वक्त पार्टी विधायक दल की बैठक बुला सकता हूं और (सरकार बनाने का दावा पेश करने) राजभवन जा सकता हूं। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं।' लेकिन बताते हैं कि दिल्ली में इस संबंध में भाजपा संसदीय बोर्ड की बुधवार को कोई बैठक नहीं हुई। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, 'पार्टी नेतृत्व ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। सिर्फ मीडिया में ही कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व संभवतः बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।'

वहीं, स्पीकर रमेश कुमार ने बताया कि अयोग्यता याचिका पर कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा, 'वकील आए थे और अपने मुवक्किलों की ओर से उन्हें जो कहना था, उन्होंने कहा। मैंने उनकी बात सुनी। मैं सब देखूंगा और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा।' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने विधायकों को पेश होने के लिए और समय दिया है? उन्होंने कहा, 'सब कुछ हो चुका है। वे भी संतुष्ट हैं और मैं भी संतुष्ट हूं। आगे अब सिर्फ कार्रवाई होगी।'

बेंगलुरु में बुधवार को कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा अपने आवास पर जुटे समर्थकों की बधाईयां स्वीकार करते नजर आए। एएनआइ

गुहार

सीएम के नाम 13 साल की बेटी का लिखा पत्र वायरल, पत्र चर्चा में आया तो बैक डेट में वेतन भुगतान की हुई संस्तुति, पिता को एक साल से वेतन नहीं मिलने से पढ़ाई छूटने का था डर

योगी दादा, पापा की तनख्वाह दिला दें

जागरण संवाददाता, फर्रु खाबाद

पिता को एक वर्ष से वेतन नहीं मिलने से पढ़ाई छूटने के हालात बने तो बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मार्मिक पाती लिखकर गुहार लगाई। लगभग एक वर्ष पूर्व लिखी यह चिट्ठी फाइलों के ढेर में कहां गुम हो गई, किसी को नहीं पता, हां.. सोशल मीडिया पर इस पत्र के वायरल होने के बाद बुधवार को बेटी के पिता के पास अधिकारियों के फोन आने शुरू हो गए। वेतन भुगतान के लिए बैक-डेट में संस्तुति भी जारी हो गई।

कानपुर दुग्ध संघ में विलीन किए जा चुके फर्रुखाबाद दुग्ध संघ में श्रमिक अजय कटियार की बेटी आस्था ने बताया कि उसके एक बहन व दो भाई हैं। पापा पराग डेयरी में श्रमिक हैं। करीब एक वर्ष से पापा को वेतन नहीं मिल रहा है जिससे मेरी व बहन की फीस नहीं जमा हो पा रही है। हमारी पढ़ाई छूटने वाली है। मैंने आठवीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है। छोटी बहन सिद्धि ने चौथी क्लास पास की है। हम दोनों आगे पढ़ना चाहते हैं। पत्र में लिखा है कि 'योगी दादा और मोदी बाबा लड़कियों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। बहुत उम्मीद के साथ आपको पत्र लिख रही हूं ताकि आपके आशीर्वाद से हम दोनों बहन की पढ़ाई पूरी हो सके।' यह पत्र करीब एक वर्ष पूर्व भेजा गया था। कोई सुनवाई नहीं होने पर आस्था के मामा ने यह पत्र कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर डाल दिया। आस्था के पिता अजय कटियार ने बताया कि दुग्ध संघ के प्रभारी महाप्रबंधक संजय सिंह का बुधवार फोन आया था। बता रहे थे कि भुगतान के लिए संस्तुति तीन जुलाई को भेजी जा चुकी है। हालांकि उन्हें अभी तक कोई भुगतान नहीं मिला है।

> मामले की जांच कराई जाएगी। श्रमिकों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। बेटियों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।
> – विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी।

पिता का वेतन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी को आग्रह पत्र लिखने वाली आस्था। साथ में उसके भाई-बहन भी हैं। जागरण

छग के पूर्व गृह मंत्री और पांच आइएएस अफसरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए चिटफंड कंपनियों के करोड़ों के घोटाले में रायपुर के न्यू राजेंद्रनगर थाने में सनसाइन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड और साईं प्रसाद के खिलाफ अलग-अलग धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। एफआइआर में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, पांच आइएएस और एक आइपीएस के नाम भी अफसर के भी नाम हैं। यह कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश पर की गई है।

पुलिस के मुताबिक महासमुंद जिले के खल्लारी में प्रकरण दर्ज करने के बाद केस डायरी रायपुर के न्यू राजेंद्रनगर पुलिस थाना को भेजी गई। इसमें पुलिस ने सनसाइन इंफ्राबिल्ड के डायरेक्टर बनवारी लाल बघेल, वकील सिंह बघेल, संजीव सिंह, सुरेंदर सिंह बघेल, धरम सिंह कुशवाहा, राजीव गिरी व अन्य के साथ ही पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, आइएएस अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले, सिद्धार्थ कोमल परसेदी, अमृतलाल ध्रुवे, भीम सिंह और नीलकंठ टेकाम के खिलाफ केस दर्ज किया है।

आयकर विभाग ने बिश्नोई का बगीचा तक खोद डाला

जागरण संवाददाता, हिसार

▶ कांग्रेस नेता के खिलाफ हिसार में दूसरे दिन भी आयकर सर्वे

पुलिस ने किया सड़क मार्ग बंद

दो दिन से चल रही छापेमारी और कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए परेशानी न हो इसलिए आवास के सामने की सड़क को बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सड़क के दोनों तरफ बैरीकेड्स लगा दिए हैं।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के यहां सेक्टर-15 स्थित आवास पर 36 घंटे बाद भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर टीम ने दूसरे दिन बगीचे को खंगाला। पेड़ों की जड़ों तक खोदाई की गई। गमलों को भी खाली किया गया। कार्रवाई के दौरान घर के अंदर कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई और मां पूर्व विधायक जसमा देवी भी मौजूद थीं।

आयकर विभाग की टीम ने सिरसा रोड स्थित एक कार एजेंसी पर दोपहर को कार्रवाई बंद कर दी। उसके बाद से टीम भजनलाल के आवास पर बैठी है। बुधवार सुबह करीब दस बजे टीम के सदस्यों द्वारा एक बैग अंदर ले जाने को लेकर विवाद हो गया। कार्यकर्ताओं ने उस कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया और पहले बैग की जांच कराने की मांग की। पुलिस ने विरोध को देखते हुए जांच के बाद कर्मचारी को अंदर जाने दिया। बैग में कुछ कागजात और एक लैपटॉप था। पुलिस ने छापे के कारण भजनलाल आवास के सामने की सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आयकर अधिकारियों ने कुलदीप की आदमपुर दुकान पर वर्षों से काम कर रहे मुनीम को हिसार आवास पर बुला लिया है। उससे दोबारा से पूछताछ की जा रही है।

86 फीसद की कमी आई है जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2009 और 30 जून 2019 के बीच आतंकी घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 25 जुलाई 2019

सरकार ने एनसीसी कैडेट के लिए बढ़ाए पुरस्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों को विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों और उनकी राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब कैडेटों को पहले की तुलना में 100 पुरस्कार अधिक दिए जाएंगे। पहले कुल पुरस्कारों की संख्या 143 थी, जिसे बढ़ाकर 243 कर दिया गया है। कैडेटों को ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। सरकार एनसीसी में लड़के और लड़कियों की संख्या को बढ़ाकर 15 लाख से अधिक करने पर भी जोर दे रही है। आंकड़े बताते हैं कि एनसीसी में शामिल होने के लिए लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा इच्छुक हैं। इसे देखते हुए देश भर में एनसीसी में लड़के और लड़कियों की संख्या को पांच चरण वाले कार्यक्रम के तहत बढ़ाया जा रहा है।

नौ नए सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कारों भी मिली हरी झंडी : रक्षा मंत्री ने विभिन्न वर्गों में एनसीसी कैडेट के लिए नौ नए सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कारों को भी हरी झंडी दी है। इसके बाद ऐसे पुरस्कारों की संख्या 27 हो गई है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए नकदी प्रोत्साहन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने एनसीसी की नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि कैडेट पहले के 20,000 रुपये के मूल्य के एक पदक की जगह अब 30,000 रुपये के नकद प्रोत्साहन वाले दो रक्षा मंत्री पदक, 15,000 रुपये मूल्य (प्रत्येक) के तीन प्रशस्ति पुरस्कार की जगह 20,000 रुपये मूल्य के (प्रत्येक) चार रक्षा मंत्री प्रशस्ति पुरस्कार पाने के हकदार हैं। राजनाथ सिंह ने डीजी प्रशस्ति पुरस्कारों में भी उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 102 से बढ़ाकर 200 करने को मंजूरी दी है।

चर्च की जमीन कब्जाने को सैकड़ों लोगों ने बोला धावा

संघर्ष ▶ पंजाब के मोगा में पुलिस की सतर्कता से नाकाम हुई साजिश

110 साल पुराने चर्च की जमीन धोखे से बेचने पर हुआ विवाद, 207 पर केस

जागरण संवाददाता, मोगा

मोगा में मंगलवार रात को चर्च की जगह पर कब्जा लेने पहुंचे लोग अपनी जिन स्कूटी व मोटरसाइकिल को छोड़कर भागे थे, उन्हें मौके पर लोगों ने तोड़ दिया। जागरण

पंजाब के मोगा में भी उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जैसी घटना होते-होते बची। 110 साल पुराने चर्च की सौ करोड़ की जमीन पर कब्जे के इरादे से मंगलवार देर रात हथियारों से लैस करीब 250 लोग पहुंच गए। हमलावर रातों-रात दीवार खड़ी कर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए ईंटों से भरी पांच ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी साथ लाए थे, लेकिन समुदाय विशेष के 40 लोगों के साथ पुलिस के पहुंचने के कारण हमलावर वाहन व अन्य सामान वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सात लोगों को नामजद करते हुए 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है।

मंगलवार दिन में ही जिला उपायुक्त संदीप हंस ने धोखाधड़ी कर इस जमीन को बेचने के मामले की जांच के आदेश दिए थे। चर्च से संबंधित मिशन स्कूल के प्रिंसिपल और चर्च प्रॉपर्टी के नियंत्रक एलीशन ने बताया कि मंगलवार रात लगभग साढ़े दस बजे सेंट थॉमस स्कूल वाली जगह पर कुछ लोगों के घुसने पर उन्होंने चर्च का घंटा बजा दिया। आवाज सुनते ही ईसाई समाज के करीब 40 लोग वहां पहुंच गए। वहां गश्त कर रहे थाना सिटी-1 के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने हथियारबंद लोगों को देखा और कंट्रोल रूम को सूचना दी। डीएसपी सिटी परमजीत सिंह, डीएसपी (एच) बरिंदर सिंह चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक हमलावर सेंट थॉमस स्कूल का एक गेट ध्वस्त कर चुके थे। उनको देखते ही हमलावर सामान और वाहन छोड़कर भाग गए। लोगों ने एक ट्रैक्टर को भी आग लगा दी। डीएसपी सिटी ने आग बुझा कर लोगों को शांत किया।

यह है विवाद : यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट की मोगा की प्रॉपर्टी की देखरख कर रहे एलीशन ने शिकायत की थी कि उनके ट्रस्ट के नाम से मिलती-जुलती सोसायटी बनाकर लुधियाना निवासी बंसीलाल ने चर्च की जमीन धोखे से बेच दी है। धोखाधड़ी में तहसील कार्यालय के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने पुरानी तारीखों में इंतकाल कर दिया। सौ करोड़ की जमीन को मात्र 2.50 करोड़ में ही बेच दिया गया।

पांच लाख का इनामी लश्कर आतंकी दबोचा

राज्य ब्यूरो, जम्मू: सुरक्षाबलों ने बुधवार को ठाठरी (डोडा) के निकट फागसू जंगल में तलाशी अभियान चलाकर पांच लाख के इनामी लश्कर आतंकी जमालदीन गुज्जर उर्फ अबु बकर को गिरफ्तार कर लिया। वह सितंबर 2017 को आतंकी बना था और किश्तवाड़ में सक्रिय सात अति वांछित आतंकियों में एक था। हालांकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि जमालदीन घायल व बीमारी की हालत में जंगल में छिपा बैठा था। मौत सामने देख उसने समर्पण कर किया। पुलिस निगरानी में इलाज जारी है।

जमालदीन किश्तवाड़ जिले के पठना केशवान का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी को किश्तवाड़, डोडा और रामबन में आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी जमालदीन नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या व उसके बाद इसी साल अप्रैल माह में आरएसएस नेता चंद्र प्रकाश व उनके अंगरक्षक की हत्या में भी कथित तौर पर शामिल रहा है। गत माह 22 जून को किश्तवाड़ के सरवां जंगल में जमालदीन अपने साथियों संग सुरक्षाबलों की घेराबंदी में फंस गया था, लेकिन मुठभेड़ में जख्मी होने के बावजूद वह बच निकला था। उसके बाद वह डोडा की तरफ चला गया और ठाठरी के निकट एक जंगल में छिपकर अपना इलाज कराने लगा, लेकिन आवश्यक दवाओं और उचित चिकित्सा के अभाव में उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मौत को सामने देख उसने किसी तरह सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया।सूत्रों ने बताया कि जमालदीन का बड़ा भाई हबीब गुज्जर भी लश्कर का नामी कमांडर था, जो 4 अक्तूबर 2011 में नागनीगढ़ में हुई मुठभेड़ में मारा गया था।

प्रधान दूसरों की भूमि पर कब्जा करने के लिए चलवाता था ट्रैक्टर

सोनभद्र में घोरावल क्षेत्र के उभ्भा गांव में ग्रामीणों से जानकारी लेती जांच टीम। जागरण

सोनभद्र हिंसा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

- शासन की तीन सदस्यीय टीम ने ग्रामीणों से ली घटना से पहले व बाद की जानकारी
- टीम ने उभ्भा के ग्रामीणों से मिलकर राजस्व रिकार्ड को खंगाला

उप्र के सोनभद्र स्थित उभ्भा नरसंहार की जड़ खोजने पहुंची शासन की तीन सदस्यीय टीम को प्राथमिक जांच में बड़ा सुराग हाथ लगा। पता चला कि प्रधान अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भूमि पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर चलवा रहा था।

प्राथमिक विद्यालय उभ्भा में पांच ग्रामीणों से हकीकत सुनने के बाद गांव के नक्शे व खतौनी से यह बात सामने आई। अभिलेख में जिस जमीन पर प्रधान कब्जा कर रहा था, वह उभ्भा के आदिवासियों के नाम दर्ज है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहीं अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा व विंध्याचल कमिश्नर एके सिंह का काफिला बुधवार दोपहर बाद उभ्भा गांव पहुंचा। प्राथमिक विद्यालय उभ्भा में ग्रामीणों से रूबरू टीम के सदस्यों ने जगरनाथ, बहादुर, पुष्पा, नगीना व प्रतिमा से एक-एक कर घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने खेती के बदले में लेवी लेने समेत तमाम अहम जानकारियां दीं। कहा कि ग्राम पंचायत में छह सौ बीघा विवादित भूमि है। जिसमें करीब सौ बीघा जमीन डूब, तालाब व नाले में चली गई है। पांच सौ बीघा खेती के लायक है। घटना से पहले भूमि को लेकर विवाद होता रहा लेकिन राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं आता था। जगरनाथ ने बताया कि प्रधान ने सोसाइटी की जमीन रजिस्ट्री कराई तब उन्हें जानकारी हुई। प्रधान यज्ञदत्त 2018 में बरसात में पहली बार भूमि पर कब्जा करने पहुंचा था लेकिन ग्रामीणों के विरोध व पुलिस के आने के कारण वह पीछे हट गया था लेकिन उसकी निगाह भूमि पर गड़ी रही। 2015 में ग्राम पंचायत मूर्तिया का प्रधान बनने के बाद यज्ञदत्त का हौसला और बढ़ गया। जगरनाथ ने कहा कि सोसाइटी से रजिस्ट्री जमीन पर ट्रैक्टर चलवाता तो कुछ नहीं होता। प्राथमिक विद्यालय में नक्शा देखने के बाद जांच टीम घटनास्थल पर धमक पड़ी।

कब्जा पाने के लिए प्रधान ने जमा किए थे 1.42 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : उउभ्भा गांव में भूमि पर कब्जा पाने के लिए ग्राम प्रधान ने पुलिस विभाग में 1.42 लाख रुपये जमा किया था। इसकी रसीद कटवाकर कब्जा दिलाने की तिथि भी सुनिश्चित कराई थी लेकिन राजस्व विभाग ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अंततः प्रधान ने जमीन पर स्वयं कब्जा करने की कोशिश की और नरसंहार हुआ। प्रधान को कब्जा पाने की इतनी जल्दबाजी थी कि वह दाखिल खारिज होने से पहले ही कब्जा पाने के लिए परेशान था। ऐसे में एसडीएम के यहां प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण है उसे हटवाया जाए। इस पर एसडीएम ने 11 अक्टूबर 2018 को तहसीलदार घोरावल को कार्रवाई के लिए कहा। तहसीलदार ने एसएचओ घोरावल को पत्र लिखा तो एसएचओ ने फोर्स की एक दिन की सैलरी दिलाने के लिए कहा। इस पर प्रधान ने रुपये जमा कराए थे।

अब अमलीपोखर के एक मामले की बदल गई पत्रावली

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : सोनांचल में राजस्व मामलों में बड़ा खेल होता है। उभ्भा के पड़ोसी गांव अमलीपोखर के एक मामले की पत्रावली रिकार्ड रूम में रखे-रखे बदल दी गई। जानकारी होने पर पट्टाधारक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पट्टाधारक रवि सिंह के मुताबिक उन्हें और उनके बड़े भाई रघुनंदन सिंह को अमलीपोखर गांव में सात बीघा दस बिस्वा भूमि पट्टा हुई थी। वह जमीन पर काबिज थे। इसी दौरान कुछ विपक्षियों ने अपर कलेक्टर से उनका पट्टा निरस्त कर दिया। जबकि पूर्व में 30 जुलाई 2001 के आदेश में अपर कलेक्टर ने विपक्षियों के प्रार्थना पत्र निरस्त कर पट्टे को वैध माना था। पीड़ित ने जब पड़तालकी तो रिकार्ड रूम में आदेश वाले पन्ने बदले रखे मिले।

28 राज्यों के 20 लाख लोगों से की 14 हजार करोड़ की ठगी

जागरण संवाददाता, जयपुर

- आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल

देश के चर्चित आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। जयपुर महानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में एसओजी ने माना है कि सोसायटी के पदाधिकारियों ने देश के 28 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के निवेशकों को धोखा देकर करीब 14 हजार 800 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। करीब 20 लाख लोगों को ठगा गया।

करीब 26 हजार पेज की चार्जशीट में एसओजी ने माना कि सोसायटी की देशभर में 806 शाखाएं खोलकर एजेंटों के माध्यम से निवेशकों से पहले तो पैसा जमा किया गया और फिर अपने रिश्तेदारों के नाम से 187 फर्जी कंपनियां बनाकर रकम आपस में लोन देने के बहाने बांट ली। इन कंपनियों में गुरुग्राम की एक फर्म के नाम पते पर ही 125 कंपनियां बना ली गईं। सोसायटी ने मूल रकम के ब्याज की राशि को भी खाता धारकों में बांटने के बजाय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़प ली। सोसायटी में घोटाले करने वाले राजस्थान के सिरोही निवासी वीरेंद्र मोदी और मुकेश मोदी ने प्रदेश में 309 शाखाएं खोलकर 20 लाख सदस्य बनाए। वीरेंद्र मोदी सिरोही नगर पालिका का पूर्व में चेयरमैन भी रह चुका है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान एसओजी को सोसायटी के फर्जीवाड़े की शिकायत पिछले साल अगस्त माह में मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि सोसायटी के संस्थापक मुकेश मोदी के परिवार ने लाखों निवेशकों से पैसा जमा करवाने के बाद उन्हें वापस नहीं किया। निवेशकों को ना तो ब्याज दिया गया और ना ही मांगने पर लोन। एसओजी ने जांच की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। सामने आया कि सोसायटी के मोदी परिवार ने अपने परिजनों एवं मित्रों के नाम पर 187 लोन खातों में 20 लाख निवेशकों से प्राप्त राशि का 99 प्रतिशत निवेश शैल कंपनी को अवैध तरीके से सदस्य बनाकर किया।

झारखंड में नक्सलियों ने दो को अगवा कर की हत्या

15 घंटे बाद पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी सिंहभूम : झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले की नक्सल प्रभावित लोंजो पंचायत में नक्सलियों ने गोली मारकर दो की हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात आठ बजे की है। ग्रामीणों की सूचना पर वारदात के 15 घंटे बाद पुलिस बुधवार को घटनास्थल पर पहुंची। मृतक रिश्ते में जीजा-साला थे। पुलिस के अनुसार घटना को भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर जीवन कंडुलना दस्ते ने अंजाम दिया है।

मृतकों के परिजनों ने बताया कि माईलपीढ़ गांव में मंगलवार शाम सात बजे वर्दीधारी हथियारबंद करीब चार नक्सली पहले बागुन बोदरा के घर पहुंचे। उसे अगवा कर नक्सली प्रभावित गांव के मुंडा डांगो डांगिल के घर पहुंचे। यहां दोनों के साथ मारपीट की गई। घर में रखे टीवी व सामान तोड़ दिए गए। इसके बाद नक्सली दोनों को हाथ पीछे बांधकर साथ ले गए। घर से चार किमी दूर ले जाकर बुरुघाट में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में सटाकर गोली मारने से उसके परखच्चे उड़ गए थे।

जाकिर के भाषणों से प्रभावित हैं आइएस से जुड़े संगठन के सदस्य

- जनवरी में गिरफ्तार किए गए थे उम्मत-ए-मुहम्मदिया के 10 सदस्य
- महाप्रसाद में जहर मिलाकर श्रद्धालुओं को मारने की रची थी साजिश

मुंबई, प्रेट्र : इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े आतंकी संगठन उम्मत-ए-मुहम्मदिया के महाराष्ट्र में गिरफ्तार 10 सदस्य इस्लामी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हैं। इन सदस्यों को कथित रूप से एक मंदिर में एक साथ कई श्रद्धालुओं को मारने की साजिश रचने के आरोप में जनवरी में मुंब्रा और औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने मामले की विस्तृत जांच के बाद इस महीने की शुरुआत में मुंबई की अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। इसके मुताबिक, एटीएस को गिरफ्तार आरोपितों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकिर नाइक के कई वीडियो और तस्वीरें मिलीं। इससे पता चलता है कि वे जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हैं। आरोप-पत्र के मुताबिक, आरोपितों ने मुंब्रा स्थित 400 साल पुराने श्री मुंब्रेश्वर मंदिर के महाप्रसाद में जहर मिलाकर एक साथ कई श्रद्धालुओं को मारने की योजना बनाई थी। पिछले साल दिसंबर में मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था जहां हजारों श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। गिरफ्तार किए गए एक आरोपित तलहा पोट्रिक ने प्रसाद में जहर मिलाने की कोशिश की भी थी।

एक एटीएस अधिकारी ने बताया कि संगठन के सदस्यों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिये विस्फोटक और जहर बनाने की जानकारी हासिल की थी। साथ ही उन्होंने मुंब्रा बाईपास के नजदीक पहाड़ियों में विस्फोटकों का परीक्षण भी किया था। इन परीक्षणों को करने वाले समूह के सरगना की पहचान एटीएस ने अबु हमजा के रूप में की है। आरोप-पत्र के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपित मुंब्रा के एक स्टेडियम में आयोजित आतंकी गतिविधियों के एक शारीरिक प्रशिक्षण सत्र में भी शामिल हुए थे। साथ ही समूह के कुछ सदस्य विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में भी थे।

मुस्लिम कारीगरों के हाथ से बनी कांवड़, राखी न खरीदें : साध्वी प्राची

जासं, बागपत : उप्र के शामली स्थित कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने संबंधी बयान के बाद अब बुधवार को साध्वी प्राची ने विवादित दिया। उन्होंने मुस्लिम कारीगरों के हाथ की बनी राखी व कांवड़ न खरीदने की सलाह दी है। बुधवार को दाहा गांव में एक भंडारे के उद्घाटन में पहुंचीं साध्वी ने कहा कि कांवड़ मेला हरिद्वार में 99 प्रतिशत मुस्लिम कारीगर कांवड़ तैयार कर रहे हैं, जिनका बहिष्कार कर हिंदुओं को खुद कांवड़ तैयार करनी चाहिए। इससे हिंदुओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले रक्षाबंधन त्योहार पर मुस्लिम कारीगरों के हाथ की बनी राखियां भी न खरीदें।

मामले की जांच एएसपी अनिल सिंह को सौंपी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-शैलेश पांडेय, एसपी, बागपत

मिनी कुंभ की तरह माघ मेले में सुविधाएं देने के लिए तैयारियां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

मेले के आकर्षण

- कुंभ की तरह ही मेला में हर जगह रामचरित मानस और पौराणिक महत्व की चौपाइयों के बोर्ड लगाए जाएंगे।
- पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए स्विस कॉटेज, फूड कोर्ट, वॉटर स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर से माघ मेला दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है।
- मेला के चारों ओर पॉर्किंग की व्यवस्था होगी। नैनी, झूंसी, फाफामऊ, शहर की ओर बड़ी पॉर्किंग बनाई जाएगी, जहां आवश्यक सुविधाएं भी होंगी।

माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे भी मिनी कुंभ की तरह सेक्टर में बसाया जाएगा। फिलहाल नौ सेक्टर बसाने के लिए लेआउट तैयार किया जा रहा है। आवश्यकता के मुताबिक सेक्टर बढ़ाए जा सकते हैं। कुंभ में 20 सेक्टर बनाए गए थे। इसके अलावा विभिन्न विभागों से कार्ययोजना और बजट का प्रस्ताव मांगा गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य, जल निगम, पर्यटन, नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार कराने में जुट गया है। जल्द ही बजट शासन को भेजा जाएगा, जिसकी स्वीकृति के बाद कार्य तेज हो जाएगा।

दिव्य और भव्य कुंभ के बाद इस बार माघ मेला को भी अद्भुत बनाने की तैयारी है। इसके लिए अफसर तैनात किए जाने लगे हैं। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया को वरिष्ठ अधिकारी, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश कुमार मिश्र को मेला का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ एसएलओ अनिल चतुर्वेदी को भी लगाया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव दयानंद प्रसाद को सेनीटेशन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी की ओर से 11 पांटून पुल बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। कुंभ में 22 पांटून पुल बनाए गए थे। इसी तरह चकर्ड प्लेट की सड़कों का भी प्लान तैयार हो रहा है। बिजली विभाग की ओर से 22 हजार एलईडी लगाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। कुंभ की तरह ही इस बार भी सेक्टर कार्यालयों में ही सभी विभागों के दफ्तर खोले जाएंगे।

एचएएल ने तय समय से पहले सौंपा नौसेना को चेतक हेलीकॉप्टर

बेंगलुरु, एएनआइ : हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने नौसेना को तय समय से पहले ही एक चेतक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति कर दी है। एचएएल और नौसेना ने अगस्त 2017 में आठ चेतक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का अनुबंध किया था। कार्यक्रम के मुताबिक पहले दो हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति अगस्त, 2019 और बाकी छह हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति अगस्त, 2020 तक होनी है।

एचएएल की हेलीकॉप्टर डिवीजन के महाप्रबंधक एस. एंबुवेलन ने एक कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के दस्तावेज कोमोडोर विक्रम मेनन को सौंपे। इस मौके पर हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स के सीईओ जीवीएस भास्कर ने कहा, 'एचएएल ने चेतक हेलीकॉप्टरों का फिर से सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू कर दिया है जिन्हें अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है।

हम बाकी सात हेलीकॉप्टरों को भी आपूर्ति कार्यक्रम के मुताबिक नौसेना को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' एचएएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर. माधवन ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों में एचएएल द्वारा विकसित अत्याधुनिक संचार एवं नौपरिवहन प्रणाली लगाई गई है। कोमोडोर मेनन ने कहा कि तय समय से एक महीने पहले एक हेलीकॉप्टर को प्राप्त करना बेहद सम्मान का विषय है।

मालूम हो कि एचएएल पिछले पांच दशकों से फ्रांस की यूरोकॉप्टर (वर्तमान में एयरबस हेलीकॉप्टर्स) के लाइसेंस के तहत चेतक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन कर रही है। कंपनी ने नौसेना को पहले चेतक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति फरवरी, 1966 में की थी। एचएएल अब तक 350 से ज्यादा चेतक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन कर चुकी है और इनमें से करीब 80 की आपूर्ति भारतीय नौसेना को की गई है। वर्तमान में नौसेना के पास 51 चेतक हेलीकॉप्टर हैं। नौसेना इनका इस्तेमाल यात्री परिवहन, सामान ढोने, राहत एवं बचाव कार्यों, हवाई सर्वेक्षण, गश्त, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं आदि कार्यों में करती है।

वर्तमान में नौसेना के पास 51 चेतक हेलीकॉप्टर हैं। प्रतीकात्मक

- तय कार्यक्रम के मुताबिक अगले महीने तक की जानी थी आपूर्ति
- अगस्त 2017 में आठ चेतक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का अनुबंध किया था
- अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं हेलीकॉप्टर

युवती के पेट से निकले डेढ़ किलो गहने व 60 सिक्के

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवती के पेट से डेढ़ किलो गहने और 60 सिक्के निकाले गए हैं। ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने युवती के पेट से गहने व सिक्के निकाले हैं। इनमें नाक, कान, गला व पैरों के गहने शामिल हैं। पेट से निकाले गए गहने का वजन एक किलो 680 ग्राम है। वीरभूम के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने गहने निकाले। युवती का नाम रुनी खातून (22) है। वह वीरभूम की रहने वाली है। परिजनों का कहना है कि भूख लगने पर वह घर में रखे गहने निगल जाती थी।

एक सप्ताह पूर्व रुनी के पेट में तेज दर्द होने पर जांच के लिए उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए। रुनी की जांच के बाद पता चला कि उसके पेट में धातु के एक से अधिक टुकड़े हैं। डॉक्टर के अनुसार सिद्धार्थ विश्वास के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल हमने रुनी के पेट का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। डॉक्टर के नेतृत्व में पांच डॉक्टरों के दल ने युवती के पेट का ऑपरेशन करना शुरू किया।

एक घंटा 15 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद उसके पेट से सोने की चेन, अंगूठी, बाला, घड़ी, कान व नाक समेत धातु के अन्य गहने निकाले गए। वहीं युवती के पेट से एक दो नहीं, बल्कि 60 की संख्या में सिक्के भी डॉक्टरों को मिले। परिवार का कहना है कि युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घर में एक स्टेशनरी की दुकान है। युवती वहां जाकर सिक्के व अन्य धातु के सामान खा लेती थी।

ऋषिकेश के रामझूला पुल पर भी मंडरा रहा संकट

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश

- लोक निर्माण विभाग ने इसे अधिक आवाजाही के लिए खतरनाक माना
- लक्ष्मणझूला पुल को खतरनाक घोषित कर पहले ही किया जा चुका बंद
- तत्काल दुपहिया वाहनों, रेहड़ी-ठेली की आवाजाही प्रतिबंधित करने को कहा

तीर्थनगरी ऋषिकेश में ऐतिहासिक लक्ष्मणझूला पुल पर आवाजाही पूरी तरह बंद होने के बाद अब रामझूला पुल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोक निर्माण विभाग(लोनिवि) ने इस पुल को अधिक आवाजाही के लिए खतरनाक मानते हुए इस पर तत्काल दुपहिया वाहनों समेत रेहड़ी-ठेली की आवाजाही प्रतिबंधित करने को कहा है। इस संबंध में विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी है।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि 1985 में तैयार इस 220 मीटर लंबे पुल से रोजाना हजारों लोग और वाहन गुजरते हैं। प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान पुल पर दबाव और भी बढ़ जाता है। इससे पुल की स्थिति खतरनाक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार रामझूला पुल का निर्माण गंगा नदी को पार करने के लिए वैकल्पिक साधन के रूप में किया गया था, न कि दुपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए। इसे मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति भी कभी नहीं दी गई।

विदित हो कि 2013 में नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस पुल पर दुपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि करीब 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की क्षमता वाला यह पुल वर्तमान में सिर्फ 350 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर का भार ही झेलने की स्थिति में है। बावजूद इसके पुल को न केवल मुख्य मार्ग की तरह ही उपयोग में लाया जा रहा है, बल्कि इस पर धड़ल्ले से दुपहिया वाहनों की आवाजाही भी हो रही है।

ऋषिकेश के रामझूला पुल पर वाहनों व पैदल यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने के बाद इस पुल से दोपहिया वाहन व यात्री गुजर रहे हैं। ऐसे में इस पुल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जागरण

टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर व बड़गाम में एनआइए के छापे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- छात्र को पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग मामले में बुधवार को लगातार दूसरे दिन श्रीनगर और बड़गाम में छापे मारे। इस दौरान एक छात्र को पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले किया गया है।

एनआइए ने गत मंगलवार को पुलवामा और श्रीनगर में क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े व्यापारियों के छह ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरम लैपटॉप, बैंक पासबुक और क्रास-एलओसी ट्रेड में लेन-देन के कुछ बही-खाते भी जब्त किए थे। बुधवार सुबह एनआइए ने कुरसु राजबाग में मोहम्मद शफी डार नामक एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। यह छापा डार के मकान में किराए पर रह रहे बख्तियार मुजीब मल्ला नामक एक छात्र के लिए था। अरीगाम त्राल का रहने वाला बख्तियार इन दिनों श्रीनगर में नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की कोचिंग ले रहा है। बताया जाता है कि वह त्राल के एक पुराने हिज्ब कमांडर का करीबी रिश्तेदार है और दो साल पहले बाघा बार्डर पर पकड़ा गया था। बाद में उसके नाबालिग होने का संज्ञान लेते हुए उसे रिहा किया गया था। बख्तियार के कमरे से एनआइए ने कुछ दस्तावेज, पेन ड्राइव और लैपटाप को जब्त किया है। उसे हिरासत में लेकर राजबाग पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोपहर बाद एनआइए ने श्रीनगर के साथ सटे बड़गाम जिले के अरिपंथन में एक व्यापारी मोहम्मद अफजल मीर के घर पर छापा मारा। एनआइए मीर के मकान में दोपहर दो बजे पहुंची और करीब तीन घंटे तक वहां रही। एनआइए ने उसके घर से कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। मीर के परिजनों से भी पूछताछ की है। मीर भी कथित तौर पर क्रास एलओसी व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है। बड़गाम के एसएसपी अमोद नागपुरे ने कहा कि अफजल मीर के घर से क्या जब्त किया गया है, यह एनआइए की टीम ही बता सकती है।

जनमत
मुद्दा

क्या राष्ट्रीय की जगह राज्यवार आबादी के आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का समय आ चुका है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran
mudda@jagran.com

23 हजार से ज्यादा पशु जब्त हुए हैं बंगाल में इस वर्ष 30 जून तक सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल द्वारा। मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री संजीव कुमार बाल्यान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

लगातार बारिश से बिहार में भयावह हुई बाढ़

आफत ▶ जलस्तर में वृद्धि से नदियां हो रहीं विकराल, उत्तर बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, 13 की जान गई

नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है

जागरण टीम, पटना

बिहार के दरभंगा में बुधवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ितों के लिए वायु सेना ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई। एएनआइ

असम के नलबाड़ी में बुधवार को बाढ़ग्रस्त इलाके में पीड़ितों की मदद में जुटे सेना के जवान। प्रेट्र

नेपाल, उत्तर बिहार और कोसी-सीमांचल क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को और भयावह कर दिया है। जलस्तर में वृद्धि से नदियां विकराल होने लगी हैं। उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में बाढ़ से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। कोसी-सीमांचल की नदियों के जलस्तर में भी उतार-चढ़ाव जारी है। नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण नदियों के पास बसे ग्रामीण भयभीत हैं। बाढ़ व जलजनित हादसों में विभिन्न जिलों में 13 की मौत हो गई।

नेपाल और बिहार सरकार की चेतावनी : पश्चिम चंपारण में गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी रही। बिहार जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी है। प्रशासन ने दियारा के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। मधुबनी जिले में कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान है। सीतामढ़ी शहर के कई मोहल्ले बाढ़ के पानी की गिरफ्त में हैं। 27 जुलाई तक सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। सीतामढ़ी का पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर तथा नेपाल से लगातार 15वें दिन भी सड़क संपर्क कटा रहा। दरभंगा के कई नए इलाकों में पानी फैल गया है।

महानंदा फिर उफनाई : वहीं किशनगंज में बारिश के कारण एक बार फिर बाढ़ के हालात हो गए हैं। महानंदा का जलस्तर खतरे के निशान 60 सेमी ऊपर होने के कारण पोठिया, कोचाधामन व किशनगंज प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। खगड़िया में बारिश होने से बूढ़ी गंडक, कोसी व बागमती नदियों के जलस्तर में फिर वृद्धि होने लगी है।

पटना में 20 मिमी. बारिश, छह डिग्री लुढ़का तापमान: पटना और आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान 20 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। गया, भागलपुर और पूर्णिया के आसपास इलाकों में बुधवार को बारिश हुई। बारिश के कारण पटना सहित पूरे प्रदेश के तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश होगी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर हिमालय क्षेत्र में सक्रिय रहने का असर रहेगा। 28 जुलाई तक मानसूनी बादल छाए रहेंगे। तापमान सामान्य में चार डिग्री तक की कमी आने की संभावना है।

झारखंड में वज्रपात से 23 की मौत

जेएनएन, रांची : बूंद-बूंद पानी को तरसते झारखंड में बुधवार को खूब बारिश हुई। सूखे खेतों के लिए वरदान बन आई बरसात ने किसानों को राहत पहुंचाई है। लेकिन, राहत के बीच आसमान से गिरी बिजली लोगों पर आफत बन टूटी। पूरे राज्य में वज्रपात ने कहर बरपाया और 23 लोगों की जान ले ली। जामताड़ा में छह की, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, रामगढ़, गढ़वा, रांची में दो-दो और देवघर, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा में एक-एक मौत हुई।

ईडी ने तलब किया जौहर विश्वविद्यालय का विवरण

जागरण संवाददाता, रामपुर

▶ सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने डीएम से मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में विवरण मांगा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र मिल गया है। किसानों की जमीन कब्जाने के आरोपों में घिरे सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी में अरबों रुपयों की लागत से आलीशान इमारतें बनी हैं। श्रम विभाग दो हजार करोड़ की इमारतें बनाने का नोटिस चार साल पहले दे चुका है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि जौहर विवि में जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनके बारे में श्रम विभाग लेबर सेस जमा कराने के लिए कह चुका है, लेकिन उन्होंने सेस की रकम जमा नहीं की। इसके अलावा अन्य स्रोतों से भी यूनिवर्सिटी में लगे धन की जानकारी की जाएगी। उधर, अब ईडी भी आजम खां से हिसाब मांग सकती है कि पैसा कहां से आया। हालांकि आजम कहते रहे हैं कि उन्होंने चंदा करके यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया है लेकिन, ईडी उनसे यह भी जानना चाहेगा कि इतनी मोटी रकम चंदे में किस-किस ने दी है। इससे आजम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

आजम पर अब तक दर्ज हो चुके हैं 68 मुकदमे

जासं, रामपुर : रामपुर शहर से नौ बार विधायक रहे आजम के खिलाफ इस समय 54 मुकदमे विचाराधीन हैं, जबकि 14 मुकदमे राजस्व परिषद में दायर हुए हैं।

आजम के खिलाफ 26 मुकदमे तो एक सप्ताह के दौरान दर्ज हुए हैं। ये मुकदमे 12 से 20 जुलाई के बीच अजीमनगर थाने में दर्ज किए गए हैं। इनमें पहला मुकदमा 12 जुलाई को जिला प्रशासन की ओर से 26 किसानों की जमीन कब्जाकर मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में दर्ज कराया गया। इसके बाद 25 किसानों ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए। इससे पहले एक जून को भी जिला प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कोसी नदी क्षेत्र की पांच हेक्टयर जमीन कब्जाकर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है। इस तरह जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर 27 मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज कराए गए हैं।

एसआइटी ने भी बढ़ाए कदम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां पर जांच एजेंसियों का चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। भूमि पर कब्जो के मुकदमों के बीच आजम की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। जलनिगम भर्ती घोटाला व जौहर विश्वविद्यालय में हुई धांधली की जांचों में एसआइटी ने भी कदम बढ़ाये हैं। एसआइटी ने एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) हैदराबाद को पत्र लिखकर जलनिगम भर्ती के रिजल्ट से जुड़ी हार्ड डिस्क की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। इसी माह एसआइटी हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है।

दरअसल, एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ही एसआइटी की जांच के कई बिंदु तय होंगे। सूत्रों का कहना है कि जांच में तत्कालीन मंत्री आजम खां व उनके ओएसडी सैय्यद आफाक अहमद की भूमिका सामने आई है। सैय्यद आफाक के भर्ती से जुड़े कई विभागीय दस्तावेजों में दस्तखत भी मिले हैं। जौहर विश्वविद्यालय में धांधली के मामले में भी एसआइटी कई कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है।

उल्लेखनीय है कि जलनिगम भर्ती घोटाले के मामले में एसआइटी ने जांच पूरी कर एफआइआर दर्ज कराने की संस्तुति की थी। एसआइटी ने शासन के आदेश पर 25 अप्रैल 2018 को सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसआइटी अब तक की गई विवेचना में 50 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली संस्था अपटेक के अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। एफआइआर में जलनिगम के तत्कालीन एमडी पीके आसूदानी, नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव एसपी सिंह, पूर्व मंत्री आजम के तत्कालीन ओएसडी सैय्यद आफाक अहमद व तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल कुमार नामजद आरोपित हैं।

रास्ता बंद करने के आरोप में आजम का भांजा गिरफ्तार

जासं, रामपुर : सांसद आजम खां के भांजे समेत तीन सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांसद के पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बुधवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। सांसद के पड़ोस में रहने वाले मुहल्ला घेर मीरबाज खां निवासी आसिफ रजा खां ने कुछ दिन पहले गंज कोतवाली में मुहल्ले में ही रहने वाले सांसद के भांजे फरहान खां, सलमान और मुहल्ला घेर बक्शी खां निवासी बिट्टू खां को नामजद किया था। आरोप था कि तीनों ने उनके घर के सामने रास्ता बंद कर दिया।

क्या 20 साल बाद आरटीआइ के तहत दी जा सकती है निजी जानकारी!

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्या 20 वर्षों के बाद सरकारी अधिकारियों की निजी जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रदान की जा सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इस संबंध में 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले के एक दोषी की याचिका का संज्ञान लेते हुए पूर्ण पीठ के गठन का निर्णय लिया है। प्रथम श्रेणी डिब्बों में हुए इन विस्फोटों में 188 लोग मारे गए थे जबकि 829 लोग घायल हुए थे।

दरअसल, इस मामले में मौत की सजा पाए एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत 12 आइपीएस अफसरों के यूपीएससी फार्म और दूसरे अन्य रिकॉर्ड मांगे थे। लेकिन गृह मंत्रालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद अब उसने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

सिद्दीकी का दावा है कि इन धमाकों में उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। उसने अधिकारियों के संबंध में जो रिकॉर्ड मांगे हैं वह आरटीआइ आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 साल से अधिक पुराने हैं। उसने इस संबंध में आरटीआइ अधिनियम की धारा 8 (3) का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि

▶ मौत की सजा पाए आतंकी के अनुरोध पर सीआइसी ने किया पूर्ण पीठ का गठन

12 आइपीएस के रिकॉर्ड मांगे थे। प्रतीकात्मक

सूचना मांगे जाने से 20 साल पहले अगर कोई घटना हुई है तो धारा-6 के तहत इस संबंध में मांगी गई जानकारी प्रदान की जा सकती है। हालांकि रणनीति महत्व, राष्ट्रीय हित, संसद और विधानसभाओं से जुड़ी जानकारियों को इससे अलग रखा गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना है, इसलिए इस अधिकार को किसी भी कानून द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।

मृतक आश्रितों को नौकरी के बजाय पैकेज दे सरकार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ सेवानिवृत्ति तक या तीन से पांच साल तक मिल रहे वेतन के बराबर भुगतान का कानून बनाए उत्तर प्रदेश सरकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में ऐतिहासिक पहल की है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को संबंधित विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने के बजाय एक पैकेज दे। इसके तहत मृत कर्मी की सेवानिवृत्ति तक या तीन से पांच साल तक उसे मिल रहे वेतन के बराबर आश्रित को भुगतान दिया जाए। इससे परिवार को अचानक आई विपत्ति से उबरने में मदद मिलेगी, वहीं आश्रित खुली प्रतियोगिता में चयनित होने लायक बन सकेगा और सरकारी विभाग को भी योग्य अभ्यर्थी आसानी से मिल जाएंगे।

कोर्ट ने सुझाव में कहा कि सरकार मृत कर्मचारी के परिवार को पैकेज का भुगतान करने के बारे में कानून बनाए। यह कदम सरकारी सेवाओं में समान अवसर और सामाजिक न्याय में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मृतक आश्रितों की भारी संख्या और पदों की कमी के मद्देनजर सरकार ऐसा तरीका अपनाए जिससे खुली प्रतियोगिता में योग्य की नियुक्त हो सके और आश्रितों को भी सामाजिक न्याय मिल सके। ऐसा करने से खुली प्रतियोगिता से नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे और आश्रित को भी मदद मिल सकेगी। यह सुझाव न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने अंकुर गौतम व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

अहम सुझाव

- सरकारी सेवा में समान अवसर और सामाजिक न्याय में सामंजस्य की पहल
- इस कदम से मृतक आश्रित परिवार को मदद मिलेगी
- आश्रित विभाग की खुली भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए तैयार होगा
- विभिन्न महकमों में योग्य लोग चयनित हो सकेंगे

यह है मामला : पुलिस विभाग में नियम 5 (1) के तहत सीधी भर्ती की पांच फीसद रिक्तियों पर ही आश्रित की नियुक्ति की अनुमति है। अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी का कहना था कि यह नियम ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से आश्रित नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। इसलिए, यह नियम रद किया जाए, क्योंकि सीधी भर्ती के पांच फीसद रिक्तियों पर आश्रितों की संख्या ज्यादा होने पर टेस्ट से मेरिट पर उनका चयन किया जाएगा। वहीं, कोर्ट ने सीधी भर्ती में पांच फीसद पदों पर आश्रितों की नियुक्ति के नियम को वैध ठहराया है। कहा कि ऐसा न करने से आश्रितों की संख्या अधिक होने से सीधी भर्ती के अवसर कम होंगे। पुलिस विभाग में रिक्त पदों का 50 फीसद सीधी भर्ती व 50 फीसद पदोन्नति से भरने का नियम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर कानून सही होता है, अब जो इसे चुनौती देगा उसे सिद्ध करना होगा कि किस प्रकार यह संविधान के उपबंधों के विपरीत है।

...तो सारे पदों पर आश्रित दिखेंगे : कोर्ट ने कहा कि आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण यदि सभी की नियुक्ति कर दी गई तो खुली भर्ती के अवसर नहीं रह जाएंगे।

बरेली में गोकशी पर भड़के हिंदू संगठन हाईवे किया जाम

जागरण संवाददाता, बरेली : उप्र के बरेली स्थित फतेहगंज पूर्वी कस्बे में मंगलवार रात गोतस्करों ने आधा दर्जन से अधिक गोवंशीय पशु काट डाले। बुधवार सुबह पशु के अवशेष देखकर भड़के ग्रामीणों ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। सीओ और एसडीएम कई थानों के पुलिसकर्मियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। हाईवे करीब एक घंटे जाम रहा।

कस्बे में राजमार्ग के किनारे रक्षा संपदा विभाग की खाली जमीन पर बीती रात गो-तस्करों ने आधा दर्जन से अधिक गोवंशीय पशुओं का कटान किया। तस्कर मांस ले गए और अवशेष वहीं छोड़ गए। सुबह ग्रामीण पशुओं के अवशेष देखकर भड़क उठे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में घटनास्थल के पास ही यूपी-100 पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पुलिस पर साठगांठ के आरोप लगाकर हाईवे जाम कर दिया। एसडीएम व सीओ जगमोहन बुटोला फोर्स के साथ पहुंचे। अवशेषों को जेसीबी से दफना दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के विनोद राठौर की ओर से कसवान मोहल्ला निवासी जाहिद, सलीम, शानू व तस्लीम समेत पांच के खिलाफ तहरीर दी गई है।

वेबसाइट से लोकेशन गायब कर टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर

▶ लोक निर्माण विभाग द्वारा ई-टेंडरिंग में किया जा रहा घालमेल

▶ टेंडर जारी करते समय जिले का नाम ही कर दिया जा रहा गायब

लोक निर्माण विभाग के ठेकों में मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक तो जान पहचान के लोगों को बिना विज्ञापन टेंडर देने, संबंधित टेंडर का आंकलन कम या ज्यादा करके लाभ दिलाने का ही काम हो रहा था। अब सरकार की पारदर्शी व्यवस्था को ध्वस्त कर नया कारनामा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के टेंडर में जनपद का नाम गायब कर दिया जाता है। इससे लोकेशन द्वारा टेंडर सर्च करने पर जिले का टेंडर नहीं दिखता।

सरकारी ठेकों में पारदर्शिता के लिए शुरू की गई शासन की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में सेंध लग चुकी है। अभियंता भले कोई नई तकनीकी इजाद न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने टेंडर में खेल करने की तकनीकी पर महारत हासिल कर ली है। दरअसल, निविदादाताओं की आसानी के लिए उत्तर प्रदेश एनआइसी की साइट पर विभिन्न जनपदों व विभागों के टेंडर ढूंढ़ने के लिए सर्च बाई लोकेशन विकल्प है। इसी कालम का तोड़ निकालकर पीडब्ल्यूडी विभाग टेंडर में बड़ा खेल कर रहा है।

> लोकेशन छूटने की जांच होगी
> इस तरह की शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेंडर में लोकेशन का कालम भूलवश छूट गया हो लेकिन इसकी जांच कराई जाएगी।
> **-रमेश राम, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी**

इसमें निविदा का विवरण अपलोड करते समय लोकेशन के कालम में जनपद का नाम ही नहीं डाला जाता है। इससे संबंधित काम किसी जनपद की सर्च लोकेशन में आता ही नहीं है। इन कार्यों की 'लोकेशन' गायब कर दी जाती है और अपने जानने वालों को टेंडर जारी कर दिया जाता है। इससे टेंडर में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती और विभाग मनमाने आधार पर टेंडर दे देता है।

जनता दरबार लगाने पालकी पर सवार होकर निकले जिला उपायुक्त...

सरकारें वीवीआइपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में भले ही बढ़ रही हों, लेकिन अधिकारियों में यह मानसिकता अभी भी गहरी बैठी हुई है। जम्मू-कश्मीर के रामबन में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इस बात की गहरे से तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में रामबन के जिला उपायुक्त (डीसी) शौकत एजाज बट पालकी पर सवार होकर चक्क कुंडी करोल इलाके में जनता दरबार लगाने जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक आदमी छाता भी लगाए हुए है। यह वीडियो वायरल होने के बाद शौकत एजाज बट विवादों में घिर गए हैं। कई सारे लोग इसे सामंती प्रवृत्ति बताते हुए एजाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग बचाव में भी उतर आए हैं। वहीं डीसी रामबन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सो .मीडिया

शामली में छेड़छाड़ से त्रस्त मां-बेटी ने एसपी दफ्तर में खाया जहर

जागरण संवाददाता, शामली : दबंगों के उत्पीड़न व छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस के ध्यान न देने से क्षुब्ध मां-बेटी ने बुधवार को एसपी कार्यालय परिसर में जहर निगल लिया। दोनों को गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

झिंझाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार का गांव के ही दबंग से विवाद है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष की तीन बेटियों के साथ स्कूल आते-जाते आरोपित छेड़छाड़ और गाली-गलौज करते हैं। चौसाना पुलिस चौकी में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक महिला अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। किशोरी झिंझाना क्षेत्र के एक स्कूल में दसवीं की छात्रा है। एसपी की गैरमौजूदगी में मां-बेटी ने कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया और परिसर में ही जहर निगल लिया। पुलिस मां-बेटी को सीएचसी ले गई। एसपी अजय कुमार भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामले में विपिन, अरविंद, नरेश व सुनील व भारत के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। चौसाना चौकी इंचार्ज बीनू सिंह को निलंबित कर जांच एएसपी राजेश श्रीवास्तव को सौंपी है।

कर्ज का बोझ

एनर्जी प्लांट लगाने वाली कंपनी की हालत खस्ता, यूएई की एक कंपनी के साथ सौदा लगभग तय, महज पांच साल पहले ही शुरु हुई थी व्यवस्था

मप्र का कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट बिकने की कगार पर

अंजुल मिश्रा, जबलपुर। नईदुनिया

शहर में लगा प्रदेश का पहला कचरे से बिजली बनाने वाला पॉवर प्लांट 'वेस्ट टू एनर्जी' बिकने की कगार पर पहुंच गया है। एस्सल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी पिछले तीन माह से इसके लिए खरीदार की तलाश कर रही थी। हाल ही में यूएई की एक बड़ी कंपनी से प्लांट का सौदा तय होना बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने वाली एस्सल इंफ्रा कंपनी की माली हालत खस्ता हो चुकी है। कंपनी ने बैंक से कर्ज लेकर यह प्लांट लगाया था। कर्ज चुकाने में काफी परेशानी आ रही है। इसके अलावा प्लांट के अन्य खर्च भी कंपनी वहन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इसे बेचने का फैसला किया गया।

महज पांच साल पहले ही हुई थी शुरुआत : कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगाने की शुरुआत कठौंदा में 2014 में हुई थी। इसके लिए नगर निगम ने कंपनी को जमीन लीज में दी थी। प्लांट 2016 में बनकर तैयार हुआ और 11 मई 2016 से कचरे से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया था। प्लांट की क्षमता 11.7 मेगावाट प्रतिदिन की है लेकिन इसके लिए हर दिन करीब 450 टन कचरा आवश्यक था। हालांकि अभी तक प्लांट एक बार भी पूरी क्षमता पर नहीं चला। इससे हर दिन 6 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो पा रहा है। कंपनी ने प्लांट से बनने वाली बिजली के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से करार किया है। कंपनी प्लांट की बिजली 6 रुपए 39 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेच रही है। अब तक अनुमानित करीब 70 करोड़ रुपए की बिजली बेची जा चुकी है।

जबलपुर का वेस्ट टू एनर्जी कठौंदा प्लांट, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नईदुनिया

> जबलपुर में लगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बेचने की प्रक्रिया चल रही है। कई पार्टी से बात चल रही है लेकिन अभी तक डील पूरी नहीं हुई है। डील पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
> **-संदीप छामुन्या, सीईओ, एस्सजल इंफ्रा लिमिटेड**

डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर भी खतरा

यह प्लांट लगाने वाली एस्सल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ही शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का ठेका भी संचालित कर रही है। यह काम कंपनी पिछले ढाई साल से कर रही है। घाटे के कारण जब कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बेच रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कचरा संग्रहण के काम पर भी खतरा मंडराने लगा है। वैसे भी फिलहाल संग्रहण व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है।

डीआरआइ ने जब्त की 1.62 करोड़ की विदेशी सिगरेट

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ कोलकाता, सिलीगुड़ी व गुवाहाटी में छापेमारी कर सिगरेट की खेप जब्त

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने विदेशी सिगरेट की तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 1.62 करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की है। इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बुधवार को डीआरआइ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि विदेशी सिगरेट की यह खेप सिलीगुड़ी, कोलकाता और गुवाहाटी से पकड़ी गई। जांच में पता चला है कि विदेशी सिगरेट की खेप को म्यांमार से अवैध रूप से तस्करी कर मणिपुर के रास्ते लाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआइ की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर इसे जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि तीनों स्थानों से अलग-अलग ब्रांडों के पैकेटों में बंद कुल 16.27 लाख पीस विदेशी सिगरेट जब्त की गई है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.62 करोड़ रुपये है। ये सिगरेट इंडोनेशिया, चीन, कोरिया व म्यांमार मूल के हैं।

डीआरआइ के अनुसार सर्वप्रथम सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में एक ट्रक को रोककर 1.04 करोड़ रुपये मूल्य की 10.43 लाख पीस से अधिक सिगरेट बरामद की गई। इस सिलसिले में शंकर यादव नामक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि सिगरेट को म्यांमार से तस्करी कर मणिपुर के मोरेह में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते से लाया गया था। यादव ने पूछताछ में यहां से भेजे गए दो और खेप के बारे में जानकारी दी, जिसे कोलकाता व गुहावाटी भेजा गया था। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए डीआरआइ की टीम ने कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके में एक गोदाम में छापामारी कर 51.22 लाख रुपये मूल्य के पांच लाख पीस से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त की।

Downloaded from: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

एकाग्रता की राह में बड़ी बाधा हमारे भीतर उठती अभिलाषाएं हैं

एक और एकतरफा चिट्ठी

असहमति की अनदेखी और भीड़ की हिंसा को लेकर 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी जो चिंता जाहिर की वह नई नहीं है। इस तरह की चिट्ठियां पहले भी लिखी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं असहिष्णुता बढ़ने का शोर मचाते हुए पुरस्कार भी वापस किए गए हैं और जनता से यह आग्रह भी किया गया है कि भाजपा को वोट न दें। इस तरह की चिट्ठियां लिखने वाले खुद को लिबरल यानी उदारवादी बताते हैं, लेकिन शायद वे खुद नहीं जानते कि उदारवाद क्या है? चूंकि ऐसे बुद्धिजीवी चतुराई से चुनिंदा मामलों का उल्लेख करते हुए अपनी एकतरफा सोच ही सामने रखते हैं इसलिए उनकी अपीलों का कोई असर नहीं होता। इस नई चिट्ठी का भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें केवल दलितों और अल्पसंख्यकों को ही भीड़ की हिंसा का शिकार बताते हुए इस सच को जानबूझकर ओझल किया गया कि अन्य अनेक वर्गों के लोग भी भीड़ के उन्माद की चपेट में आ रहे हैं। आखिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिक्के का एक ही पहलू दिखाना बौद्धिक बेईमानी नहीं तो और क्या है? वास्तव में इसी रवैये के कारण यह कहा जाने लगा है कि उदारवादी ही उदारवाद के सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं।

49 प्रबुद्ध लोगों ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जय श्रीराम नारे को एक भड़काऊ नारे में तब्दील कर दिया गया है और उसके नाम पर भीड़ हिंसा कर रही है। इससे इन्कार नहीं कि ऐसे एक-दो मामले सामने आए हैं, लेकिन क्या इक्का-दुक्का मामलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जय श्रीराम नारे का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए किया जा रहा है? क्या इस सच की अनदेखी कर दी जाए कि जय श्रीराम नारे के नाम पर कथित हिंसा के कई मामले फर्जी भी पाए गए हैं? आखिर इन फर्जी घटनाओं को कौन गढ़ रहा है? निःसंदेह भीड़ की हिंसा पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन यह साबित करने का कोई मतलब नहीं कि जय श्रीराम का नारा एक भड़काऊ नारा बन गया है। सदियों से राम का नाम अलग-अलग भाव में लिया जाता रहा है, जैसे सीताराम, सियाराम, राम-राम। इसी कड़ी में जय श्रीराम भी है। इसका उपयोग भक्तिभाव प्रकट करने के साथ ही जोश जगाने या फिर गर्व का भाव व्यक्त करने के लिए होता चला आ रहा है। साफ है कि जय श्रीराम नारे को भड़काऊ करार देना एक किस्म की असहिष्णुता ही है।

उद्योगों को बचाना जरूरी

बिजली बिल में वृद्धि से कोल्हान क्षेत्र की चार कंपनियों के बंद होने की स्थिति इस तथ्य को रेखांकित कर रही कि झारखंड में उद्योगों को बचाने-बढ़ाने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना पर अमल करने की आवश्यकता है। उद्योगों के सामने यह समस्या सिर्फ कोल्हान में ही नहीं आई है। पूरे राज्य के छोटे-बड़े उद्योग बिजली दरों में हुए इजाफे से प्रभावित हैं। इसका असर दिखने भी लगा है। इसलिए समय रहते बिजली बिल की मार से उद्योगों को बचाने के लिए शासन के स्तर से ठोस पहल शीघ्र होनी चाहिए। ऐसा रास्ता तलाशा जाना चाहिए कि औद्योगिक विकास की गाड़ी बेपटरी न हो जाए। वैसे भी किसी उद्योग या कंपनी के बंद होने का प्रतिकूल असर चौतरफा होता है। कामगार एवं उनके परिवार तो सीधे तौर पर प्रभावित होते ही हैं, उद्योगों के आसपास के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी चपेट में आती है। राज्य की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह बात भी सही है कि केवल सब्सिडी और मदद के जरिए किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि ऐसी मदद छोटे उद्योगों के लिए संजीवनी साबित होती है। राज्य के वैसे उद्योगों को यह राहत तत्काल मिलने की दरकार है जो बिजली का अधिकतम उपयोग करके संचालित होते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने वर्ष 2019-20 के दौरान बिजली की दरों में औसतन छह फीसद की वृद्धि की है, जबकि फर्नेस वाले उद्योगों के लिए यह वृद्धि 24 फीसद तक है। स्वाभाविक तौर पर उन उद्योगों को बिजली दर वृद्धि बहुत भारी पड़ रही। इसलिए इस प्रस्ताव पर समग्र विचार मंथन कर ऐसी नीति अंगीकार की जानी चाहिए जिसमें स्पष्ट रहे कि किस श्रेणी के उद्योग को किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी और कितने दिनों तक। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्सिडी का बेजा फायदा उठाने की कोशिश न की जाए। बिजली चोरी करने या बिजली बिल का समय से भुगतान नहीं करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखनेवाले उद्योगों को इस लाभ से हर हाल में वंचित रखने का भी इंतजाम होना चाहिए। तभी सही उद्योगों को सही तरीके से मदद मिल सकेगी और फर्जीवाड़ा करनेवाले उद्योगों को कार्रवाई का करंट लगेगा।

> किसी उद्योग या कंपनी के बंद होने का प्रतिकूल असर चौतरफा होता है। कामगार एवं उनके परिवार तो सीधे तौर पर प्रभावित होते ही हैं, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी चपेट में आती है

नजरअंदाज करने लायक बयान

हर्ष वी पंत

> अगर ट्रंप के विचारों से तालमेल बैठाने में खुद उनके विदेश विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तो समझा जा सकता है कि भारत के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती है?

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर भारत की परंपरागत नीति के उलट बयान दिया तो मानों भूचाल सा आ गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने अनपेक्षित और उससे भी कहीं अधिक नाटकीय रूप से यह दावा किया कि भारत ने उनसे कश्मीर मामले में मध्यस्थता की पेशकश की। उनके इस बयान से भारत में राजनीतिक हलचल होनी स्वाभाविक थी। उनका यह बयान सुर्खियां बन गया। जापान के ओसाका में आयोजित जी-20 देशों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए ट्रंप ने बड़े विचित्र ढंग अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'दो सप्ताह पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था और हमने इस विषय पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्या आप मध्यस्थ बनना चाहेंगे? मैंने पूछा कि कहां? उन्होंने जवाब दिया कश्मीर में। चूंकि यह मसला इतने वर्षों से उलझा हुआ है तो मुझे लगता है कि वे इसे सुलझाना चाहते हैं और आप (इमरान) भी इसका समाधान होते देखना चाहते हैं। अगर इसमें मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो ऐसा करते हुए मुझे बेहद खुशी होगी।'

भारत में तमाम लोगों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह अमेरिका की दशकों पुरानी उस नीति के उलट है जिसमें वह कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता आया है कि यह मसला भारत और पाकिस्तान को आपस में सुलझाना चाहिए। उसका यह रवैया भारतीय भावनाओं के अनुरूप ही रहा। हालांकि बराक ओबामा सहित तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति कश्मीर मसले पर मध्यस्थ बनने का मोह रोक नहीं पाए और यदाकदा ऐसी पेशकश करते रहे। हालांकि अब वाशिंगटन को भलीभांति समझ आ गया है कि अगर वह भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर और परिपक्व करना चाहता है तो फिर कश्मीर के मसले में टांग न ही अड़ाए तो बेहतर होगा। फिर भी आखिर ट्रंप को ऐसा कहने के लिए किसने उकसाया होगा, इस पर भारत में अटकलों का बाजार गर्म है। ट्रंप की इस हालिया जुमलेबाजी की तह में जाने के लिए तमाम परतें उघाड़ी जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि अहम भू-राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप की क्या मनोदशा रहती है? अगर ट्रंप के विचारों से तालमेल बैठाने में खुद उनके विदेश विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तो समझा जा सकता है कि भारत के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती है?

चूंकि यह मसला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था तो भारतीय पक्ष ने भी त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी कि यदि भारत और पाकिस्तान अनुरोध करते हैं तो वह कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया है। भारत का हमेशा से यही रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी किस्म के मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय स्तर पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की सक्रियता से पहले जरूरी होगा कि वह अपने यहां आतंकी ढांचा खत्म करें। शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र में वे सभी बिंदु हैं जिनके आधार पर सभी मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं।'

अवधेश राजपूत

ट्रंप के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत विस्तृत नहीं थी, लेकिन इसने यह जरूर स्पष्ट किया कि इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। नई दिल्ली की ओर से औपचारिक विरोध जताने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी नुकसान की कुछ भरपाई की कोशिश के तहत यह रेखांकित किया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और अगर दोनों देश बातचीत के लिए साथ आते हैं तो अमेरिका इसका स्वागत करता है। उसने यह भी कहा कि आंतकवाद के खिलाफ पाकिस्तान 'निरंतर और स्थायी' कदम उठा रहा है जो भारत के साथ सार्थक वार्ता में अहम है।

कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है और भारतीयों की अपने मित्र देशों से यह अपेक्षा सही है कि वे भारत के मूलभूत हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं, मगर ट्रंप जैसे अक्खड़ नेता से यह अपेक्षा बेमानी लगती है। वह बहुत ही अस्थिर मिजाज वाले राष्ट्रपति हैं और उनका रवैया भी गैरपरंपरागत है। अमेरिका के कुछ करीबी देशों के प्रति उनके विषवमन ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के समक्ष चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय नई दिल्ली को कुछ प्रतीक्षा कर यह देखना चाहिए कि कश्मीर को लेकर ट्रंप के रवैये में आगे क्या रुझान देखने को मिलता है? अगर वह कश्मीर पर ऐसे ही हाव-भाव दिखाते हैं तो भारत को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, लेकिन अगर वह इस मसले पर आगे कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर इसे कोई मुद्दा न मानते हुए इस पर ऊर्जा व्यर्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रहे कि व्हाइट हाउस की ओर से ट्रंप-इमरान के संयुक्त बयान में कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ट्रंप के बयान पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया दमदार और दूसरे पक्ष को साधने की कवायद भी सराहनीय रही। अमेरिका को संदेश मिल गया होगा कि उसे भूल सुधार की दरकार है। वह यही करने में जुटा है। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय एजेंडे में कई और मुद्दे सुलझाए जाने बाकी हैं। इनमें ईरान के साथ व्यापार, रूस के साथ एस 400 की खरीद से लेकर 5जी तक पर पेंच फंसे हुए हैं। वांछित परिणाम हासिल करने की दिशा में परस्पर सहमति के स्तर पर पहुंचने के लिए दोनों देशों को सार्थक संवाद की दरकार है। वास्तव में हमारे लिए अफगानिस्तान में बनते हालात गहन चिंता का विषय होने चाहिए, विशेषकर यह देखते हुए कि ट्रंप ने किस तरह अफगानिस्तान से निकलने में पाकिस्तान से मदद मांगी है।

वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे की गूंज वक्त के साथ कुछ कमजोर पड़ी है, लेकिन भारतीय राजनीति के कुछ हलकों में इसकी व्यापक संवेदनशीलता को देखते हुए यह मुद्दा वापस वैश्विक एजेंडे में आ सकता है। अतीत में जब भारत वैश्विक शक्ति अनुक्रम में अपेक्षाकृत निचले पायदान पर था तब भी वह तमाम बड़ी शक्तियों को कश्मीर मामले में दखल देने से रोकने में सफल रहा था। उसकी तुलना में आज जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं तब कश्मीर के मुद्दे और बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हैं। ट्रंप का अनर्गल बयान जिस लायक है उसे उसी लिहाज से नजरअंदाज करते हुए नई दिल्ली को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

भाजपा के कांग्रेसीकरण का सवाल

प्रदीप सिंह

> भाजपा और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है और वह शायद हमेशा रहेगा तथा भाजपा के कांग्रेसीकरण को रोकेगा

राजनीतिक हलकों में आजकल यह नया विमर्श चल रहा है कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है या फिर उसका कांग्रेसीकरण हो रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे दलों से सांसद, विधायक और नेता भाजपा में शामिल हुए या कराए गए उससे यह विमर्श निकला है। केंद्र के साथ 16 राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा को ऐसा करना क्यों जरूरी लग रहा है और इसके जरिये पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रही है? कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल-एस की साझा सरकार गिरने के बाद भाजपा की 17वीं राज्य सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले गोवा में कांग्रेस के दस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। अब चर्चा है कि अगला नंबर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का है। उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। इन अटकलों के आधार पर सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा 1960-70 के दशक की कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है? अपने वर्चस्व के दिनों में कांग्रेस ने भी अपनी विरोधी सरकारों के साथ यही किया था। एक समय गोविंदाचार्य ने भी कहा था कि भाजपा दरअसल गुलाबी छटा वाली कांग्रेस है।

भाजपा में इस समय दो धाराएं समानांतर रूप से चल रही हैं और यह ध्यान रहे कि समानांतर रेखाएं कभी मिलतीं नहीं। पहली धारा के तीन चरण हैं। पहला, ऐसे क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार नहीं है वहां दूसरे दलों से लोगों को पार्टी में शामिल करके पार्टी का यकायक विस्तार। इसकी शुरुआत 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हरियाणा से हो गई थी। जहां कांग्रेस के राज्य स्तर के कई नेता भाजापा में शामिल हो गए और राज्य में सरकार बन गई। इसके अलावा बंगाल, असम, केरल, तेलंगाना, आंध्र जैसे राज्यों में दूसरे दलों से लोगों को पार्टी में इसी रणनीति के तहत लाया गया। दूसरा, नए सामाजिक समूहों से पार्टी को जोड़ना। इसके लिए पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर बड़े पैमाने पर इस वर्ग में अपनी पैठ बनाई। इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा और हाल के लोकसभा चुनाव में दिखा। तीसरा, जहां कांटे की टक्कर है वहां कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास। पार्टी की इसी नीति को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। गोवा में सरकार को स्थिर बनाने के लिए भाजपा ने विचारधारा और नैतिकता, दोनों स्तर पर समझौता किया। जिस नेता के बारे में पार्टी ने प्रचार किया कि वह दुराचारी है उसे पार्टी में शामिल किया और उसकी पत्नी को मंत्री बना दिया। गोवा में इस समय भाजपा के 27 विधायकों में से 15 ईसाई हैं यानी उनका बहुमत है। क्या गोवा भाजपा के लिए इतना बड़ा और अहम प्रदेश है कि उसके लिए पार्टी ऐसे समझौते करे? आंध्र के दागी नेता जिसे भाजपा राज्य का माल्या कहती थी, को इस आधार पर पार्टी में शामिल किया गया कि राज्यसभा में बहुमत जुटाने के लिए ऐसा करना मजबूरी थी।

कर्नाटक का मामला थोड़ा अलग है। राज्य में भाजपा का मजबूत जनाधार है। राज्य की 28 में से 25 सीटों पर उसके सांसद हैं। कांग्रेस और जद-एस के बागी विधायकों में से ज्यादातर बिल्डर हैं। अगले कुछ दिन में ये भाजपा में शामिल होंगे ही। राज्य में अभी जो हालात हैं उनमें जब भी विधानसभा चुनाव होते तो पार्टी को बहुमत मिलने की प्रबल संभावना थी। फिर जोड़तोड़ की सरकार बनाने का फैसला क्यों किया गया? विपक्ष के जो बागी आएंगे उनकी कितनी मांगे पार्टी पूरी कर पाएगी? ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व इन सवालों को महत्वहीन मानता है। आरएसएस में आजकल इन नवागंतुकों को नव नेकरवादी कहा जा रहा है। अभी तक कुछ अपवादों को छोड़कर नव नेकरवादियों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। यही दूसरी धारा का संकेत है। दूसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद मेनका गांधी, जयंत सिन्हा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, केजे अल्फांस और राम कृपाल यादव जैसे कई नव नेकरवादियों की छुट्टी कर दी गई। जो बचे वे केवल अपनी कार्यकुशलता की वजह से। इसके जरिये पार्टी ने एक संदेश दिया है कि उसकी नजर में विचारधारा गौण नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों, एनआरसी, अनुच्छेद 370, 35 ए, समान नागरिक संहिता और तीन तलाक के मुद्दे पर पार्टी कायम है। अमित शाह का गृहमंत्री बनना भाजपा की विचारधारा के लिहाज से सामान्य घटना नहीं है। जो काम पिछले पांच साल में नहीं हुआ वह अब होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह की कश्मीर यात्रा के दौरान जो नजारा देखने को मिला वह आने वाले दिनों का संकेत है। इस मोर्चे पर मोदी-शाह की जोड़ी ने एक और बड़ा और शायद सबसे अहम काम किया है और वह है वाजपेयी सरकार के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखकर आरएसएस, पार्टी और सरकार में सांगोपांग समन्वय। कर्नाटक के बीएल संतोष का संगठन महासचिव बनना इस रणनीति के अलावा एक और संदेश है कि वाजपेयी राज में जिस तरह संगठन की उपेक्षा हुई थी वैसा नहीं होगा। उस समय वाजपेयी, आडवाणी दोनों के सरकार में जाने के बाद ऐसा ही हुआ था। संगठन की दृष्टि से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सबसे अहम बदलाव है।

भाजपा कांग्रेस तभी बन सकती है जब नव नेकरवादी दूध में पानी के बजाय पानी में दूध की तरह हो जाएं। इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती यानी दोनों धाराओं का मिलन मुश्किल है। भाजपा और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है, जो शायद हमेशा रहेगा। भाजपा में विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज हमेशा रहती है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की सप्लाई लाइन संघ से सदा बनी रहती है। जब भाजपा विचारधारा से हटकर सत्ता के लिए ही सब कुछ करने की ओर बढ़ती है तो कार्यकर्ताओं की यह फौज घर बैठ जाती है। उसके बाद चुनाव में जो होता है उससे सत्ता का नशा उतर जाता है। कभी-कभी नेताओं को गलतफहमी हो जाती है कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा विचारधारा से ज्यादा उनके प्रति है। बड़े-बड़े दिग्गज इसी मुगालते में हाशिये पर चले गए। कार्यकर्ताओं का यही निष्ठा भाव ही भाजपा को कांग्रेस नहीं बनने देगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समस्या से मुक्ति

हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, उसके समाधान के लिए जरूरी है कि हम अपनी समस्या को समझें और फिर समाधान खोजें। मानसिक बल निषेधात्मक भावों द्वारा कमजोर होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह माना है कि जितने नकारात्मक भाव हैं, वे हमारी बीमारियों एवं समस्याओं से लड़ने की प्रणाली को कमजोर बनाते हैं। ईर्ष्या, भय, क्रोध, घृणा नकारात्मक भाव हैं। प्रायः यह कहा जाता रहा है कि ईर्ष्या मत करो, घृणा और द्वेष मत करो। इससे पाप कर्म का बोध होता है। एक धार्मिक के लिए यह महत्वपूर्ण निर्देश है, किंतु आज यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसे निषेधात्मक भावों से बचना चाहिए। बार-बार क्रोध करना, चिड़चिड़ापन आना, मूड का बिगड़ते रहना-ये सारे भाव हमारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति को कम करते हैं।

आज जरूरत है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए औरों के मोहताज न बनें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे भीतर से न मिले। भगवान महावीर का यह संदेश जन-जन के लिए सीख बने-'पुरुष! तू स्वयं अपना भाग्यविधाता है।' औरों के सहारे मुकाम तक पहुंच भी गए तो क्या? इस तरह की मंजिलें स्थायी नहीं होतीं और न इस तरह का समाधान कारगर होता है। हमारे भीतर ऐसी शक्तियां हैं, जो हमें बचा सकती हैं। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्पवान व्यक्ति अंधकार को चीरता हुआ स्वयं प्रकाश बन जाता है। चंचलता की अवस्था में संकल्प का प्रयोग उतना सफल नहीं होता जितना वह एकाग्रता की अवस्था में होता है। हर व्यक्ति रात्रि के समय सोने से पहले एक संकल्प करे, उसे पांच-दस मिनट तक दोहराए, मैं यह करना या होना चाहता हूं, इस भावना से स्वयं को भावित करे, एक निश्चित भाषा बनाए और उसकी सघन एकाग्रता से आवृत्ति करे, ऐसा करने से संकल्प बहुत शीघ्र सफल होता है। व्यक्ति में यह आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि जो मुझे चाहिए वह मेरे भीतर है तो मानना चाहिए कि समस्या के समाधान का मार्ग मिल गया है। इस प्रकार से शक्ति का बोध, जागरण की साधना और उसका सही दिशा में नियोजन, यदि इतना सा विवेक जाग जाए तो सफलता का स्रोत खुल जाएगा।

ललित गर्ग

विज्ञान की दुनिया में महिलाएं

डॉ. मोनिका शर्मा

> देश में विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी सामाजिक-पारिवारिक स्तर में भी बड़ा बदलाव ला सकती है

हाल ही में सफलतापूर्वक लांच किए गए चंद्रयान-2 अभियान में इसरो की दो महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने देश के सपनों को आकार देने वाले चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट में ऋतु करिधाल अभियान निदेशक और एम. वनिता परियोजना निदेशक हैं। सुखद है कि भारत का अंतरिक्ष में फतेह पाने का यह सिलसिला विज्ञान की दुनिया में देश की आधी आबादी की भूमिका भी पुख्ता कर रहा है।

यह सकारात्मक और संबल देने वाली बात है कि कभी महिलाओं का न के बराबर दखल वाले इस क्षेत्र में स्त्रियों का हर अभियान में बढ़-चढ़ योगदान देखने को मिल रहा है। विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करने के लिए अपेक्षित भी है कि महिला वैज्ञानिकों को ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने और खुद को साबित करने का अवसर मिले, ताकि राष्ट्र निर्माण से जुड़े एक अहम क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने का माहौल बने। यकीनन इसरो का हर अभियान महिलाओं के विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान की दुनिया में बढ़ते कदमों का मजबूत आधार तैयार कर रहा है। इस बुनियाद पर आने वाले समय में देश की बेटियां विज्ञान और अनुसंधान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने की राह चुनेंगी। निःसंदेह महिला वैज्ञानिकों की यह भागीदारी इस क्षेत्र में युवतियों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने वाली है। फिलहाल यह संतोषजनक है कि देश के प्रमुख वैज्ञानिक अभियानों में शीर्ष स्तर से लेकर एक सफल टीम बनाने तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखने लगा है।

इसरो की 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 2069 महिलाएं विज्ञान संबंधी तथा तकनीकी श्रेणियों और 3285 महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसंधान और विकास गतिविधियों में कार्यरत कुल 2.82 लाख लोगों में से 14 प्रतिशत महिलाएं हैं। समय के साथ इस हिस्सेदारी के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी महिलाओं के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी बेहतर बनाने वाला है। विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी सामाजिक-पारिवारिक स्तर में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिक चेतना और तकनीकी जागरूकता स्त्री जीवन से जुड़ी कई रूढ़ियों से मुक्ति दिला सकती है।

आज जिंदगी के हर मोर्चे पर महिलाएं बराबरी से शामिल हैं। खेल का मैदान हो, राजनीति का अखाड़ा हो या फिर अंतरिक्ष से जुड़े अनुसंधान की दुनिया। हालांकि हमारे यहां कई कारणों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की संख्या कम रही है। यही वजह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रशासनिक ही नहीं, सामाजिक-पारिवारिक स्तर पर भी सहयोगी वातावरण बनाना जरूरी है, ताकि बड़ी संख्या में युवा महिलाएं विज्ञान की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकें। सुखद है कि इस मोर्चे पर भी धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है। विज्ञान और अनुसंधान की दुनिया में न केवल महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, बल्कि वे नेतृत्वकारी भूमिका में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आरटीआइ कानून में संशोधन

सूचना कानून पर मंडराता खतरा शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगदीप एस छोकर ने मोदी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को जनहित के विरुद्ध बताया है, लेकिन जरूरी नहीं कि मोदी सरकार अगर सूचना कानून में कुछ संशोधन करके सभी अधिकार अपने अधीन ले लेती है तो इससे आम लोगों को नुकसान ही होगा। हो सकता है कि मोदी सरकार इस कानून को और सरल और इसकी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी कानून की धारा-9 में कुछ मामलों में सूचना नहीं देने का आधार है। धारा-11 के तहत थर्ड पार्टी से संबंधित जानकारी नहीं देने का भी प्रावधान है। वहीं धारा-24 के तहत कानून कुछ संगठनों पर लागू भी नहीं होता है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि यह अधिनियम सूचना देने में शत प्रतिशत सक्षम है। सभी सरकारी विभाग सरकार के अधीन ही होते हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जो मौजूदा समय में सूचना अधिकार नियम के अंतर्गत सूचनाएं दी जाती हैं, वे सरकार की मर्जी के खिलाफ ही दी जाती हैं? अक्सर कभी-कभी कुछ विभाग इस कानून में मांगी कुछ जानकारियों को न देने के लिए यह तर्क भी दे देते हैं कि यह जानकारी गोपनीयता से जुड़ी है। हमारे देश में बहुत से लोग तो सूचना अधिकार अधिनियम से भी अनजान हैं। उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकारें भी गंभीरता नहीं दिखातीं। शायद वे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहतीं। अगर देश के सभी नागरिक इस अधिनियम के प्रति जागरूक हो गए तो फिर भ्रष्ट नेताओं-अधिकारियों की खैर नहीं। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वह लोगों को इसके प्रति जागरूक करे।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

होनहार हिमा दास

हिमा दास भले ही मुंह में चांदी का चम्मच लिए न पैदा हुई हों, पैरों से सोना रोंदने की काबलियत रखती हैं। देश जहां बेटियों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है वहीं हिमा बेफिक्री से दुनिया को पैरों से नापने चल पड़ी हैं। एक पखवाड़े में छह गोल्ड मेडल झटकना कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर हिमा मल्लिका-ए-रफ्तार ने खेल-खेल में यह कारनामा कर दिखाया। उम्मीद है कि इस होनहार धावक की रफ्तार कभी कम न होगी।

mkmishra75@yahoo.in

कर्नाटक में बना इतिहास

पिछले साल मई 2018 में जब येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और राज्यपाल ने उन्हें 4 दिन का समय बहुमत साबित करने के लिए दिया था तो आधी रात को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 24 घंटे में बहुमत सिद्ध किया जाए। न्यायमूर्ति ने कहा था कि जिसे सदन का विश्वास प्राप्त नहीं, उसे एक घंटे भी पद पर बने रहने का हक नहीं है। इस वर्ष पूरे 6 दिन एक अल्पमत की सरकार शासन करती रही। यह शायद भारतीय इतिहास की पहली घटना है, जब इतने दिन तक विश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई चलती रही। दो-दो बार राज्यपाल का आदेश ठुकराते हुए मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहे, ये एक खतरनाक नजीर बनी है।

ajay.mittal97khandak@gmail.com

आत्मनिर्भरता की उड़ान

चंद्रयान-2 भारत की बड़ी सफलता है। भारतीय वैज्ञानिकों को चाहिए कि इसी तरह आधुनिक हथियार भी बनाएं, जिससे पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने पर अधिक धनराशि खर्च न करनी पड़े।

डॉ. नूतन कुमार सी. पाटणी, नोएडा

ट्रंप का अनुचित बयान

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर झूठ बोलें तो सबके सामने उनकी छवि कैसी बनेगी? यह सोचने की बात है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं है। हो सकता है वह किसी रणनीति के तहत ऐसा बोलते हों। कश्मीर मसले पर उनके दो कारण हो सकते हैं। एक भारत का रूस से अत्याधुनिक हथियार खरीदना और दूसरा पाकिस्तान की मदद से तालिबान से वार्ता कर अफगानिस्तान से शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिकी सेना को बाहर निकालना। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगना कतई उचित नहीं है। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, वह काफी है। अमेरिका खुद भी न तो इस बयान का समर्थन कर रहा है और न ही किसी रिकार्ड में रखा है। ऐसे में बेवजह का शोर शराबा करना गलत है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

13 करोड़ को पार कर जाएगी 2045 तक देश में मधुमेह रोगियों की संख्या। दो साल पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में सात करोड़ तीस लाख लोग ऐसे थे जो मधुमेह की चपेट में थे।

आजकल

फर्जीवाड़े के दुष्चक्र में घर का सपना

आम्रपाली समूह के खिलाफ दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न केवल इसके प्रोजेक्ट में घर लेने वाले 42 हजार ग्राहक, बल्कि वे ईमानदार बिल्डर भी राहत महसूस कर रहे होंगे, जिनकी विश्वसनीयता इस सेक्टर में हो रही धांधलियों के चलते संकट में पड़ गई थी। सवाल यह है कि जो काम बेहद लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, सरकारें अगर चाहती तो क्या यह सब कुछ पहले नहीं हो सकता था

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

भारत जैसे आबादी बहुल देश में रोटी, कपड़े के बाद तीसरी सबसे अहम जरूरत मकान की उपलब्धता का क्या हाल है, इसका अंदाजा इससे लग जाता है कि पिछले एक-डेढ़ दशक में घर के सपने दिखाकर तमाम रियल्टी कंपनियों ने हजारों-लाखों जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाकर खुलेआम धोखाधड़ी की और प्राधिकरणों से मिलीभगत कर कौड़ियों के भाव ली गई जमीनों पर घर बनाकर फिर भी नहीं दिए। इससे सरकारों, बैंकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई और अंततः वही हुआ, जिसका डर था। घबराए घर खरीदारों ने अपनी इस महती जरूरत से हाथ खींच लिया, जिससे पूरा रियल्टी सेक्टर चरमरा गया। ऐसे में 23 जुलाई, 2019 को एक नामी बिल्डर आम्रपाली समूह के खिलाफ दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न केवल इसके प्रोजेक्ट में घर लेने वाले 42 हजार ग्राहक, बल्कि वे ईमानदार बिल्डर भी राहत महसूस कर रहे होंगे, जिनकी विश्वसनीयता इस सेक्टर में हो रही धांधलियों के चलते संकट में पड़ गई थी।

यूं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ जो फैसला दिया है और जिसमें अधूरे प्रोजेक्ट उससे छीनकर उन्हें पूरा करने का जिम्मा सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिया है, उससे एक फौरी राहत की उम्मीद तो की जा रही है, पर सवाल यह है कि जो काम बेहद लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, सरकारें अगर चाहतीं तो क्या यह सब कुछ पहले नहीं हो सकता था। पिछले दो-एक साल में चंद नामी बिल्डरों के मालिकों-सीईओ की गिरफ्तारी भी ग्राहकों से धोखा करने के लिए की गई है। उन्हें जेल में ठूंसा गया है और उन्हें दी गई जमीनों के आवंटन प्राधिकरणों ने रद कर दिए हैं। ऐसी कार्रवाइयां एक संतोष तो जगाती है कि आखिर फर्जीवाड़े करने वाले बिल्डरों के खिलाफ देश में कुछ तो एक्शन हुआ है, वरना करोड़ों-अरबों का चूना लगाने के बावजूद कोई उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे कुछ अहम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। जैसे एक सवाल तो यही है कि निजी बिल्डर कंपनियों के अधूरे प्रोजेक्टों को एनबीसीसी जैसी सरकारी कंपनी आखिर समय पर कैसे पूरा कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती फंड जुटाने की है। आम्रपाली समूह के मामले को देखें तो इससे संबंधित ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खुद करीब 6 हजार करोड़ के कर्ज तले दबी है। इस दौरान भवननिर्माण की लागत भी काफी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के रोडमैप के अनुसार काम शुरू होता है तो 6 महीने से 36 महीने के अंदर निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा सिर्फ आदर्श स्थितियों में ही संभव है, पर यहां तो समस्या ऐसे मामलों में एक झोल के अंदर कई झोल छिपे होने की है। एक अन्य सवाल यह है कि पिछले अरसे में धोखा देने वाली जिन कंपनियों की जमीन वापस ली गई है, जिनके आवंटन रद कर दिए गए हैं, उन जमीनों पर बनने वाले अपार्टमेंटों में घर लेने के बदले पैसा दे चुके ग्राहकों का क्या होगा? जाहिर है कि जब ये मामले सालों-साल अदालत में चलेंगे, वर्षों बाद कहीं जाकर उन पर कोई फैसला आएगा, तब तक ग्राहक सिवाय हाथ मलने के कुछ कर नहीं सकेंगे।

आवासीय सेक्टर में पारदर्शिता

हालांकि बरसों तक पूरे देश के आवास सेक्टर में धांधलियां होने के बाद सरकार और कानून की नजर इस गोरखधंधे पर गई है और अब इस इंडस्ट्री के कायदे-कानून बदल रहे हैं। एक बड़ा बदलाव इस संबंध में लागू हुए रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट से आया है, क्योंकि इस कानून के लागू के बाद बिल्डरों का वह जलवा नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। इसमें बिल्डरों के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं, ताकि वे ग्राहकों से वादाखिलाफी और कोई धोखाधड़ी न कर पाएं, पर इस सेक्टर में ज्यादा बड़ी तब्दीली की उम्मीद अब रियल्टी एक्ट से ही है। आवास सेक्टर में पारदर्शिता लाने वाले इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पारदर्शिता के लिए निजी बिल्डरों को अपने पूरे प्रोजेक्ट का खुलासा करना होता है। उन्हें यह बताना पड़ता है कि उनका प्रोजेक्ट कितने साल में पूरा हो जाएगा। यही नहीं, गड़बड़ी करने पर बिल्डर को सजा भी हो सकती है।

असल में यह पूरा मामला आवासीय सेक्टर में पारदर्शिता लाने का है, जिसकी जरूरत कई वजहों से पैदा हुई है। दरअसल सरकारी योजनाओं के मकान इतने महंगे रहे हैं कि मध्यवर्ग ने उन योजनाओं के जरिये घर-मकान पाने के सपने को हाशिये पर रख देना ही बेहतर समझता है। यह नजारा देश के तकरीबन हर छोटे-बड़े शहर में कायम है जहां रोजी-रोजगार के सिलसिले में पड़ोसी इलाकों या राज्यों से आ पहुंचे लोग या तो गांव-देहात की अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर अथवा हैसियत से कई गुना ज्यादा कर्ज लेकर घर लेने की कोशिश करते हैं या फिर अपने घर के सपने को मुल्तवी रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हालांकि किराये के मकानों में भी महंगाई की जैसी आग लगी है, उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। लिहाजा या तो वे शहरों के इर्दगिर्द अवैध ढंग से काटी गई कॉलोनियों में सिर छिपाने को छोटा-मोटा इंतजाम कर यह मनाते रहते हैं कि उनके घर पर सरकार की नजर न पड़े या फिर वे अपनी सारी जमापूंजी निजी बिल्डर के हाथों इस आस में थमा देते हैं कि वही किसी ठीकठाक जगह पर उनके रहने का इंतजाम कर देगा, लेकिन यह इंतजाम कैसा हो सकता है, दिल्ली-एनसीआर में अधूरे पड़े लाखों फ्लैट इसकी गवाही देते हैं।

हालांकि इस बीच में सरकार ने शहरी इलाकों में सभी लोगों के सिर पर छत दिलाने के वास्ते जो एजेंडा तय किया है, उसके मुताबिक 2022 तक नौ करोड़ मकान तैयार किए जाने हैं, लेकिन इसकी राह किसी भी लिहाज से कांटों भरी ही है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक यह लक्ष्य पाने के लिए सरकार को आवासीय निर्माण क्षेत्र में 260 अरब डॉलर का निवेश करना होगा जो उसके बूते के बाहर की बात है। इसलिए उसे कर्जदाता संस्थाओं और विदेशी पूंजीदाताओं के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है और निजी बचतों पर डाका डालना पड़ सकता है। यही नहीं, निजी आवासीय योजनाओं की संस्तुति के कामकाज में भी उसे काफी तेजी लानी होगी, क्योंकि फिलहाल विश्व बैंक का आकलन यह है कि भारत में किसी निर्माण कार्य की अनुमति लेने की 34 न्यूनतम प्रक्रियाएं हैं और उन्हें पूरा करने में औसतन 196 दिन लगते हैं। यदि यही रफ्तार आगे भी कायम रहती है तो नौ करोड़ लोगों को मकान देने में 60-70 साल लग सकते हैं।

कैसे दूर हो मकानों की किल्लत

आज देश में 2.7 करोड़ लोगों के पास रहने को घर नहीं हैं और वे झोपड़-पट्टियों में गुजर-बसर कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मकानों की यह किल्लत दूर हो तो आखिर कैसे। चूंकि शहरों में लोगों को रोजगार मिल रहा है और आने वाले वर्षों में गांव-कस्बों से काम की तलाश में लोगों का शहरों की तरफ पलायन थमने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ऐसे समाधान की जरूरत है जो इन लोगों के आवास की तात्कालिक जरूरतों को भी पूरा करे और शहरों पर अनावश्यक बोझ भी न डाले। इसका एक उपाय है खाली पड़े मकानों को किराये पर उपलब्ध कराना और सिंगापुर एवं हांगकांग की तर्ज पर किराये के लिए ही नए सरकारी मकान बनाना। ध्यान रहे कि किसी शहर का काम सिर्फ बाबुओं और निजी कंपनियों में काम करने वाले मैनेजरों के बल पर नहीं चलता। शहरों को घर में काम करने वाली आया-महरी से लेकर रेहड़ी-पटरी वाले और आठ-दस हजार रुपये महीने पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, लेकिन ये सारे शहर में तभी रह सकते हैं, जब दो-ढाई हजार रुपये में उनके वहां रहने का इंतजाम हो सके। अफसोस कि निजी हो या सरकारी-आज किसी भी आवासीय योजना में ऐसे लोगों के लिए भी कोई खास जगह नहीं बची है। इस जरूरत को ठीक से समझने और इसके समाधान की कोशिशें करने का वक्त आ चुका है। यदि अब भी इसमें कोई अनावश्यक देरी की गई तो न सिर्फ एक आम शहरी के लिए मकान का सपना महज हवाई बनकर रह जाएगा, बल्कि ऐसी कामकाजी आबादी अपने मूल ठिकानों की ओर वापसी का रुख कर सकती है। खास तौर से मध्यवर्गीय कामकाजी आबादी को घर-मकान दिलाना वक्त की जरूरत है।

किराये के घरों से होगी मुश्किल आसान

घर का मालिक बनना हमारे देश में ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन बैंकाक, बर्लिन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में 40 से 80 फीसद आबादी किराये के मकानों में रहती है। यही ट्रेंड दुनिया के तकरीबन उन सभी शहरों में है जहां आबादी का ज्यादा बोझ है। इसका एक कारण और है। वह यह कि इनमें से कई मुल्कों में किराये के मकानों की एक स्पष्ट नीति (रेंटल हाउसिंग पॉलिसी) है। इससे न तो लोगों को अपना मकान किराये पर देने में कोई समस्या होती है और न ही किरायेदार को कोई परेशानी। कुछ साल पहले आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने जयतीर्थ राव की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय एक पैनल बनाया था जिसे आवास समस्या का गहराई से अध्ययन कर इसका हल सुझाना था।

इस पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में रेजिडेंशियल रेंटल हाउसिंग एक्ट लाने के साथ आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी के लिए एक पृथक कानून बनाने की सिफारिश की थी। पैनल ने मकानों-दुकानों का मानक किराया बनाने के लिए अदालत अथवा रेंट कंट्रोलर की निगरानी में एक तंत्र विकसित करने की भी सिफारिश की, ताकि किराये बेहिसाब ढंग से नहीं बढ़ाए जा सकें।

किराये के मकान आवास समस्या का वाजिब हल दे सकते हैं, यह साबित होता है हांगकांग के उदाहरण से। वहां की सरकार ने विशेष रूप से किराये के लिए घर बनाए हैं। इन मकान की कीमत प्राइवेट हाउसिंग से काफी कम है और किराया भी काफी कम है। सरकार इसमें काफी सब्सिडी देती है। वहां ऐसी इमारतें 40 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची हैं जिनमें कई हजार लोग एक साथ रह सकते हैं। हांगकांग की तरह सिंगापुर में भी 85 फीसद आबादी ऐसे ही सरकारी मकानों यानी पब्लिक हाउसिंग सोसायटी में रहती है। उनमें रहने को गरीबी या कमतर जीवनशैली का प्रतीक नहीं माना जाता। वहां अलग-अलग आय वर्ग के लिए अलग तरह के फ्लैट हैं। इसी तरह चीन में भी रेंटल हाउसिंग को शुरू हुए एक दशक हो रहा है। वहां की सरकार अलग-अलग तरह से लोगों को घर मुहैया कराती है। नए घर बनाकर, छोड़ी गई प्रॉपर्टी में और पुराने फ्लैटों को किराए पर देकर, जो बहुत कम किराए पर दिए जाते हैं।

ऐसी योजनाओं में वे लोग किराये पर घर ले सकते हैं जो खरीद नहीं सकते। सरकार की तरफ से किराये के लिए मकान बनाकर लोगों को घर देने वाली ऐसी योजनाएं फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में भी लागू हैं। फ्रांस में तो कानून बनाकर यह जरूरी कर दिया गया कि हर शहर में कम से कम 20 फीसद घर कम किराये वाले होने चाहिए।

खरी-खरी

उधारी का परिचक्र

प्रभाशंकर उपाध्याय

मैं, प्रतिदिन सुबह जिस चाय वाले के यहां जाता हूं, वह शांत प्रकृति का व्यक्ति है। लेकिन एक सुबह, जब मैं वहां पहुंचा तो वह एक शख्स से उलझा हुआ था। मुझे देख वह कुछ नरम हुआ-देखिए भाईजान! लोगों में ईमान-धरम नाम की चीज नहीं रह गई है। यह आदमी मेरे यहां कई सालों तक उधारी की चाय पीता रहा। फिर कुछ महीनों की उधारी दाब कर गायब हो गया। आज पकड़ में आया है।

मैंने उस उधारिए से प्रश्न किया-तुम इसका उधार क्यों नहीं चुकाते, भाई? वह दीनता से बोला, इसी मार्केट में मेरी किराने की दुकान थी। लोग उधार पर सामान ले जाते और चुकाने के नाम पर आज-कल करते। धीरे-धीरे उधारी इतनी हो गई कि घाटा खाकर दुकान बंद करनी पड़ी। अब, कोई धंधा सेट हो तो इसका चुकाऊं! मैंने उससे पूछा-किस-किसके पास फंसा है तुम्हारा पैसा? उसने जेब से एक डायरी निकाल कर कुछ नाम बोले। उनमें से तीन-चार लोगों को मैं जानता था। मैंने किराने वाले युवक का मोबाइल नंबर लिया और कहा कि मैं आज ही इन लोगों से मिलता हूं।

मैं मिला। दो लोग तो मेरी बात सुनते ही भभक गए-आप होते कौन हैं हमसे पैसा वसूलने वाले? तीसरे ने कहा कि उसका पैसा भी कुछ लोगों के पास फंसा है, उनसे मिलते ही किराने वाले को देगा। मैंने तीसरे शख्स से उन लोगों के नाम-पते लिए तथा दूसरे दिन उनसे मिलने चला। एक कहीं बाहर गया हुआ था। दूसरे ने मीठा बोलकर, टालू-मिक्चर पिला दिया। तीसरे ने कहा कि वह एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। प्रेस मालिक ने उसका वेतन कुछ महीनों नहीं दिया है। जैसे ही वह देगा, मैं उधारी चुका दूंगा।

मैंने प्रेसवाले का पता लिया और तीसरे दिन उससे मिलने जा पहुंचा। प्रेस मालिक ने कहा मेरा पेमेंट एक प्रकाशक के पास बकाया है। उससे वसूली करा दो तो मैं अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर दूंगा। उसने मुझे प्रकाशक का नाम बताया। मैं उस प्रकाशक से परिचित था। उससे पुस्तकें खरीदता रहता था।

तीन दिन बीत गए थे। उधारी का परिचक्र पूरा होता नहीं दिख रहा था। फिर चौथे दिन प्रकाशक से मिला। मैंने पूरी बात प्रकाशक महोदय को तफसील से समझाई। वह गंभीर हो गया-लोग किताबों का ऑर्डर तो दे देते हैं और हम भेज भी देते हैं किंतु पेमेंट करने में उनकी नानी मरती है। उसने एक लंबी सूची मेरे सामने रखी। मैंने उस सूची पर नजर डाली। सूची में सबसे ऊपर मेरा ही नाम था।

ट्वीट-ट्वीट

इतिहास सच पर आधारित होता है, लेकिन आज इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। जो लोग इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं वे कभी अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है।

अशोक गहलोत@ashokgehlot51

असहिष्णुता ब्रिगेड कुछ और नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम भारतीयों के उत्थान से चिढ़ने वालों का गिरोह है। गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से समानुभूति रखने वाला कोई भी शख्स जानता है कि मोदी सरकार के आधुनिक भारत से बेहतर दौर उनके लिए कोई और नहीं रहा।

विवेक रंजन अग्निहोत्री@vivekagnihotri

कश्मीर को लेकर ट्रंप के शिगूफे पर भारतीय विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही राजनीति को आप दोष नहीं दे सकते, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्तों के किसी भी गंभीर विश्लेषक को ऐसा नहीं लगता कि मोदी ने वास्तव में ट्रंप से मध्यस्थता के लिए कहा होगा।

सदानंद धूमे@dhume

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

पाटनी होंगी नयना देवी की दरारें

दूध का जला अगर छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है तो यह क्रिया अनुभवजन्य है। ये अनुभव कहावतों या लोकोक्तियों में इसीलिए दाखिल हो जाते हैं, ताकि सीख बन सकें। लगभग पूरे भारत और विशेष रूप से उत्तर भारत के आस्था केंद्र नयना देवी परिसर का सेफ्टी ऑडिट करवाया गया था। सेफ्टी ऑडिट से निकला है कि मुख्य मंदिर परिसर की भूमि में दरारें हैं... बस अड्डे से मंदिर तक एक किलोमीटर का पैदल चलने वाला रास्ता भूस्खलन की जद में है... कई बहुमंजिला इमारतें हैं, जो गिर सकती हैं। क्योंकि ऑडिट की रपट है इसलिए प्रशासन ने ऐसे भवनों में श्रद्धालुओं के ठहरने पर रोक भी लगा दी है। सुखद पक्ष यह है कि आमतौर पर कोई घटना घटने के बाद ही सारी रपटें बनती हैं। फिर मजिस्ट्रेट जांच भी हो जाती है, लेकिन यह वास्तव में पूर्व आपदा प्रबंधन है कि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट कुछ बता रही है। बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान ने स्वयं वहां का जायजा लिया है।

नयना देवी मंदिर के साथ अगस्त 2008 का वह हादसा एक बुरी याद की तरह नत्थी है, जिसमें भगदड़ मचने से 145 लोगों की मौत हो गई थी। अब संकट यह है कि इस समस्या के कुछ हल दीर्घकालीन और खर्चीले हैं। लिहाजा एक विकल्प यह भी हो सकता है कि श्रावण नवरात्रों के दौरान बारिश अधिक हो तो यात्रा ही स्थगित कर दी जाए। जो हो, लेकिन समय आ गया है कि दीर्घकालीन और खर्चीले हल की ओर भी बढ़ा जाए। पंजाब ही नहीं, उत्तर भारत के श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश की देवियों में सबसे पहले नयना देवी ही आते हैं। उसके बाद चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, कांगड़ा स्थित ब्रजेश्वरी देवी और फिर चामुंडा धाम। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दरारों को पाटने में जिन क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण रहता है, उनमें से एक है धार्मिक पर्यटन। हिमाचल प्रदेश के मंदिर इतने समर्थ तो हैं ही कि अपना वजूद बचाए रखने के लिए संसाधन जुटा सकें, क्योंकि मामला असंख्य लोगों की आस्था का भी है।

ठन गई है संगठन में : जब घर में संपन्नता आ जाती है तो बड़े लोग धनधान्य से आगे बढ़ कर केवल सद्बुद्धि की मांग ईश्वर से करते हैं। हमेशा अलग पार्टी होने का दावा करने वाली प्रदेश भाजपा के कतिपय घटनाक्रम से कांग्रेस की गंध आ रही है। विधानसभा में 15 विधायक भेजने वाले कांगड़ा जिले में पालमपुर और ज्वालामुखी में संगठन में सब ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा करते हैं कि 15 दिनों में सब सुलटा लिया जाएगा। वास्तव में डबल इंजन तो दौड़ रहा है, लेकिन पहाड़ी प्रदेश के कुछ डिब्बों में गुबार इतना भर गया है कि वहां से शोर आ रहा है और दिशाएं अलग प्रतीत हो रही हैं। पालमपुर से गत विधानसभा चुनाव में उतारी गईं इंदु गोस्वामी ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ई-मेल से भेजा इस्तीफा कई दिनों बाद दिखा तो तत्काल स्वीकार भी हो गया। उनके नजदीकियों का कहना है कि उनके डीओ पर काम नहीं हो रहे थे और एक मंत्री उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

उधर ओबीसी वर्ग से संबद्ध विधायक रमेश धवाला कैबिनेट दर्जे के साथ योजना बार्ड के उपाध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल पेश हुआ और विधायक की शिकायत की। बाद में आए बयानों से आभास मिला कि दोनों के पीछे संगठन है। संगठन मंत्री और रमेश धवाला के बीच के बयान सुन कर ऐसा लगा कि इन दिनों हिमाचल भाजपा 'पार्टी विद ए डिफरेंस' इतनी भी नहीं है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडेय भी याद आए। उनकी विवशता यह है कि वह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। दोनों मामलों में पार्टी की छवि कुछ व्यक्तियों के कारण बहस का केंद्र बन रही है। त्रिदेव सम्मेलन या बूथ तक पहुंचना दूसरी बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल घर की बात घर में रहे तो बेहतर होता है, लेकिन दीवारें एक दूसरे के प्रति साजिश के रंग में हों तो खुला आंगन ही मंच बन जाता है।

धर्मशाला और पच्छाद में उपचुनाव आने वाले हैं। मंत्रिमंडल के दो पद खाली हैं। उन्हें संभवतः उपचुनाव के बाद ही भरा जाएगा। तब तक 'शिमला दूर है' का अस्फुट स्वर तलबगारों का मार्गदर्शन करता रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह प्रदेश से भाजपा के पदाधिकारी ऐसे बयान देने से बचेंगे जिनसे पार्टी की खिल्ली उड़ती हो।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या कश्मीर पर ट्रंप का बयान भारत-अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है?

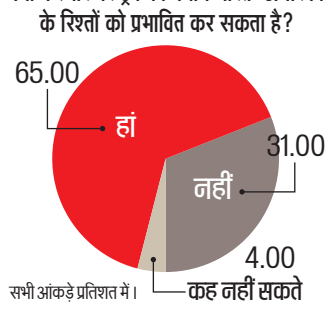

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ट्रंप के बयान पर विपक्ष द्वारा पीएम मोदी से सफाई मांगना सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बकरे की मां कब तलक भला मनाती खैर,
कुमारस्वामी अब करें कर्नाटक की सैर।
कर्नाटक की सैर जुटाओ और विधायक,
मियां बनोगे आप तभी सत्ता के लायक।
नंबर कम तो रोज सहो साथी के नखरे,
होते रहो हलाल हमेशा बनकर बकरे।

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

मुसीबत बनता मधुमेह

आज भारत मधुमेह को लेकर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जरूरत है कि इस पर सरकार अलग से कोई नीति बनाए, जिसमें जांच, दवाओं के लिए कुछ कम तनाव वाली व्यवस्था हो

पंकज चतुर्वेदी
सामाजिक मामलों के जानकार

दो साल पहले के सरकारी आंकड़ों को सही मानें तो उस समय देश में कोई सात करोड़ तीस लाख लोग ऐसे थे जो मधुमेह या डायबीटिज की चपेट में आ चुके थे। अनुमान है कि 2045 तक यह संख्या 13 करोड़ को पार कर जाएगी। मधुमेह वैसे तो खुद में एक बीमारी है, लेकिन इसके कारण शरीर को खोखला होने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे मरीजों की जेब भी खोखली हो रही है और देश के मानव संसाधन की कार्य क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि बीते एक साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के लोगों ने मधुमेह या उससे उपजी बीमारियों पर सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो कि हमारे कुल सालाना बजट का 10 फीसद है। बीते दो दशक के दौरान इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना भी कम चिंता की बात नहीं है।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) की एक रिपोर्ट बताती है कि 2017 में देश के साढ़े पांच करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य पर किया गया व्यय उनकी हैसियत से अधिक व्यय की सीमा से पार रहा। यह संख्या दक्षिण कोरिया या स्पेन की आबादी से अधिक है। इनमें से 60 फीसद यानी तीन करोड़ अस्सी लाख लोग अस्पताल के खर्चों के चलते बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आ गए। पहले मधुमेह, दिल के रोग आदि खाते-पीते या अमीर लोगों की बीमारी माने जाते थे, लेकिन अब ये ग्रामीण, गरीब बस्तियों और तीस साल तक के युवाओं को शिकार बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मधुमेह जीवनशैली बिगड़ने पर उपजने वाला रोग है। फिर भी बेरोजगारी, बेहतर भौतिक सुख जोड़ने की अंधी दौड़ तो खून में शर्करा की मात्रा बढ़ा ही रही हैं, कुपोषण, निम्न गुणवत्ता वाला भोजन भी इसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बड़े कारक हैं। बदलती जीवनशैली कैसे मधुमेह को आमंत्रित करती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेह-लद्दाख है। पहाड़ी इलाका होने के चलते पहले वहां लोग खूब पैदल चलते थे, जीवकोपार्जन के लिए उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ती थी सो लोग ज्यादा बीमार नहीं होते थे। पिछले कुछ दशकों में वहां पर्यटक बढ़े। उनके लिए घर में जल की व्यवस्था वाले पक्के मकान बने। बाहरी दखल के चलते वहां चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल होने लगा और इसी का कुप्रभाव है कि स्थानीय समाज में अब मधुमेह जैसे रोग घर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अपने भोजन के समय, मात्रा, सामग्री में परिवेश एवं शरीर की मांग के मुताबिक सामंजस्य ना बैठा पाने के चलते ही अमीर एवं सर्वसुविधा संपन्न वर्ग के लेग मधुमेह में फंस रहे हैं।

हाल ही में दवा कंपनी सनोफी इंडिया के एक सर्वे में ये डरावने तथ्य सामने आए हैं कि मधुमेह की चपेट में आए लोगों में से 14.4 फीसद को किडनी और 13.1 फीसद को आंखों की रोशनी जाने का रोग लग जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में से 14 फीसद मरीजों के पैरों की धमनियां जवाब दे जाती हैं जिससे उनके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं लगभग 20 फीसद लोग किसी ना किसी तरह की दिल की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। वहीं 6.9 प्रतिशत लोगों को न्यूरो अर्थात तंत्रिका से संबंधित दिक्कतें भी हो जाती हैं। जाहिर है कि मधुमेह अकेले नहीं आता, वह कई अन्य शारीरिक विकारों को साथ लाता है।

यह तथ्य बानगी है कि भारत को रक्त की मिठास बुरी तरह खोखला कर रही है। एक तो अमेरिकी मानक संस्थाओं ने भारत में रक्त में चीनी की मात्रा को कुछ अधिक दर्ज करवाया है जिससे प्री-डायबीटिज वाले भी इसकी दवाओं के फेर में आ जाते हैं। सभी जानते हैं कि एक बार मधुमेह हो जाने पर मरीज को जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं। मधुमेह नियंत्रण के साथ-साथ रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं को लेना आम बात है। जब इतनी दवाएं लेंगे तो पेट में बनने वाले अम्ल के नाश के लिए भी एक दवा जरूरी है। जब अम्ल नाश करना है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कोई मल्टी विटामिन अनिवार्य है। एक साथ इतनी दवाओं के बाद लीवर पर तो असर पड़ेगा ही। प्रत्येक मरीज हर महीने औसतन डेढ़ हजार रुपये की दवा तो लेता ही है अर्थात सालाना 18 हजार रुपये। देश में अभी कुल साढ़े सात करोड़ मरीज होने का अनुमान है। इस तरह यह राशि तेरह लाख पचास हजार करोड़ रुपये होती है। इसमें शुगर मापने वाली मशीनों एवं टेस्ट को तो जोड़ा ही नहीं गया है।

दुर्भाग्य है कि देश के दूरस्थ अंचलों की बात तो छोड़ दें, राजधानी या महानगरों में ही हजारों ऐसे लैब हैं जिनकी जांच की रिपोर्ट संदिग्ध रहती है। फिर भी गंभीर बीमारियों के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था में मधुमेह जैसे रोगों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जरता की बानगी सरकार की सबसे प्रीमियम स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस यानी केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा है। इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों में चालीस फीसद मधुमेह के मरीज हैं और वे हर महीने केवल नियमित दवा लेने जाते हैं।

आज भारत मधुमेह को लेकर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जरूरत है कि इस पर सरकार अलग से कोई नीति बनाए, जिसमें जांच, दवाओं के लिए कुछ कम तनाव वाली व्यवस्था हो। वहीं स्टेम सेल से मधुमेह के स्थायी इलाज का व्यय महज सवा से दो लाख रुपये है, लेकिन सीजीएचएस में यह इलाज शामिल नहीं है। सनद रहे स्टेम सेल थेरेपी में बोन मैरो या एडीपेस से स्टेम सेल लेकर इलाज किया जाता है। इस इलाज की पद्धति को ज्यादा लोकप्रिय और सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाए तो बीमारी से लड़ने में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद सामानों एवं हलवाई की दुकानों की सामग्रियों की कड़ी पड़ताल, देश में योग या व्यायाम को बढ़ावा देने के और अधिक प्रयास युवा आबादी की कार्यक्षमता को बढ़ाने और इस बीमारी से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं।

फिच ने टाटा मोटर्स की रेटिंग घटाई

मुंबई : अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को टाटा मोटर्स की रेटिंग को 'बीबी' से घटाकर 'बीबी-' कर दिया और उसके आउटलुक को भी घटाकर नकारात्मक कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग में कमी करने के लिए कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता में पहले से चल रही कमजोरी और मुक्त नकदी सृजन में अगले दो-तीन साल तक जोखिम बढ़ने का हवाला दिया। फिच ने छह फरवरी को कंपनी की लांग टर्म इशुअर रेटिंग 'बीबी' को नकारात्मक रेटिंग निगरानी पर रखा था। (प्रेट्र)

प्रत्यक्ष कर की वसूली पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान दहाई अंकों में बढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस वर्ष का बजट लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेगी।

— अजय भूषण पांडे, राजस्व सचिव

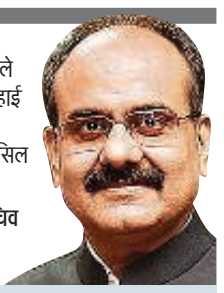

सेंसेक्स	37,847.65 ▼ 135.09	निफ्टी	11,271.30 ▼ 59.75	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 35,870 ▲ ₹150	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 42,300 ▲ ₹350	$ डॉलर	₹ 68.98 ▲ ₹0.04	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 64.31

गन्ने की एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल घोषित

कैबिनेट का फैसला ▶ पिछले साल के बराबर ही रखा गया गन्ना मूल्य, रिकवरी दर 10 फीसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी पेराई सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा कर दी है। चीनी के अधिक उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार ने गन्ना मूल्य को पिछले साल के 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ही कायम रखा है। चीनी मूल्य को स्थिर रखने और किसानों के गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस साल भी बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इस बार यह 40 लाख टन का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में यह फैसला लिया गया है। यह फैसला कृषि मूल्य व लागत आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुरूप है।

कैबिनेट के फैसले की यह जानकारी केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। गन्ने का यह मूल्य 2019-20 के अक्तूबर माह में शुरू होने वाली पेराई सीजन पर लागू होगा। सीएसीपी की सिफारिशों में एफआरपी की यह दर 10 फीसद की रिकवरी दर पर तय किया गया है। इसके अलावा प्रति अंक 2.75 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जबकि बीते पेराई सीजन में 9.5 फीसद की रिकवरी दर को आधार बनाया गया था, जिसके उपर प्रति अंक 2.68 रुपये का अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया था।

जावड़ेकर ने कहा कि एफआरपी की घोषणा में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे उनकी उपज के मूल्य के भुगतान की पूरी गारंटी होगी। एफआरपी का निर्धारण चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत मूल्य तय किया जाता है। इसके तहत मिलें गन्ने का भुगतान करने को बाध्य होंगी।

सरकार के एफआरपी की घोषणा का इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने स्वागत करते हुए कहा कि यही होना चाहिए था। इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि बीते वर्षों में एफआरपी में तेज और भारी बढ़ोतरी की गई थी। यही वजह है कि गन्ना अन्य फसलों के मुकाबले अधिक लाभ देने वाली फसल बना गया। चीनी उत्पादन में गन्ना मूल्य की भागीदारी 70 से 75 फीसद होती है। वर्मा ने बताया कि इससे किसानों का बकाया चुकाने और ताजा मूल्य का भुगतान करने में मदद मिलेगी। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसके ऊपर अपना मूल्य तय करते हैं, जिसे राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) कहा जाता है।

मिलों के लिए किसानों को 15,000 करोड़ रुपये का भुगतान होगा आसान। फाइल

चालीस लाख टन चीनी का बफर स्टॉक

चीनी के बंपर उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार ने मिलों को राहत देने के लिए 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी है। इससे चीनी मिलों के लिए किसानों को गन्ने के मद में 15 हजार करोड़ रुपये का भुगतान आसान हो जाएगा। यह प्रावधान चालू वर्ष 2019-20 के लिए किया गया है।

बीते चीनी वर्ष में अगस्त 2018 में केंद्र सरकार ने चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था, जिस पर 1175 करोड़ रुपये का खर्च आया था। सरकार के इस कदम से चीनी मिलों को नगदी संकट का मुकाबला करने में मदद मिलती है। गन्ना किसानों का भुगतान करने और घरेलू जिंस बाजार में चीनी मूल्य को स्थिर करने में सहूलियत होती है। देश का चीनी उत्पादन चालू वर्ष (अक्टूबर, 2018 - सितंबर, 2019) के दौरान कुल उत्पादन 3.29 करोड़ टन रहने का अनुमान है। जबकि चीनी की घरेलू मांग 2.6 करोड़ टन रहने की संभावना है। इस्मा के अनुसार, इस वर्ष अक्टूबर में नया चीनी सत्र शुरू होने के समय पुरानी चीनी का स्टॉक रिकार्ड 1.45 करोड़ टन पर रहेगा। जबकि उस समय केवल 50 लाख टन चीनी की जरूरत होती है।

लक्ष्मी मित्तल का भाई गिरफ्तार 45 वर्षों की सजा संभव

सराजेवो, एएफपी : विश्व विख्यात इस्पात उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई प्रमोद मित्तल को बोस्निया में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रमोद मित्तल धोखाधड़ी और शक्ति का दुरुपयोग करने के मामले में संदिग्ध है। यदि वह दोषी पाया जाता है, तो उसे 45 वर्षों तक के जेल की सजा हो सकती है।

यह मामला पूर्वोत्तर के शहर लुकावाक के एक कोकिंग संयंत्र के संचालन से जुड़ा हुआ है। प्रमोद मित्तल 2003 से इस संयंत्र के सह-प्रबंधक हैं। प्रोसिक्युटर काजिम सेराल्टिक ने कहा कि पुलिस ने प्रोसिक्युटर के आदेश पर कार्रवाई की और जीआइकेआइएल के सुपरवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट प्रमोद मित्तल को गिरफ्तार किया। जीआइकेआइएल की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका प्रबंधन प्रमोद मित्तल की ग्लोबल स्टील होल्डिंग्स और एक स्थानीय कंपनी केएचके करती है। लुकावाक के कोकिंग संयंत्र में 1,000 कर्मचारी काम करते हैं।

कंपनी के दो अन्य अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें महाप्रबंधक परमेश भट्टाचार्य और सुपरवाइजरी बोर्ड का एक अन्य सदस्य शामिल हैं। प्रोसिक्युटर ने कहा कि उन पर संगठित अपराध और खास तौर से शक्ति के दुरुपयोग और आर्थिक अपराध का संदेह है। सेराल्टिक ने कहा कि दोषी पाए जाने पर संदिग्धों को 45 साल तक के जेल की सजा हो सकती है। एक चौथे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भी वारंट जारी किया गया है। माना जाता है कि वह भी संगठित अपराध करने वाले इस समूह का सदस्य है। संदिग्धों को बुधवार को एक न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि संदिग्धों ने 28 लाख डॉलर (करीब 19.3 करोड़ रुपये) का गबन किया है।

गौरतलब है कि आर्सेलरमित्तल के सीईओ लक्ष्मी मित्तल ने अपने भाई प्रमोद मित्तल को भारत में कंगाल होने से बचाया था। प्रमोद मित्तल के पास बाल्कन क्षेत्र में कई कंपनियां हैं।

प्रमोद मित्तल। फाइल

ऑटो सेक्टर में लाखों नौकरियों पर तलवार

बदहाली ▶ मंदी जारी रही, तो कंपोनेंट उद्योग को 10 लाख नौकरियां जाने की आशंका

उद्योग ने रखी जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18 फीसद करने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही मंदी का खतरा इस उद्योग के लाखों कामगारों की तरफ बढ़ रहा है। ऑटोमोटिव कंपनोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन (एक्मा) का मानना है कि मंदी जारी रही तो 10 लाख नौकरियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए एसोसिएशन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 18 फीसद पर लाने की सिफारिश की है।

पिछले 10 महीने से ऑटो उद्योग की बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे कंपोनेंट उद्योग भी प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम वेंकटरमानी ने उद्योग के सालाना प्रदर्शन पर आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा, 'कंपोनेंट उद्योग की रफ्तार ऑटो कंपनियों की वृद्धि दर पर ही निर्भर करती है। वाहनों के उत्पादन में करीब 15-20 फीसद की कमी ने संकट खड़ा कर दिया है। यह स्थिति आगे बनी रही तो उद्योग में छंटनी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।' वेंकटरमानी ने कहा कि कुछ कंपनियों में तो छंटनी की शुरुआत भी हो चुकी है। वेंकटरमानी ने कहा कि मांग में कमी, बीएस-4 से बीएस-6 में तब्दील करने पर हुए निवेश, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्पष्ट रोडमैप का अभाव ने भविष्य में आने वाले निवेश पर रोक लगा दी है। उनका कहना था कि उद्योग को तत्काल सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार को समूचे ऑटो सेक्टर में जीएसटी की एकसमान 18 फीसद की दर को लागू कर देना चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक करीब 70 फीसद ऑटो कंपोनेंट 18 फीसद जीएसटी दर के दायरे में आते हैं। जबकि शेष 30 फीसद उत्पादों पर 28 फीसद दर लागू होती है। लेकिन इन पर 15 फीसद तक का सेस भी लगता है।

एसोसिएशन के महानिदेशक विनी मेहता ने कहा कि नीति आयोग की तरफ से ऑटो उद्योग को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने के आक्रामक अभियान ने ऑटो उद्योग में हलचल मचा दी है। जबकि उद्योग ने फेम-2 स्कीम को तय करने में भारी उद्योग मंत्रालय के साथ हुई मंत्रणा में पूरा योगदान किया है। मेहता ने कहा कि सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में बढ़ने के लिए एक स्थिर रोडमैप बनाने पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि नीति आयोग ने साल 2023 तक तिपहिया वाहन उद्योग और 2025 तक दोपहिया वाहन उद्योग को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का प्रस्ताव किया है।

ऐसा रहा है प्रदर्शन : वित्त वर्ष 2018-19 में ऑटो कंपोनेंट उद्योग में वृद्धि की दर 14.5 फीसद रही। जबकि उससे पिछले वित्त वर्ष में उद्योग की बिक्री में 17.1 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2018-19 की दूसरी छमाही से उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट आनी शुरू हुई।

करीब 50 लाख कर्मचारी हैं कंपोनेंट उद्योग में, 70 फीसद ठेके पर। फाइल

छंटनी की वजह

कंपोनेंट उद्योग में 70 फीसद श्रमिक ठेका व्यवस्था में काम करते हैं। इसलिए जब भी मांग में कमी आती है और ऑटो कंपनियां उत्पादन कम करती हैं तो कंपोनेंट उद्योग में भी कर्मचारियों की संख्या में कमी आती है। विभिन्न प्रकार के वाहन बनाने वाली ऑटो कंपनियों को कलपुर्जे और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने वाले कंपोनेंट उद्योग में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं।

एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को चुकाने होंगे 3,050 करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ जियो मामले में डीसीसी ने इन कंपनियों पर जुर्माना रखा कायम

▶ तीनों कंपनियों पर था अपने नेटवर्क से जियो का कॉल पास नहीं होने देने का आरोप

दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च निर्णायक संस्था डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने बुधवार को भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के ट्राई के फैसले को मंजूरी दे दी। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, 'डीसीसी ने एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने की टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब डीसीसी अपनी यही सिफारिश सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।'

यह था मामला : दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अक्टूबर, 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी देने से इंकार के दंडस्वरूप एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने की सिफारिश की थी। एयरटेल और वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया था। इनमें वोडाफोन और आइडिया का अब आपस में विलय हो चुका है। उस वक्त ट्राई ने इन कंपनियों के लाइसेंस रद करने की सिफारिश इसलिए नहीं की थी कि इससे ग्राहकों के लिए बड़ी असुविधा हो सकती थी। ट्राई की उक्त सिफारिश जियो की शिकायत के बाद सामने आई थी। जियो ने कहा था कि उक्त तीनो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा पर्याप्त पीआइओ (प्वाइंट आफ इंटरकनेक्ट) नहीं दिए जाने के कारण उसकी 75 फीसद कॉल्स फेल हो रही हैं।

पिछले महीने ही ले लिया था फैसला : डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने पिछले महीने ही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाए जाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन बाद में दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा हालत को देखते हुए उसने जुर्माने की राशि के बारे में एक बार फिर से ट्राई की राय लेने का फैसला किया था। परंतु ट्राई ने इस बार भी अपनी पुरानी राय दोहराई और 3,050 करोड़ के जुर्माने को उचित ठहराया। उसका कहना था कि ट्राई एक्ट के अनुसार वह अपनी सिफारिश में संशोधन नहीं कर सकता। भारती एयरटेल ने डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन के फैसले पर निराशा प्रकट करते हुए कहा है कि इस मनमाने कदम से दूरसंचार कंपनियों पर वित्तीय बोझ और बढ़ने के साथ सरकार के डिजिटल इंडिया के विजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

टेलीकॉम नियामक ट्राई ने जियो के आरोपों को सही पाया था। प्रतीकात्मक

आइडीबीआइ बैंक के वित्तीय स्थायित्व पर सवाल

▶ इंडिया रेटिंग्स ने बैंक का आउटलुक नकारात्मक किया

मुंबई, एएनआइ : इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने आइडीबीआइ बैंक की लांग टर्म इशुअर रेटिंग को संशोधित कर इंड ए और शॉर्ट टर्म इशुअर रेटिंग को इंड ए1 कर दिया। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग आउटलुक को 'नकारात्मक रेटिंग निगरानी' से बदलकर 'नकारात्मक' कर दिया। रेटिंग आउटलुक में कटौती बैंक के वित्तीय स्थायित्व पर गंभीर सवाल खड़ा करती है।

कुछ दिनों पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आइडीबीआइ बैंक के 743 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में छानबीन की थी। इस मामले में एक आरोपित ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कथित तौर पर फर्जी परियोजना तैयार कर लोन राशि का गबन गबन किया था।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि निगेटिव आउटलुक इस संभावना की वजह से दिया गया है कि बैंक को 2020-21 में बड़े पैमाने पर शेयर पूंजी निवेश की जरूरत हो सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने हालांकि निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन वह कितना निवेश कर सकती है और कब तक करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। इस आउटलुक से यह भी पता चलता है कि बैंक अपनी संपत्ति में समुचित बढ़ोतरी करने में अक्षम है।

नकारात्मक आउटलुक से रेटिंग एजेंसी की इस आशंका का भी पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से आइडीबीआइ बैंक जल्दी बाहर नहीं निकलने जा रहा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आइडीबीआइ बैंक सर्वाधिक ग्रॉस एनपीए वाले समकक्ष बैंकों में शामिल है। बैंक की स्टैंडअलोन क्षमता में गिरावट दर्ज की जा रही है। बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति में इसकी हिस्सेदारी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

कर चोरों के साथ सख्ती से निपटें, चुकाने वालों को सुविधा मुहैया कराएं अधिकारी : सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टैक्स चोरी करने वालों और व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने वालों के साथ सख्ती से निपटें। उन्होंने साथ ही कहा कि अधिकारियों को ईमानदार करदाताओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए राजस्व विभाग की तीन जांच शाखाओं को आपस में सूचना साझा करने का भी निर्देश दिया। सीतारमण ने करदाताओं से कहा कि उन्हें टैक्स भुगतान को सजा सजा के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में देखना चाहिए।

सीतारमण इनकम टैक्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप करदाताओं की संख्या को वर्तमान आठ करोड़ से बढ़ाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आम बजट 2019-20 में चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर वसूली के लिए तय किए गए 13.35 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि पिछले पांच साल में टैक्स विभाग ने वसूली को दोगुना कर लिया है।

डाटा एनालिसिस व रिस्क प्रोफाइलिंग का होगा उपयोग

नई दिल्ली : राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग आक्रामक तौर तरीकों का नहीं, बल्कि डाटा माइनिंग और रिस्क प्रोफाइलिंग का उपयोग करेगा। उन्होंने प्रत्यक्ष कर वसूली का लक्ष्य हासिल हो जाने की भी उम्मीद जताई।

▶ वित्त मंत्री ने ईमानदार करदाताओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करने का भी अधिकारियों को दिया निर्देश

▶ टैक्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं मंत्री

टैक्स भुगतान के लिए खुशनुमा माहौल बने : सीबीडीटी

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी ने 159वें इनकम टैक्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि टैक्स अधिकारियों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि एक साधारण आदमी को टैक्स का भुगतान कर खुशी मिले।

हवाई अड्डों के निजीकरण पर सरकार ने साफ की स्थिति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सुरक्षा, कस्टम और एयर नेवीगेशन, इमिग्रेशन रहेंगे सरकार के पास

हवाई अड्डों के निजीकरण पर खड़े किए जा रहे सवालों पर सरकार ने बुधवार को सफाई दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस फैसले के बाद भी हवाई अड्डों की सुरक्षा, कस्टम, एयर नेविगेशन और इमिग्रेशन का काम पहले की तरह सरकार के पास ही रहेगा। वैसे भी यह कोई नया कदम नहीं है। दिल्ली और मुंबई में पहले से यह व्यवस्था लागू है। वहां सफलता के बाद ही इसे दूसरे हवाई अड्डों पर भी आजमाने का फैसला लिया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर कालिता के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस सांसद के सवाल में हवाई अड्डों को बेचे जाने जैसी भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस फैसले से हवाई अड्डों की सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम् और मंगलुरु हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने का फैसला लिया है। इनमें अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु में इस पर काम भी शुरू हो गया है, जबकि जयपुर और गुवाहाटी में जमीन का कुछ मामला है। जिसे लेकर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

वहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद एके एंटनी के सवाल के जवाब में बताया कि केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के निजीकरण को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है। केरल सरकार ने इसे खुद चलाने की मांग की है।

निराशा

सेंसेक्स 135 .09 अंकों की गिरावट के साथ 37,847 .65 पर बंद, निफ्टी 59 .75 अंक लुढ़ककर 11,271 .30 पर स्थिर हुआ

विकास अनुमान घटने से लगातार पांचवें सत्र में गिरा बाजार

मुंबई, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा देश का विकास अनुमान घटाए जाने के बाद बुधवार को देश के शेयर बाजारों में लगातार पांचवें सत्र में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 135.09 अंकों की गिरावट के साथ 37,847.65 पर बंद हुआ, जो दो महीने से अधिक का निचला स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 59.75 अंकों की गिरावट के साथ 11,271.30 पर बंद हुआ।

गत पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,049.81 अंक टूट चुका है। इस दौरान निफ्टी में 325.60 अंकों की गिरावट आ चुकी है। आइएमएफ ने मंगलवार को चालू वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 0.3 फीसद घटाकर सात फीसद और अगले वर्ष के विकास अनुमान को भी 0.3 फीसद घटाकर 7.2 फीसद कर दिया।

सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 3.87 फीसद गिरावट रही। बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील भी तीन फीसद से अधिक लुढ़के। दूसरी ओर एशियन पेंट्स में सर्वाधिक 3.87 फीसद तेजी रही। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ में 17.90 फीसद बढ़ोतरी दर्ज की है। एचडीएफसी और हिंदुस्तान यूनीलिवर (एचयूएल) दो फीसद से अधिक उछले। एचयूएल ने जून तिमाही के कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ में 14.40 फीसद बढ़ोतरी दर्ज की है।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के धातु सेक्टर में सर्वाधिक 2.48 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर एक मात्र तेज खपत उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) सेक्टर में 0.17 फीसद तेजी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 1.48 फीसद और स्मॉलकैप में 1.23 फीसद गिरावट रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती की आशंका को देख निवेशकों ने पूंजी निकासी का रास्ता अपनाया। टैक्स संबंधी चिंता से बाजार में पहले से ही गिरावट जारी थी। आइएमएफ द्वारा विकास अनुमान घटाए जाने से बाजार में गिरावट को और बल मिला।

बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने 2,607.97 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने 2,625.10 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। एशियाई बाजारों में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंगसेंग और निक्केई में तेजी और कोस्पी में गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुझान देखा गया।

लगातार पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स लगा चुका है 1,000 से ज्यादा अंकों का गोता। फाइल

एफल इंडिया का आइपीओ सोमवार को आएगा

नई दिल्ली : मोबाइल मार्केटिंग कंपनी एफल इंडिया का 459 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) सोमवार को आएगा। इस ऑफर का प्राइस बैंड प्रति शेयर 740-745 रुपये रखा गया है। इश्यू बुधवार का बंद होगा।

मजबूत विदेशी रुझान के बीच सोना-चांदी उछले

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों में दिखे मजबूत रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 150 रुपये उछलकर 35,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं द्वारा खरीदारी बढ़ाए जाने से चांदी भी 350 रुपये मजबूत होकर 42,300 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई।

विश्लेषकों ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के कारण निवेशकों ने सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों को अधिक तरजीह दी। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने में मजबूती दिखी। स्थानीय ज्वेलर्स द्वारा खरीदारी बढ़ाए जाने से भी सोने में तेजी को बल मिला। न्यूयॉर्क में सोने में 1,425.40 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 150 रुपये उछलकर 35,870 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 35,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी भी 100 रुपये उछलकर 27,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर आ गई। मंगलवार को सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम कमजोर हुआ था।

चांदी हाजिर 350 रुपये मजबूत होकर 42,300 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। वीकली डिलीवरी 511 रुपये चढ़कर 41,546 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये बढ़कर 85,000 रुपये खरीद और 86,000 रुपये बिक्री के स्तर पर पहुंच गई।

शेयर बाजार सुस्त तो सोना चुस्त। प्रतीकात्मक

72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है गूगल पर नौ साल पुराने निजता के उल्लंघन के मामले में। वर्ष 2010 में, गूगल 'वाई-स्पाई' मामले को लेकर विवाद में आ गया था। इस मामले में उसकी स्ट्रीट व्यू कारों को लोगों के ईमेल, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत डाटा को असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क से निकालते पाया गया था।

बोरिस जॉनसन बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

संभाला पदभार ▶ कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष ने देश को ताकतवर बनाने का संकल्प जताया

31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलगाव प्रक्रिया को किया जाना है पूरा

बोरिस जॉनसन। रायटर

लंदन के 10 डाउनस्ट्रीट में भाषण देने के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करतीं ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री टेरीजा मे और उनके पति फिलिप। एएफपी

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में बुधवार को बोरिस जॉनसन (55) ने प्रधानमंत्री पद संभाल लिया। मंगलवार को कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों ने पार्टी के नए नेता के रूप में बड़े बहुमत से उनका चुनाव किया था। बोरिस ने जेरेमी हंट को पराजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस को नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी है। बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले टेरीजा मे ने बकिंघम पैलेस जाकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा, इसके बाद बोरिस जॉनसन ने महारानी से मुलाकात की। बोरिस ने महारानी के समक्ष घुटनों पर बैठकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, संसद में समर्थन की हामी भरने के बाद महारानी ने उनका दावा स्वीकार कर लिया और वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। बोरिस अब अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे।

पीएम के रूप में अपने पहले उद्बोधन में जॉनसन ने कहा, ब्रेक्जिट प्रक्रिया हर हाल में 31 अक्टूबर को पूरी होगी। वह देश को ताकतवर बनाएंगे। टेरीजा तीन बार ब्रेक्जिट से संबंधित प्रस्ताव लेकर संसद में गईं लेकिन हर बार उन्हें वहां विफलता मिली।

मंत्री बन सकता है भारतीय : हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय मूल के दिग्गज सांसद जीतेश गढ़िया ने उम्मीद जताई है कि बॉरिस जॉनसन अपने मंत्रिमंडल में कम से कम एक भारतीय को अवश्य मौका देंगे। सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी में जो सांसद मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं उनमें प्रीति पटेल, ऋषि सुनक और आलोक शर्मा प्रमुख हैं। गढ़िया ने कहा, बोरिस अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए ब्रिटेन में प्रतिभाओं को आमंत्रित करने के लिए आव्रजन नियमों में सुधार करेंगे। जाहिर है इससे भारतीय प्रतिभाओं के लिए उम्मीद के नए द्वार खुलेंगे।

बोरिस का भारत से जुड़ाव: न्यूयॉर्क में पैदा हुए लेकिन ब्रिटेन में बसे बोरिस जॉनसन का भारत से भी जुड़ाव रहा है। उनकी पूर्व पत्नी मरीना व्हीलर की मां भारतीय मूल की थीं। मरीना से जॉनसन का 25 साल का वैवाहिक जीवन 2018 में ही खत्म हुआ है। उससे पहले जॉनसन कई बार भारत आए और रिश्तेदारों के घरों में रहे। जॉनसन पत्रकार, लंदन के मेयर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं।

ब्रेक्जिट पर बोरिस की चतुराई : ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की ओर से ब्रेक्जिट मामले के मुख्य वार्ताकार माइकेल बर्नियर ने कहा है कि वह बोरिस जॉनसन के साथ काम कर चुके हैं। इसलिए उन्हें पता है कि वह चतुर हैं। इसका असर ब्रेक्जिट प्रक्रिया पर भी पड़ना तय है। ब्रेक्जिट के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है। हमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस किस तरह के ब्रेक्जिट को प्रमुखता देते हैं। वह यूरोपीय यूनियन को शर्तों के साथ छोड़ते हैं या बिना शर्तों के।

वैश्विक मुद्दों पर क्या है जॉनसन की राय

लंदन, रायटर : ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष और नव नियुक्त प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना पदभार संभाल लिया है। बोरिस जॉनसन अपनी शख्सियत और विवादों में घिरने के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। टेरीजा मे के कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुके जॉनसन ने पत्रकार, मेयर, सांसद, और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सफर तय किया है। पीएम बनने के बाद स्वाभाविक रूप से जॉनसन के सामने पहले से ही कई चुनौतियां खड़ी हैं। आइए जानते हैं कि हाल-फिलहाल में दुनियाभर में घटित हुई घटनाओं और विभिन्न मुद्दों पर बोरिस जॉनसन की क्या राय है।

ईरान : 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते पर जॉनसन ने कहा है कि यह समझौता तेजी से कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे बनाए रखने के लिए नए तरीकों की आवश्यकता है। परमाणु हथियारों की होड़ न करने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इससे पहले बोरिस जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरह कठोर कदम उठाने को सही ठहराते रहे हैं। उन्होंने कहा था, 'मैं नहीं समझता तेहरान के लोग सुलझे हुए हैं, वे खतरनाक और जटिल लोग हैं।' हालांकि, अब उनका कहना है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में वह ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई को गलत मानते हैं।

अमेरिका के साथ संबंध

जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। ब्रिटिश मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक, जल्द ही बोरिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीते दिनों ब्रिटिश राजदूत किम डारोच द्वारा ट्रंप प्रशासन को अयोग्य बताए जाने की खबर लीक होने के बाद भी बोरिस ने खुल कर अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ह्वाइट हाउस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। यह और भी महत्वपूर्ण है कि हम करीबी मित्र होने के साथ-साथ करीबी साझेदार भी हैं।

हुआवे: ब्रिटेन के 5जी टेलीकॉम नेटवर्क में चीन की कंपनी हुआवे को शामिल करने का निर्णय मई में वापस ले लिया गया था। बीते दिनों अमेरिका ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि हुआवे चीन की सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इस मुद्दे पर जॉनसन का कहना है कि दूसरे देशों का निवेश फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप मुझसे यह नहीं चाहेंगे कि हम अपने खुफिया विभाग के साथ समझौता करें।

हांगकांग : हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण बिल और चीन के विरोध में बीते कई महीनों से स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ब्रिटेन के नव-नियुक्त प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा 'मैं प्रदर्शनकारियों का समर्थन करता हूं और मैं खुशी से उनके लिए बोलूंगा, उनके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं, बीजिंग के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि एक देश में दो स्तरीय तंत्र काम करता है और इसे अलग नहीं किया जा सकता।'

अर्थव्यवस्था : बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्टर में अरबों पाउंड खर्च करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया है कि वे शिक्षा, परिवहन और सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड पर खर्च में वृद्धि करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे पास अभी पर्याप्त पैसा है, फिर भी कुछ उद्देश्यों को पूरा करने लिए यदि कर्ज लेने की जरूरत भी पड़ती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी राजकोषीय जिम्मेदारियों का निर्वहन भी पूरी तरह करेंगे। जॉनसन को वित्तीय सेवाओं का चैंपियन माना जाता है। जब वह लंदन के मेयर थे तो उनकी नीतियों ने सब को कायल बनाया था। हालांकि, अब उनके सामने कंपनियों के साथ दोबारा संबंध स्थापित करने की चुनौती भी है।

14 दिन के लिए बढ़ी हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी सईद को गुजरांवाला स्थित आतंक रोधी न्यायालय (एटीसी) ने 17 जुलाई को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज था। उसकी अवधि पूरी होने पर बुधवार को फिर उसे एटीसी के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही पंजाब प्रांत के आतंक विरोधी विभाग (सीटीडी) को भी मामले में सात अगस्त तक पूरी चार्जशीज पेश करने को भी कहा है।

बता दें कि सीटीडी ने तीन जुलाई को सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत लेने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। उसी दिन उसे आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष भी पेश कर दिया गया था। भारत ने हाफिज की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का नाटक बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'यह पहली बार नहीं है जब हाफिज की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि यह बस नाटक है या उसे सजा होगी।'

▶ बुधवार को एटीसी के सामने पेश हुआ मुंबई हमले का मास्टरमाइंड

हाफिज सईद। फाइल

7 बार हो चुका है गिरफ्तार : बीते दिनों एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इन आतंकी संगठनों की मदद करती हैं। पाकिस्तान अब तक 7 बार 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार कर चुका है, लेकिन उसे हर बार छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा की इस बार पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाता है।

श्रीलंका ने फिर शुरू की मुफ्त वीजा की सुविधा, भारत भी शामिल

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका ने देश के पर्यटन क्षेत्र को फिर पटरी पर लाने के लिए आगमन पर मुफ्त वीजा सेवा को फिर शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा एक अगस्त से प्रभावी होगी। इस बार इस सेवा का लाभ भारत और चीन के पर्यटकों को भी मिलेगा। अप्रैल में ईस्टर के दिन हुए आतंकी हमले के बाद श्रीलंका ने इस सेवा को रोक दिया था।

उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में नौ आत्मघाती हमलावरों ने तीन चर्च और कई लक्जरी होटल पर हमले को अंजाम दिया था। इसमें 258 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद श्रीलंका ने 39 देशों को दी जाने वाली आगमन पर मुफ्त वीजा सेवा को बंद कर दिया था। श्रीलंका ने बुधवार को जानकारी दी कि इस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। यह एक अगस्त से प्रभावी होगी। समाचार पोर्टल श्रीलंका मिरर ने पर्यटन एवं ईसाई मामलों के मंत्री जॉन अमारातुंगे के हवाले से कहा है कि 39 देशों को दी जाने वाली इस सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। अब इस सेवा का लाभ भारत और चीन के पर्यटकों को भी मिलेगा। पहले भारत और चीन के पर्यटकों को इस सेवा का लाभ नहीं मिलता था।

आतंकवाद पर घर में घिरे इमरान विपक्ष ने बताया 'आदतन झूठा'

लाहौर, प्रेट्र : अमेरिका दौरे के दौरान आतंकवाद पर दिए बयान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान घर में घिर गए हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान को 'आदतन झूठा' और आतंकवादियों का समर्थक बताया है। विपक्ष ने यह भी कहा कि इमरान ने आतंकवाद के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की हर संभव कोशिश की।

गौरतलब है कि इमरान ने मंगलवार को अमेरिका में 'कांग्रेसनल पाकिस्तान कॉकस' की अध्यक्ष शीला जैक्सन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया था कि पाक की पिछली सरकारों ने अमेरिका को आतंकवाद को लेकर सच नहीं बताया था।

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) की महासचिव नफीसा शाह ने बयान जारी कर कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों ने इमरान खान को 'बिना दाढ़ी वाला तालिबान खान' करार दिया है। नफीसा ने कहा, 'चयनित पीएम इमरान खान न सिर्फ भ्रष्ट हैं बल्कि आर्तकियों के समर्थक हैं। इमरान जितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, वह अभ्यास से आता है और इमरान दशकों से यह कर रहे हैं। पीपीपी महासचिव ने कहा, 'इमरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जबकि सच्चाई यह है कि वह पिछले 20 सालों में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रचने वालों के प्यादे रहे हैं। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा, 'अमेरिका में इमरान नियाजी ने मीडिया पर नियंत्रण की बात कर, अपनी तानाशाही मानसिकता का खुलासा किया है। वह झूठ बोल रहे हैं कि देश में मीडिया आजाद है, जबकि मीडिया सबसे बुरा सेंसरशिप झेल रहा है।'

▶ विपक्ष ने पाक पीएम को आतंकवादियों का समर्थक करार दिया

▶ कहा, इमरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की

इमरान खान। एएफपी

डोकलाम विवाद खत्म करने के लिए अच्छा माहौल बनाया : चीन

बीजिंग, प्रेट्र : चीन की सेना भारत से लगने वाली अपनी सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। 2017 में डोकलाम में भारत के साथ बने गतिरोध को दूर करने के लिए भी उसने सकारात्मक वातावरण बनाया था। चीनी सेना ने यह बात चाइनाज डिफेंस इन न्यू एरा (नए युग में चीन की सुरक्षा) शीर्षक से जारी श्वेत पत्र में कही है।

श्वेत पत्र में भारत, अमेरिका, रूस और अन्य देशों के सैन्य विस्तार से तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की गई है। भारत-चीन सीमा के बारे में श्वेत पत्र में कहा गया है कि वहां पर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चीनी सेना लगातार प्रयास कर रही है। उसने डोकलाम विवाद को भी खत्म करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया था। डोकलाम में भूटान के क्षेत्र में चीन के सड़क बनाने के विरोध में भारत ने इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी थी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच निशस्त्र संघर्ष भी हुआ था। दोनों देशों के सैनिक महज 100 मीटर की दूरी पर करीब ढाई महीने तक जमे रहे थे। इस सड़क के निर्माण से उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली संकरी सी भारतीय सड़क की सुरक्षा खतरे में पड़ने की आशंका थी। गतिरोध के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अंततः चीन ने इलाके में सड़क निर्माण न करने का वचन दिया, इसके बाद भारतीय सेना मौके से हटी। इसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने संबंध को ज्यादा विश्वसनीय बनाने का फैसला किया। इतिहास में पहली बार भारत और चीन की अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। 2018 में वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग मिले, दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों के विकास की नई रूपरेखा तैयार की। अनौपचारिक मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति चिनफिंग इस वर्ष के अंत में भारत आएंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत और चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है और कई स्थानों पर दोनों देशों के बीच विवाद है। इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने के लिए दोनों देश 21 बार बात कर चुके हैं। श्वेत पत्र में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर सैन्य स्पर्द्धा बढ़ी है। ऐसे में नई चुनौतियों के हिसाब से सेना के चहुंमुखी विकास की आवश्यकता है। चीन इसके मद्देनजर कार्य कर रहा है। इसके लिए सेना को युद्ध के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है। अमेरिका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वह अपनी सेना को तकनीक और संस्थागत तरीके से बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है जिससे दुनिया पर उसका अधिपत्य बना रह सके। बाकी देशों की सेनाएं भी तकनीक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

▶ गतिरोध के दो साल बाद चीनी सेना ने जारी किया श्वेत पत्र

▶ भूटान के क्षेत्र में चीन के सड़क बनाने के विरोध में भारत ने तैनात की थी सेना

थाइलैंड में सैन्य ठिकाने पर हमले में चार की मौत

थाइलैंड में पत्तानी प्रांत के सुदूर इलाके में सैन्य चौकी पर संदिग्ध मुस्लिम विद्रोहियों के हमले के बाद मौके पर छानबीन में जुटे सुरक्षाकर्मी। रायटर

पत्तानी, एएफपी: हिंसा प्रभावित थाइलैंड के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार देर रात एक सैन्य ठिकाने पर हमले में चार लोगों की मौत हो गई। पत्तानी प्रांत के सुदूर इलाके में सैन्य चौकी पर हमले में सेना के एक सार्जेंट मेजर की भी मौत हुई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि देर रात संदिग्ध मुस्लिम विद्रोहियों ने चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया और आग लगा दी। हमलावर पांच बंदूकें भी चुरा ले गए। थाइलैंड का मुस्लिम बहुल दक्षिणी भाग पिछले 15 वर्षों से सुरक्षाकर्मियों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच संघर्ष झेल रहा है। इस हिस्से में मुस्लिम स्वायत्तता की मांग पर अड़े हैं। इन्हीं संघर्षों के बीच चार दिन पहले सेना ने एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा था सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में अभी तक सात हजार से अधिक की जान जा चुकी है।

चीन में भूस्खलन से 14 की मौत, 42 लापता...

चीन के गुइझोउ प्रांत में भूस्खलन की दो घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग लापता हैं। प्रशासन के मुताबिक मंगलवार की रात इस प्रांत के शुइचेंग काउंटी में भूस्खलन से 21 घर जमींदोज हो गए। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 11 लोगों को बचाया गया है। अभी 36 लोग लापता हैं। भूस्खलन की वजह मूसलधार बारिश मानी जा रही है। लगातार बारिश और पहाड़ की तीव्र ढाल से राहत-बचाव अभियान में भी बाधा आ रही है। वहीं गुइझोउक के हेझांग काउंटी में मंगलवार दोपहर बाद हुए भूस्खलन से एक शख्स की जान चली गई जबकि छह लापता हैं। एपी

जापान में एक और परमाणु संयंत्र जल्द किया जाएगा बंद

टोक्यो, रायटर : जापान में जल्द ही एक और परमाणु संयंत्र बंद कर दिया जाएगा। बिजली उत्पादक कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर (टेपको) फुकुशिमा दायनी न्यूक्लियर स्टेशन को बंद करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में जुलाई के आखिर तक आधिकारिक घोषणा हो सकती है। बता दें कि यह स्टेशन फुकुशिमा दाइची संयंत्र से थोड़ी ही दूरी पर है। 2011 में भूकंप के बाद आई सुनामी के कारण दाइची संयंत्र में भारी तबाही हुई थी जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था।

2011 की आपदा से दायनी स्टेशन के चार रिएक्टर भी प्रभावित हुए थे। बाद में उन्हें चालू कर लिया गया था। लेकिन फुकुशिमा की सरकार कई बार इस संयंत्र को बंद करने की मांग कर चुकी है। बीते साल जून में टेपको ने दायनी स्टेशन का रिएक्टर बंद करने की मंशा जताई थी। इस संबंध में फैसला लेने से पहले कंपनी के अध्यक्ष तोमाकी कोबायाकावा फुकुशिमा जाएंगे। दायनी स्टेशन बंद होने के बाद टेपको के पास केवल काशीबजाकी-करिवा परमाणु संयंत्र ही बच जाएगा। वहीं पूरे जापान में 33 रिएक्टर सक्रिय रह जाएंगे जबकि 2011 से पहले यहां 54 स्टेशन थे।

चीन ने दी हांगकांग में सेना तैनात करने की धमकी

बीजिंग, प्रेट्र : हांगकांग में एक महीने से भी लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए चीन ने अपने सैनिक तैनात करने की धमकी दी है। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए चीनी सेना ने कहा कि स्थानीय सरकार के आग्रह पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह हांगकांग में अपने सैनिक तैनात कर सकती है।

दरअसल, हांगकांग की नेता कैरी लाम ने प्रत्यर्पण कानून प्रस्तावित किया था। इसके तहत संदिग्धों व अपराधियों को मुकदमे के लिए चीन में प्रत्यर्पित किया जाना था। इस कानून को हांगकांग की स्वायत्तता पर खतरा माना जा रहा है। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग इस शर्त पर सौंपा था कि 'वन कंट्री, टू सिस्टम' में उसकी स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जून के मध्य में लाखों लोग प्रस्तावित कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए थे। इसके दबाव में लाम को बिल निलंबित करना पड़ा था। हाल ही में लाम ने उस बिल के निरस्त होने का दावा किया था। लेकिन प्रदर्शनकारी बिल को आधिकारिक तौर पर वापस लेने और लाम के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। बीते रविवार प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग स्थित चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के चिह्न पर काला रंग पोत दिया था। चीन इससे भड़क गया है। चीनी सेना के प्रवक्ता वु कियान ने कहा, 'हांगकांग में जो भी हो रहा है उसपर हमारी नजर है।

सखी

किसी भी टेक फर्म पर फेडरल ट्रेड कमीशन की ओर से लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा दंड है

निजता के उल्लंघन मामले में फेसबुक भरेगा पांच अरब डॉलर का जुर्माना

वाशिंगटन, आइएएनएस : यूजर्स की निजता के उल्लंघन मामले में सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक पांच अरब डॉलर (करीब 39 हजार करोड़ रुपये) के जुर्माने का भुगतान करने जा रही है। अमेरिकी नियामक फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने ब्रिटिश फर्म कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा की गई डाटा चोरी के मामले में फेसबुक पर यह जुर्माना लगाया था। कैंब्रिज एनालिटिका ने लाखों भारतीयों समेत आठ करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का डाटा इकट्ठा किया था। बाद में उस डाटा का इस्तेमाल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने में किया गया था।

बता दें कि एफटीसी ने इस महीने की शुरुआत में ही फेसबुक पर जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की थी। इस फैसले को एजेंसी में दो के मुकाबले तीन वोट से मंजूरी दी गई थी। निजता के उल्लंघन मामले में किसी भी टेक फर्म पर एफटीसी की ओर से लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। कैंब्रिज एनालिटिका के अलावा भी फेसबुक को यूजरों की गोपनीयता व डाटा सुरक्षा में खामियों को लेकर कई अन्य आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम के लाखों यूजर का पासवर्ड सुरक्षित रखने में लापरवाही करने को लेकर पर फेसबुक पर सवालिया खड़े हुए थे।

अपने डाटा की सुरक्षा यूजरों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। फाइल

पहले भी लग चुका है जुर्माना : निजता उल्लंघन के मामले में फेसबुक पर पहले भी जुर्माना लग चुका है। पिछले साल ब्रिटिश सूचना कार्यालय ने भी फेसबुक पर पांच लाख पौंड (करीब 4.30 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना भी कैंब्रिज एनालिटिका के डाटा चोरी मामले में फेसबुक की भूमिका को लेकर लगाया गया था।

यूट्यूब के खिलाफ भी हुई थी कार्रवाई

बच्चों की निजता के उल्लंघन मामले में गूगल के मालिकाना हक वाले वीडियो शेयरिंग एप यूट्यूब पर भी बीते दिनों लाखों डॉलर का जुर्माना लगा था। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि इस मामले के निपटारे को लेकर गूगल और अमेरिकी नियामक फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) के बीच समझौता हो गया है। एफटीसी यूट्यूब पर लगे आरोपों की जांच के दौरान पाया कि यूट्यूब के जरिये गूगल ने गलत तरीके से बच्चों की निजी जानकारियां जुटाई थीं। गूगल का यह कृत्य चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। इस मामले में एफटीसी द्वारा गूगल पर भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने की बात बीते जून माह में ही सामने आ गई थी। अमेरिकी सीनेटर एड मार्के ने भी एफटीसी को लिखे खत में यूट्यूब के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी। मार्के का कहना था कि यूट्यूब को हर उस अवैध क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। इन सबके बाद यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड करने व देखने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात की थी। इसके साथ ही यूट्यूब बच्चों से संबंधित सभी कंटेंट को 'यूट्यूब किड्स एप' में ट्रांसफर करने का भी विचार कर रहा है।

बड़ी टेक कंपनियों की जांच करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका ने गूगल, अमेजन, एप्पल और फेसबुक जैसी नामी टेक कंपनियों की जांच करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि बिग टेक की कंपनियों ने बाजार में प्रतिस्पर्धा के मानकों का सही-सही पालन किया है या नहीं। इन कंपनियों पर बाजार में अपना दबदबा कायम करने को लेकर अनुचित तरीके अपनाने का आरोप है।

अमेरिकी संसद में भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से इन कंपनियों का उपभोक्ता बाजार में प्रभुत्व स्थापित होने से दूसरी अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने का माहौल नहीं मिल पा रहा है। अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये ये कंपनियां बाजार में मजबूत पकड़ बना चुकी है, जिससे स्टार्टअप फर्मों को सामने आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। न्याय विभाग द्वारा जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों के नाम हालांकि जाहिर नहीं किए गए हैं।

न्याय विभाग ने कहा कि बिग टेक कंपनियों द्वारा नवाचार को रोकने और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने जैसे बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। सरकार की इस घोषणा के बाद फेसबुक के शेयर में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर के भाव में एक प्रतिशत की कमी देखी गई। खबर फैलने के बाद अमेजन और एप्पल के शेयरों में भी कमी दर्ज की गई है।

अमेरिकी संसद में छाया है मुद्दा : पिछले हफ्ते अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा में न्यायिक कमेटी की एक पैनल ने इन चार कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीके को लेकर कार्रवाई की मांग कर चुका है। बाजार में इन कंपनियों के प्रभुत्व को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भाग्य आजमा रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एलिजाबेथ वारेन ने इन कंपनियों को विभाजित कर देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के दोनों राजनीतिक दलों का रुख एक जैसा है।

पाक में वेतन और नौकरी को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन

गिलगित, एएनआइ : पाकिस्तान में गिलगित-बाल्टिस्तान के शिक्षकों ने वेतन और नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इन्हें तत्काल नहीं माने जाने पर शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। गिलगित-बाल्टिस्तान के शिक्षक संघ के सचिव सज्जाद हुसैन ने बताया कि इस साल का सातवां महीना महीना भी बीतने वाला है, लेकिन वेतन के नाम पर सरकार ने शिक्षकों को महज आठ हजार रुपये दिए हैं।

इन मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत शिक्षकों का कहना है कि गिलगित-बाल्टिस्तान में बुनियादी शिक्षा क्षेत्र में 1,464 शिक्षक 1994 से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी स्थायी नहीं की गई है। पिछले साल फरवरी में गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्य मंत्री हाफिज हफीजुर रहमान द्वारा 750 नियुक्तियां स्थायी करने के आश्वासन के 17 महीने बाद भी इसे अमल में नहीं लाया गया है। अगले एक साल में असेंबली भंग होने के साथ ही वर्तमान सरकार के आदेश भी स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

सरफराज को एक विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में टीम में रखना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रारूप में टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए।
— शोएब अख्तर, पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज

कॉटरेल ने भारत की नेत्रहीन टीम को सलाम किया

जमैका, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल ने भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम की तारीफ की जब क्रिकेटरों ने यहां सेना के एक शिविर के दौरान उनसे मुलाकात की। भारतीय टीम तीन वनडे और दो टी-20 मैचों की सीरीज में जमैका की नेत्रहीन टीम से खेलेगी। कॉटरेल ने ट्वीट किया, 'भारतीय टीम जमैका के ऐतिहासिक दौरे पर। इन खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों को सलाम।'

जब पाकिस्तान में टेनिस खेल सकते हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

- बीसीसीआइ के अधिकारी ने कहा, क्या सरकार ने बदल दी है नीति
- दो टीमों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकते मापदंड

पड़ोसी देश से फैलाए जा रहे आतंकवाद के कारण भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक-दूसरे के देश का दौरा नहीं करती हैं लेकिन हाल ही में भारतीय टेनिस टीम के पाकिस्तान के प्रस्तावित दौरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय टेनिस टीम को 14-15 सितंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ग्रुप-1 एशियाई ओसियाना क्षेत्रीय मैच में मेजबान टीम से भिड़ना है और इसकी तैयारियों जोरों पर हैं। भारतीय टेनिस संघ और पाकिस्तान टेनिस संघ को उम्मीद है कि भारत सरकार इसकी अनुमति देगी लेकिन इस प्रस्तावित दौरे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने आंखें टेढ़ी कर ली हैं। बीसीसीआइ के एक पदाधिकारी ने कहा कि क्या भारत सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है? पाकिस्तान से तटस्थ देश में, वहां तक कि विश्व कप में भी मैच खेलने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआइ को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान का दौरा कैसे कर सकती है? जब हमें एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय सीरीज खेलने की अनुमति नहीं है तो फिर टेनिस में दोनों टीमें आमने-सामने कैसे हो सकती हैं? दो खेलों

सरफराज और कोहली। फाइल फोटो, एएफपी

को अलग-अलग मापदंडों पर नहीं तौला जा सकता है। अगर सरकार की नीति में परिवर्तन है तो बीसीसीआइ को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। बोर्ड के पदाधिकारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की टीमें अब सिर्फ आइसीसी विश्व कप, टी-20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में ही आपस में भिड़ती हैं।

सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण दोनों टीमों ने एक-दूसरे के यहां दौरा बंद कर रखा है। यहां तक की तटस्थ देश में भी दोनों टीमें द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा 2005-06 में किया था और उस दौरान तीन टेस्ट और पांच वनडे खेले गए थे। पाकिस्तान ने 2012-13 में आखिरी बार भारत में तीन वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज खेली थी। बीसीसीआइ के पदाधिकारी ने कहा कि हम अभी तक वही करते आए हैं जो हमारी सरकार ने हमसे कहा है और आगे भी हम वही करेंगे लेकिन हर खेल के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए क्योंकि हर जगह राष्ट्रीय टीम ही भाग ले रही है। दो राष्ट्रीय टीमों के लिए अलग-अलग नियम नहीं लागू किए जा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से अधिकतर क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं करती हैं लेकिन वे उनसे दुबई में द्विपक्षीय सीरीज खेलती हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी बाकी देशों का दौरा करती है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में केस भी किया था जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था।

भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी भिड़ंत हाल ही में इंग्लैंड में खत्म हुए विश्व कप में हुई थी। इससे पहले दोनों टीमें एशिया कप में भिड़ी थीं और उससे पहले दोनों का आमना-सामना 2016 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड में हुआ था।

आइटीएफ अधिकारियों ने लिया इस्लामाबाद में सुरक्षा का जायजा

टेनिस

- अधिकारियों ने मैच स्थल और होटल का भी दौरा किया जहां खिलाड़ी व अधिकारी ठहरेंगे

कराची, प्रेट्र : भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर में होने वाले डेविस कप मुकाबले से पहले अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) का दो सदस्यीय दल इस ग्रुप-1 एशियाई ओसियाना क्षेत्रीय मैच की तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। भारत को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप मैच खेलना है।

आइटीएफ ने 14 और 15 सितंबर को होने वाले मुकाबले की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी थी। पाकिस्तान टेनिस महासंघ (पीटीएफ) के एक अधिकारी ने कहा, 'रिचर्ड सिमोन की अगुआई में आइटीएफ प्रतिनिधिमंडल ने पीटीएफ अध्यक्ष सलीम सैफुल्लाह से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने मैच स्थल और होटल का भी दौरा किया जहां खिलाड़ी और अधिकारी ठहरेंगे।'

अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने होटल और मुकाबले के लिए चुने गए स्थल की सभी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पीएसबी के महानिदेशक आरिफ इब्राहिम को मुकाबले के सहज तरीके से आयोजित कराए जाने वाले उपायों के बारे में बताया।' उन्होंने कहा कि आइटीएफ अधिकारी मैच के लिए तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे। भारत व पाक 13 वर्षों में पहली बार टेनिस मुकाबले में आमने-सामने होंगे। ये दोनों टीमें इससे पहले अप्रैल 2006 में एक-दूसरे से भिड़ी थीं। तब मुंबई ने इसकी मेजबानी की थी। पाकिस्तान पिछले वर्षों तक तटस्थ स्थलों पर डेविस कप मैचों की मेजबानी करता रहा, क्योंकि सुरक्षा कारणों से विदेशी टीमों ने इस देश में आने से इन्कार कर दिया था। पीटीएफ अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार अपनी टीम को इस्लामाबाद में खेलने की अनुमति दे देगी।

लोगों के सामने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक किए प्रदर्शित

टोक्यो ओलंपिक

टोक्यो, एपी : एशियाई महाद्वीप में 12 साल बाद होने वाले टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह से ठीक एक साल पहले बुधवार को यहां पहली बार इसके स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया।

जापान की राजधानी में प्रशंसकों, प्रायोजकों और राजनेताओं ने विभिन्न समारोह में हिस्सा लिया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं और घड़ी 365 दिन शेष दिखा रही थी। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2020 को होगा। 1976 के ओलंपिक में तलवारबाजी का स्वर्ण पदक जीतने वाले और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने स्कूली बच्चों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। पूरे दिन चले इस कार्यक्रम के दौरान जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। जापान ने इन खेलों की मेजबानी पर लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 137755 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं। हालांकि ओलंपिक आयोजन पर होने वाले खर्चों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। खेलों के लिए आठ नए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से पांच का काम समाप्त हो गया है। नेशनल स्टेडियम 125 करोड़ डॉलर (करीब 8609 करोड़ रुपये) की लागत से तैयार किया गया है, जिसे इस साल के आखिर तक खोल दिया जाएगा। टोक्यो में आइओसी के कोर्डिनेशन कमिशन के प्रमुख जॉन कोट्स ने कहा, 'उत्साह लगातार बढ़ रहा है। आप टिकटों की बिक्री में अभूतपूर्व दिलचस्पी से इसका अनुमान लगा सकते हैं।' जापानी आयोजकों ने टिकटों की मांग आपूर्ति से 10 गुना या इससे अधिक है। विदेशों से भी टिकटों की भारी मांग है। जापान में हाल में अनाधिकृत तरीके से टिकटों की फिर से बिक्री करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था और तमाम खामियों के बीच इस कानून की असली परख होगी। टोक्यो की ओलंपिक तैयारियां आखिर चरण में प्रवेश कर गई हैं। कोट्स ने हालांकि तैयारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हमें बहुत खुशी है कि खेलों के लिए तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।' आयोजक टोक्यो की गर्मियों से निपटने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि, इस बार यहां बारिश हुई है। आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा, 'इस साल टोक्यो का मौसम अच्छा रहा। यह पिछले साल की तुलना में बहुत अलग था।'

विश्व चैंपियन इंग्लैंड 85 रनों पर ढेर

लॉर्ड्स टेस्ट ▸ पहले दिन इंग्लिश टीम को समेटने के बाद आयरलैंड के दो विकेट पर 127 रन

तेज गेंदबाज टिम मुर्टाघ ने झटके पांच विकेट, बालबिर्नी का अर्धशतक

लंदन, रायटर : विश्व कप खिताब जीतने के बाद सातवें आसमान की सैर करने वाली इंग्लैंड की टीम उस समय धड़ाम से जमीन पर गिर गई जब आयरलैंड की टीम ने उसे लॉर्ड्स टेस्ट में बुधवार को महज 85 रनों पर ढेर कर दिया। जवाब में खबर लिखे जाने तक आयरलैंड ने शानदार शुरुआत करते हुए चायकाल तक दो विकेट पर 127 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 42 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। चायकाल के समय एंडी बालबिर्नी 51 और पॉल स्टर्लिंग 35 रन बनाकर नाबाद थे।

इंग्लिश कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और नीले आसमान के नीचे पहले बल्लेबाजी करने का आसान फैसला किया लेकिन सुबह का सत्र पूरी तरह से आयरलैंड और उसके तेज गेंदबाज टिम मुर्टाघ के नाम रहा। मुर्टाघ ने सुबह के सत्र को इंग्लैंड के लिए परेशानियों का सबब बना दिया जिन्होंने नौ ओवर में महज 13 रन देकर पांच विकेट झटके। मिडलसेक्स के लिए खेलने वाले 37 साल के मुर्टाघ ने हल्की हरी विकेट का जमकर फायदा उठाया और लॉर्ड्स में पहली बार और कुल तीसरा टेस्ट खेलने उतरी आयरलैंड की टीम को स्वप्न सरीखी शुरुआत दिलाई।

छह रनों के अंदर सात विकेट : आलम यह रहा कि जब ब्रॉड बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे तब तक इंग्लैंड की टीम 43 रनों पर सात विकेट खोकर शर्मसार होने की कगार पर खड़ी थी। इस दौरान इंग्लैंड की टीम सात रनों के अंदर अपने छह विकेट गंवा चुकी थी और आयरलैंड के लिए अपना पहला टेस्ट खेलने वाले मार्क अडेर (3/32) भी जलवा बिखेर रहे थे।

रॉय का फ्लॉप पदार्पण : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी एशेज सीरीज को ध्यान में रखकर सीमित ओवरों के विशेषज्ञ जेसन रॉय को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिला लेकिन वह अपने टेस्ट करियर की पहली पारी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उन्हें महज पांच रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर मुर्टाघ ने अपना शिकार बनाया। उनके आउट होने के साथ ही इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की परेशानियां एक बार फिर बरकरार रहीं। रॉय को पहले ही अडेर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था लेकिन वह नो बॉल होने से वह बच गए। हालांकि उस जीवनदान का वह फायदा नहीं उठा सके और मुर्टाघ की गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को स्लिप में कैच थमा बैठे। तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने आए जो डेनली (23 रन) थोड़े स्थिर लग रहे थे, लेकिन वह भी पारी के 10वें ओवर में अडेर की गेंद के सामने पाए गए और एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स (छह रन) को मुर्टाघ ने विल्सन के हाथों विकेटों के पीछे कैच आउट कराया, जबकि कप्तान जो रूट (दो रन) को तीसरे अंपायर ने आयरलैंड के कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड द्वारा रिव्यू की मांग पर एलबीडब्ल्यू करार दिया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली और क्रिस वोक्स बिना खाता खोले मुर्टाघ का शिकार बने। मोइन को आउट करके मुर्टाघ ने पांच विकेट पूरे किए और लॉर्ड्स के पटल पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। सैम कुर्रन ने कुछ आकर्षक शॉट खेलकर थोड़ी हलचल मचाई लेकिन ब्रॉड (तीन रन) ने बोयड रैंकिन (2/05) की गेंद पर विल्सन को कैच देकर इंग्लैंड को मझधार में छोड़ दिया। यह वही रैंकिन हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से अपना टेस्ट करियर शुरू किया था लेकिन अब वह आयरलैंड की ओर से खेलते हैं। उधर, सैम के शॉर्ट लेग पर 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट होने के साथ ही इंग्लैंड का स्कोर नौ विकेट पर 67 रन हो गया। इसके बाद अडेर ने पदार्पण कर रहे ओले स्टोन (19 रन) को चलता करके इंग्लैंड का पुलिंदा महज 23.4 ओवर में भोजनकाल से पहले बांध दिया। इंग्लैंड के आठ बल्लेबाज दहाई रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। जवाब में आयरलैंड को कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड (14) और जेम्स मैककॉलम (19) की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। सैम कुर्रन ने पोर्टरफील्ड को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। जल्द ही कुर्रन ने मैककॉलम को भी बोल्ड कर आयरलैंड का स्कोर दो विकेट पर 45 रन कर दिया।

1997 के बाद 85 रन इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान में न्यूनतम स्कोर है। तब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में ही 77 रनों पर आउट हुई थी

01 बार लॉर्ड्स में इंग्लैंड की टीम किसी टेस्ट मैच के पहले दिन भोजनकाल से पहले ऑलआउट हो गई

05 विकेट टेस्ट मैच की एक पारी में लेने वाले आयरलैंड के पहले गेंदबाज बने टिम मुर्टाघ

10 विकेट पिछले तीन साल के एक सत्र में तीसरी बार इंग्लैंड की टीम ने खोए

लॉर्ड्स में क्रिस वोक्स का विकेट चटकाने के बाद टिम मुर्टाघ। एएफपी

रमन की नियुक्ति की समीक्षा होगी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआइ के लोकपाल डीके जैन को राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच डब्ल्यूवी रमन की नियुक्ति की समीक्षा करने को कहा है।

सीओए ने सैद्धांतिक रूप से अप्रैल में ही रमन की नियुक्ति की समीक्षा करने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जैन को कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह मामला भेजा है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रमन को पिछले साल दिसंबर में पूर्व क्रिकेटरों कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी की तदर्थ समिति ने विवादास्पद हालात में नियुक्त किया था। सीओए उस समय दो सदस्यीय समिति थी और इसके अध्यक्ष विनोद राय और डायना इडुल्जी के बीच कोच चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर मतभेद थे। रवि थोडगे के शामिल होने के बाद अब यह समिति तीन सदस्यीय हो गई है। इडुल्जी ने कोच चयन प्रक्रिया को दिखावटी और 'असंवैधानिक' करार देते हुए कहा था कि कोच चुनने की जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएससी) को दी जानी चाहिए थी।

भारतीय टीम के चयन से नाराज सौरव गांगुली

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- गिल और रहाणे का वनडे टीम में होना चाहिए था चयन
- सभी को खुश करना जरूरी नहीं, सभी प्रारूपों में समान खिलाड़ियों का करें चयन

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बुधवार को अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और युवा शुभमन गिल को वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम में नहीं चुनने पर सवाल उठाए और चयन समिति से अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखने का आग्रह किया। रहाणे का चयन सिर्फ टेस्ट टीम में हुआ है जबकि गिल को किसी भी टीम में नहीं चुना गया।

केदार जाधव निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वह टीम में हैं जबकि वेस्टइंडीज में पांच लिस्ट-ए मैचों में 218 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज रहे गिल को टीम में जगह नहीं मिली। गांगुली ने ट्विटर पर चयनकर्ताओं की खिंचाई की और उन्होंने कहा कि उनका मुख्य काम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम का चयन करना होना चाहिए ना कि लोगों को खुश करना। उन्होंने ट्वीट किया, 'लय और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए समय आ गया है कि चयनकर्ता सभी प्रारूपों में समान खिलाड़ियों का चयन करें। केवल कुछ खिलाड़ी ही हैं जो सभी प्रारूपों में खेलते हैं। मजबूत टीमों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं। सभी को खुश करना जरूरी नहीं है। देश के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करना और चयन में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।' उन्होंने आगे लिखा, 'टीम

सौरव गांगुली। फाइल फोटो, प्रेट्र

में कई ऐसे हैं जो सभी प्रारूपों में खेल सकते हैं। शुभमन गिल को वनडे टीम में नहीं देखकर हैरान हूं। रहाणे को भी वनडे टीम में होना चाहिए था।' एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली चयन समिति ने रविवार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टी-20, वनडे और टेस्ट मैचों के लिए टीम का चयन किया था।

मैं निराश हूं : गिल

नई दिल्ली : भारत-ए की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने के कारण शुभमन गिल को सीनियर टीम में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ जिससे वह निराश हैं पर इसके बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। गिल, मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बारे में माना जा रहा था कि उन्हें सीमित ओवरों की टीम में चुन लिया जाएगा लेकिन पंजाब के युवा बल्लेबाज गिल की अनदेखी की गई।

गिल ने कहा, 'मैं रविवार को भारतीय सीनियर टीम की घोषणा का इंतजार कर रहा था और मुझे किसी एक टीम में चयन की उम्मीद थी। चयन नहीं होना निराशाजनक है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मैं चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए रन बनाना और अपनी काबिलियत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूंगा।' गिल वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ सीरीज में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड में दो वनडे खेलने वाले गिल ने कहा, 'मेरे और टीम के लिए वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ शानदार सीरीज रही जो हमने 4-1 से जीती। निजी तौर पर मैं अपने दो अर्धशतकों को शतक में तब्दील करना पसंद करता लेकिन इस अनुभव से मैं सीख लूंगा।' गिल के लिए वेस्टइंडीज दौरे की सबसे बड़ी सीख परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को ढालना रही। उन्होंने कहा, 'वेस्टइंडीज दौरे में मैंने सीखा कि मैच की परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को कैसे ढालना चाहिए। अच्छी गेंदों को सम्मान देना और अधिक से अधिक समय तक क्रीज पर टिके रहना भी महत्वपूर्ण होता है।'

हमारा ध्यान ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर : मनप्रीत

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने बुधवार को कहा कि आठ बार के ओलंपिक चैंपियन भारत का ध्यान अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर है, जबकि खेलों के महाकुंभ की शुरुआत में अब सिर्फ एक साल का समय बचा है। मनप्रीत ने कहा, 'हमें भी पता है कि कितना समय बचा है और हम लगातार खुद को याद दिलाते रहते हैं कि क्वालीफाई करने के लिए कितने दिन बचे हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले कितने दिन बचे हैं। हम क्वालीफाई करने के लिए उत्सुक हैं। खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कोचिंग स्टाफ भी हमें याद दिलाता रहता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने दिन बचे हैं और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से पहले हमें क्या उपलब्धियां हासिल करने की जरूरत है। अपने कमजोर पक्षों पर काम करने के लिए हमने छोटे लक्ष्य तय किए हैं, इसके अलावा ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता, बेल्जियम दौरे जैसी आगामी प्रतियोगिताओं में हम किन टीमों के खिलाफ खेलना चाहते हैं। हम बेहतर प्रदर्शन करें यह सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रत्येक बिंदू पर गौर किया है।'

टेस्ट में उपलब्ध रहेगी नंबर-7 की जर्सी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

क्रिकेट डायरी

आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहली बार सफेद कमीज पर जर्सी नंबर डाले जाएंगे और 22 अगस्त से एंटीगा में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम दो नंबरों का इस्तेमाल शायद ही करे। सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को बीसीसीआइ 'अनधिकृत रूप से रिटायर' कर चुका है। जब तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने इसे मैच के दौरान पहना तो सोशल मीडिया पर उनकी काफी खिंचाई हुई। समझा जाता है कि अधिकांश भारतीय खिलाड़ी अपनी सीमित ओवरों की जर्सी के नंबर ही इस्तेमाल करेंगे। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'विराट 18 और रोहित 45 नंबर पहनेंगे। अधिकांश खिलाड़ी अपनी वनडे और टी-20 जर्सी के नंबर पहनेंगे। एमएस चूंकि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो जर्सी नंबर-7 उपलब्ध रहेगी, लेकिन बहुत कम संभावना है कि कोई खिलाड़ी इसे पहने। वनडे सीरीज के बाद ही वेस्टइंडीज में नंबर वाली जर्सी पहुंचेंगी।' आम तौर पर जर्सी रिटायर नहीं की जाती, लेकिन भारतीय क्रिकेट में धौनी का कद इतना बड़ा है कि बीसीसीआइ उनकी जर्सी रिटायर कर सकता है। धौनी ने 2015 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। एक अगस्त से एशेज की शुरुआत हो रही है जहां खिलाड़ी पहली बार टेस्ट क्रिकेट में जर्सी नंबर पहनते दिखाई देंगे। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत पहली द्विपक्षीय सीरीज है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।

रोड्स ने भारत के फील्डिंग कोच के लिए किया आवेदन : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और अपने समय के बेहतरीन फील्डरों में से एक जोंटी रोड्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच पद के लिए आवेदन किया। बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'रोड्स ने फील्डिंग कोच पद के लिए आवेदन किया है। रोड्स ने इससे पहले किसी भी राष्ट्रीय टीम के साथ काम नहीं किया, लेकिन वह आइपीएल में मुंबई इंडियंस को पिछले नौ सत्र से कोचिंग देते आ रहे हैं।'

तेज गेंदबाज नुवान कुलसेकरा का क्रिकेट से संन्यास

कोलंबो : श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान कुलसेकरा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 37 वर्षीय कुलसेकरा ने 184 वनडे मैचों में 199 विकेट जबकि 58 टी-20 मैचों में 66 विकेट चटकाए। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 15 साल से अधिक समय तक रहा। उन्होंने श्रीलंका की ओर से 21 टेस्ट में 48 विकेट भी हासिल किए। कुलसेकरा ने आखिरी बार जुलाई 2017 में हंबनटोटा में जिंबाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। वह मार्च 2018 के बाद से किसी प्रतिस्पर्धी मैच में नहीं खेले हैं। कुलसेकरा ने 2014 विश्व टी-20 में श्रीलंका की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाते हुए छह मैचों में आठ विकेट चटकाए थे। कुलसेकरा मार्च 2009 में आइसीसी रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बने थे। भारतीय बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने 2011 विश्व कप के फाइनल में कुलसेकरा की गेंद पर ही छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई थी।

फुटबॉल डायरी

पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से जीता रीयल मैड्रिड, दूसरे हाफ में स्टार स्ट्राइकर गेरेथ बेल ने दागा गोल, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में चूके

आर्सेनल पर रीयल की जीत में बेल ने दागा गोल

वाशिंगटन, प्रेट्र : स्पेनिश फुटबॉल क्लब रीयल मैड्रिड में अपने भविष्य को लेकर अधर में लटके गेरेथ बेल ने मंगलवार को आर्सेनल के ऊपर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इंटरनेशनल चैंपियनशिप कप के इस दोस्ताना मुकाबले में दो गोल से पिछड़ने के बाद रीयल ने आर्सेनल को निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद रीयल ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से आर्सेनल को शिकस्त दी।

बायर्न म्यूनिख के खिलाफ पिछले मुकाबले में बेल खेलने नहीं उतरे थे, जिसके बाद रीयल के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने कहा था कि वेल्स के स्टार ने उस मुकाबले में खेलने से मना कर दिया था। हालांकि, तब बेल के एजेंट ने जिदान पर अपमान करने के आरोप लगाए थे जिससे जिदान ने इन्कार किया था। आर्सेनल के खिलाफ बेल मैदान में उतरे और 56वें मिनट में गोल करके दो गोल से पिछड़ रही अपनी टीम को वापसी दिलाई। इसके तीन मिनट बाद मार्को असेंसियो ने गोल करके रीयल को बराबरी पर ला खड़ा किया। इससे पहले एलेक्जेंडर

वाशिंगटन में मैच के दौरान गोल करने के बाद साथी खिलाड़ी संग जश्न मनाते गेरेथ बेल (बायें)। एएफपी

लैकाजेत (10वें मिनट) और पियरे इमरिक अयूबमेयांग (24वें मिनट) ने गोल करके आर्सेनल को हाफटाइम तक 2-0 की बढ़त दिलाई। इस दौरान ज्यादातर समय तक दोनों टीमों को 10 खिलाड़ियों के साथ ही मुकाबले को पूरा करना पड़ा। रीयल के नाचो और आर्सेनल के सुकरातिस को रेड कार्ड दिखाया गया। इस मुकाबले में अपनी टीम का खाता खोलने वाले बेल शूटआउट में गोल करने का मौका चूक गए। हालांकि, जिदान ने कहा कि उसने अच्छा खेल दिखाया और मैं उसके लिए खुश हूं।

मेसी पर लगा एक मैच का प्रतिबंध

असुंसियन (पराग्वे), एपी : अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी 2022 फीफा विश्व कप के पहले क्वालीफायर मैच में अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ (कोनमेबोल) ने उन्हें एक मैच के लिए प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा उन पर 1500 डॉलर (करीब एक लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया है। मेसी को कोपा अमेरिका के तीसरे स्थान के लिए चिली के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान रेड कार्ड मिला था। मेसी खेल के 37वें मिनट में चिली के गैरी मेडेल से भिड़ गए थे जिसके बाद उन दोनों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया गया था। छह जुलाई को खेले गए उस मुकाबले को अर्जेंटीना ने 2-1 से जीता था। तब मेसी ने कोपा अमेरिका के आयोजकों पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है और इसे ब्राजील के जीतने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि, बाद में मेसी ने अपने बयान के लिए कोनमेबोल से माफी मांगी थी। दक्षिण अमेरिका में विश्व कप के क्वालीफाइंग मुकाबले मार्च में शुरू होंगे।

बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधू-प्रणय ने बनाई दूसरे दौर में जगह

जापान ओपन

- भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत और समीर टूर्नामेंट से हुए बाहर

टोक्यो, प्रेट्र : भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और एचएस प्रणय ने क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स स्पर्धाओं में बुधवार को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जीत दर्ज करते हुए जापान ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन में उप विजेता रहीं सिंधू ने गैरवरीय चीन की हान को सीधे गेमों में 21-9, 21-17 से हराने में महज 37 मिनट लिए। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू का सामना अब जापान की आया ओहोरी से होगा।

वहीं, आठवें वरीय श्रीकांत की खराब फॉर्म जारी है और वह बुधवार को यहां पहले दौर में ही हमवतन प्रणय से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। प्रणय ने अपने से अधिक रैंकिंग के श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से हराया। यह मैच 59 मिनट तक चला। समीर वर्मा भी पहले दौरे से आगे नहीं बढ़ पाए और डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से सीधे गेमों में हार गए। गैरवरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को 46 मिनट तक चले मैच में 17-21, 12-21 से पराजय का सामना करना पड़ा। प्रणय दूसरे दौर में डेनमार्क के रासमुस गेमके का सामना करेंगे। श्रीकांत पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। पुरुष डबल्स में भारत के लिए अच्छी खबर रही। सत्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंग्लैंड के मार्कस एलिस और क्रिस लैंग्रिज की जोड़ी को 21-16, 21-17 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं, महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी कोरिया की सो यियोंग किम और ही योंग कोंग की जोड़ी से 16-21, 14-21 से हारकर बाहर हो गई। इस बीच, प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी मिक्स्ड डबल्स से बाहर हो गई। उन्हें चीन के झेंड सी वेइ और हुआंग कियोंग ने 21-11, 21-14 से हराया।

क्लाइमेट स्मार्ट खेती : 50 फीसद पानी, 20 फीसद लागत कम

कारगर तकनीक ▶ केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में हो रहा सफल प्रयोग, पहली बार इस तरह पैदा हो रहा धान

पानी की एक भी बूंद नहीं जाती व्यर्थ, गेहूं व मक्का पर भी हो रहा प्रयोग

मनोज ठाकुर, करनाल

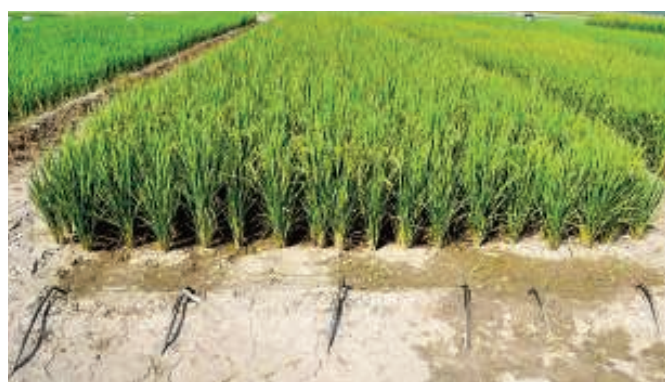

हरियाणा के करनाम में सब सर्फेस ड्रिप इरीगेशन विधि से तैयार की जा रही धान की फसल। जागरण

यह प्रयोग सफल है। देश में पहली बार सब-सर्फेस ड्रिप इरीगेशन से धान की फसल उगाई जा रही है। भविष्य में पानी की चुनौतियों को देखते हुए यह तकनीक देश के लिए कारगर साबित होगी। किसान भाई इस तकनीक से धान की खेती करेंगे तो पानी की बचत के साथ-साथ फायदा भी अधिक होगा।

- डॉ. एचएस जाट, प्रधान विज्ञानी, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा।

मक्का की फसल के लिए लगा सब सर्फेस ड्रिप इरीगेशन। जागरण

जल संरक्षण

धान की खेती को भूजल स्तर गिरने का बड़ा कारण माना गया है। यही वजह है कि इसका रकबा कम करने की बात हो रही है। अब पानी की आधी खपत में धान पैदा किया जा सकेगा। सब-सर्फेस ड्रिप इरीगेशन (उप सतह टपका सिंचाई) तकनीक किसी संजीवनी से कम नहीं है। खासकर धान पैदावार वाले क्षेत्र में यह तकनीक कारगर साबित होगी।

क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल के तहत सब-सर्फेस डिप इरीगेशन से धान, मक्का और गेहूं की फसल लेने का सफल प्रयोग केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में हो रहा है। पानी की खपत में 50 फीसद और लागत में 20 फीसद की कमी दर्ज की गई है। संस्थान के विज्ञानियों ने दावा किया है कि धान की खेती में 50 प्रतिशत तक पानी की बचत का यह प्रयोग देश में पहली बार किया गया है। इस तकनीक को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में मॉडल के रूप में जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र भी सहभाग कर रहा है। यह विधि ड्रिप इरीगेशन का ही आधुनिक स्वरूप है। ड्रिप इरीगेशन में पानी की पाइप लाइन को जमीन की सतह के ऊपर रखा जाता है और सिंचाई के बाद हटा दिया जाता है। नई तकनीक में लाइन जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर की गहराई में बिछाई जाती है। यदि धान और गेहूं की फसल लेनी है तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। मक्का और गेहूं की फसल लेनी है तो यह दूरी 65 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जमीन के नीचे जो लाइन बिछाई जाती है उसमें हर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर छिद्र बनाए जाते हैं ताकि इनसे पानी रिस सके। किसान एक साल में दो से तीन फसलें लेने के लिए 12 बार खेत की जुताई करता है। गेहूं और धान में 180 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ती है। मक्का में 175 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ती है। लेकिन नई विधि में साल में महज दो बार ही खेत जोतने की जरूरत होती है। कई फसलों में तो इसकी भी जरूरत नहीं होती। इसी तरह, धान में महज 120 किलोग्राम नाइट्रोजन में ही काम चल जाता है, यूरिया को घोलकर पाइपों के जरिये फसलों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। मक्का में 145 किग्रा से काम चल जाता है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पहली बार आठ लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम

रविंद्र कप्रवान, रुद्रप्रयाग : केदारनाथ यात्रा इस बार नित नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को इस वर्ष केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या आठ लाख का आंकड़ा पार गई। यह केदारनाथ यात्रा के इतिहास में यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। जबकि, यात्रा सीजन में अभी तीन माह का समय शेष है।

इस बार केदारनाथ धाम के कपाट नौ मई को खोले गए थे और पहले हफ्ते से ही धाम में यात्रियों का सैलाब उमड़ने लगा था। मई के आखिर में तो यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 30 हजार के आसपास पहुंच गई थी। यह भी पहली बार हुआ कि एक ही दिन में 36 हजार से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। इसके चलते श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को दर्शन का समय बढ़ाना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि पूरी रात मंदिर को दर्शन के लिए खुला रखना पड़ा।

2013 की केदारनाथ आपदा से पूर्व भी छह लाख से ऊपर नहीं था यात्रियों का आंकड़ा

मानसून आने के बाद हालांकि यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन सावन शुरू होते ही फिर यात्रियों की आमद बढ़ने लगी है। यही वजह है कि 23 जुलाई तक आठ लाख एक हजार 640 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके थे। अभी यात्रा में लगभग तीन महीने का वक्त शेष है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रियों की संख्या दस लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी।

आपदा से पूर्व 2012 में 5.72 लाख यात्री पहुंचे थे केदारनाथ : 2013 की केदारनाथ आपदा से पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे सीजन में छह लाख से अधिक यात्री कभी केदारनाथ नहीं पहुंचे। मंदिर समिति के कार्याधिकारी एनपी जमलोकी बताते हैं कि 2011 व 2012 में भी यह आंकड़ा 5.70 लाख व 5.72 लाख ही रहा। जबकि, 2018 में 7.32 लाख यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए, जो कि यात्रियों की सर्वाधिक संख्या थी। इस वर्ष की यात्रा ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

बीते दस वर्षों में केदारनाथ पहुंचे यात्री

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2019	801640 (23 जुलाई तक)
2018	732241
2017	471235
2016	309746
2015	154430
2014	40832
2013	312201
2012	572513
2011	570081
2010	399697

उखाड़े गए पेड़ों से फूटीं उम्मीद की कोपलें

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ

जागरण विशेष

- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर दूसरी जगह रोपा गया था
- सर्दी में रोपे गए पेड़ भीषण गर्मी में सूखने लगे, लेकिन बारिश होते ही निकलीं पत्तियां

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक ऐसी चुनौती पूरी की है, जो नजीर बन गई है। एक्सप्रेस-वे निर्माण की राह में बाधा बनने वाले सैकड़ों पेड़ों को सिर्फ जड़ समेत स्थानांतरित ही नहीं किया गया, बल्कि भीषण गर्मी से बचाकर उन्हें नया जीवन भी दे दिया। स्थानांतरित किए जो पेड़ गर्मी में सूख जाने का संकेत देकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के प्रयासों को धता बता रहे थे, उनमें अब उम्मीद की कोपलें फूट पड़ी हैं।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की राह में सैकड़ों पेड़ आ रहे थे, जिन्हें काटा गया और इसके बदले में नियमानुसार पौधारोपण करना सुनिश्चित हुआ। हालांकि इन्हीं में अच्छरौंडा-काशी गांव में आम के बाग के 250 पेड़ ऐसे थे, जिनके बारे में एनएचएआइ ने फैसला किया कि इन्हें रास्ते से हटाया तो जाएगा पर काटा नहीं जाएगा। तय हुआ कि पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपेंगे यानी स्थानांतरित कर देंगे। फरवरी में स्थानांतरित किए गए पेड़ों को देख ऐसा लग रहा था कि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। झुलसती गर्मी में पेड़ सूखने लगे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी गई। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए खेत की तरफ दीवार बना दी गई।

निर्माण में लगे टैंकरों से कई बार पानी डाला गया, पर तने जस के तस खड़े रहे। उम्मीद फिर भी कायम रही, जो अब पूरी हो गई है। मानसून के पहले झोंके के बाद ही इन पेड़ों में एक बार फिर हरियाली फूट पड़ी। उन पर नए पत्ते आ गए हैं। जिन शाखाओं को पेड़ को सूखने से बचाने के लिए काट दिया गया था, उन पर अब पतली-पतली नई शाखाओं ने आकार ले लिया है। एनएचएआइ के सूत्रों के अनुसार लगभग 25 हजार रुपये प्रत्येक पेड़ पर खर्च कर उन्हें स्थानांतरित किया गया था। पेड़ों को स्थानांतरित करने की इस प्रक्रिया में पेड़ उखाड़ने से पहले ट्री प्लांटर मशीन इसके चारों तरफ जड़ की लंबाई के अनुसार 6-7 फीट गहरा गड्ढा करती है। फिर पानी डालकर उस जगह को गीला किया जाता है। मशीन से ही पेड़ की शाखाओं को काटा जाता है। फिर गीली सतह के सहारे मशीन के कटर और पेड़ को थामने वाले हिस्से को नीचे पहुंचाया जाता है। जैसे ही मुख्य जड़ के नीचे तक यह हिस्सा पहुंच जाता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि मुख्य जड़ को क्षति नहीं पहुंची है, तब कटर के सहारे गोलाई में मिट्टी को काट दिया जाता है। फिर जड़ समेत पूरे हिस्से को उठा लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक-दो घंटे का समय लगता है। नया गड्ढा खोदने से लेकर मिट्टी पाटने तक का काम यही मशीन करती है।

ये पेड़ काफी बड़े और चौड़े थे, जिनका स्थानांतरण एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी आने वाले गर्मी के महीने। फिर भी कदम उठाया गया। भीषण गर्मी में ऐसा लगा कि पेड़ बच नहीं पाएंगे, लेकिन अब उनमें पत्तियां आ गई हैं। पर्यावरण के लिए किया गया यह प्रयास सफल रहा।

- आरपी सिंह, परियोजना निदेशक, दिल्ली-मेरठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे निर्माण के दौरान मेरठ जिले के काशी गांव के पास इन पेड़ों को स्थानांतरित किया गया था। गर्मी में ये पेड़ सूखने लगे थे, लेकिन मानसून की बारिश पाते ही इन पर अब पत्तियां आ गई हैं। जागरण

चमोली में 11 साल में नहीं बन पाई 11 किलोमीटर लंबी सड़क

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर(चमोली): दशकों से सड़क का इंतजार कर रहे सीमांत गांव थेंग के लिए स्वीकृत 11 किलोमीटर सड़क 11 साल बाद भी नहीं बन पाई है। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना (पीएमजीएसवाइ) के तहत निर्माणाधीन इस सड़क पर तो एक साल से ठेकेदार ने काम ही बंद कर दिया है, जबकि उसे 2.75 करोड़ में से दो करोड़ रुपये का भुगतान हो भी चुका है। ग्रामीणों के विरोध के बाद पीएमजीएसवाइ ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.68 करोड़ का जुर्माना किया है। साथ ही उसका अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। हैरत की बात यह है कि 3.3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क की लागत मौजूदा समय में बढ़कर 9.30 करोड़ रुपये हो गई है। उधर, थेंग के क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र नेगी का कहना है कि विभाग और ठेकेदार के विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द सड़क निर्माण न होने पर तहसील परिसर में धरना देने की चेतावनी ही है। इस सड़क के बनने से दो हजार की आबादी को फायदा पहुंचना है।

मारवाड़ी से थेंग तक 11 किलोमीटर मार्ग वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हुआ था। 3.3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए गाजियाबाद की रामनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2.75 करोड़ रुपये में करार हुआ। कंपनी के ठेकेदार ने वर्ष 2008-09 में काम शुरू किया था।

पति के शहीद होने पर इकलौते बेटे को सैनिक बनाने के बाद ही पहनाया सेहरा

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन

पति ने कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया था। अब शहीद की पत्नी ने इकलौते बेटे को भी देश की सेवा के लिए सेना में भेज दिया है। हम बात कर रहे हैं पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मल्लमोहरी निवासी बलजीत कौर की। लांस नायक शहीद बलविंदर सिंह ने 32 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बीस साल बाद अब शहीद का बेटा 22 वर्षीय सिमरजीत सिंह 19 सिख रेजिमेंट में उप्र के फतेहगढ़ सेंटर में तैनात है।

बकौल बलजीत कौर, जब मुझे पता चला कि पति कारगिल की चोटियों पर युद्ध में शहीद हो गए हैं। तब लगा कि मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे सिमरजीत सिंह की उम्र उस समय दो वर्ष थी। मेरी दो बेटियां भी हैं। मैं कभी तस्वीर तो कभी दोनों बेटियों और बेटे को देखती थी। मुझे एक तरफ बच्चों की परवरिश की चिंता थी तो दूसरी तरफ पति का साया उठ जाने का दर्द था। कहती हैं, मैंने अपना हौसला बरकरार रखा। इकलौते बेटे और बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी बेटे को शहीद पिता की गाथा सुनाती तो वह कहता था कि मैं पिता जी की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा।

शहीद बलविंदर सिंह की तस्वीर लिए पत्नी बलजीत कौर बेटे सिमरजीत, बहू कोमल और बेटी सिमरनजीत के साथ। जागरण

पति की चिता के सम्मुख लिया था प्रण : शहीद बलविंदर सिंह की पत्नी बलजीत कौर बताती हैं कि उन्होंने पति के अंतिम संस्कार के समय मन में ठान लिया था कि बेटे सिमरजीत सिंह के सिर पर तभी सेहरा सजाएंगी, जब वह फौजी बन जाएगा। कहती हैं, मुझे संतोष है कि मैंने उस संकल्प को पूरा किया और सेना में भर्ती के बाद ही अक्टूबर 2016 में बेटे सिमरजीत का विवाह कोमल कौर के साथ किया।

पिता की शहादत पर गर्व : सिमरजीत सिंह : एक माह की छुट्टी पर घर आए सिमरजीत सिंह ने बताया कि देश की सेवा करने का मौका तकदीर वालों को मिलता है। मुझे देशसेवा का जज्बा विरासत में मिला है। पिता बलविंदर सिंह को दिन-रात याद करता हूं। आज लोग मुझे कारगिल शहीद का बेटा होने के नाते सम्मान देते हैं। मुझे पिता की शहादत पर गर्व होता है।

अब चेहरे का नूर नहीं बिगाड़ पाएंगे मिलावटी कॉस्मेटिक, कसेगा शिकंजा

आशीष त्रिवेदी, लखनऊ

बंद होगा धंधा

- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशाला में होगी कॉस्मेटिक उत्पादों में मिलावट की जांच
- हानिकारक रसायनों की मिलावट करने वाले धंधेबाजों पर कसेगा शिकंजा

ड्रग इंस्पेक्टरों को इनके नमूने लेने के निर्देश दिए गए। प्रतीकात्मक

सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जा रहे कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) कई बार लोगों को बदसूरत बना देते है। स्किन (त्वचा) में एलर्जी होने से पहले चेहरा लाल होता है और फिर धीरे-धीरे काला हो जाता है। अब कॉस्मेटिक उत्पादों में हानिकारक रसायनों के मिलावट की जांच होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशाला में इसके नमूने जांचे जाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टरों को इनके नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं। नमूनों की जांच के बाद मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता भटनागर जैन कहती हैं कि कॉस्मेटिक उत्पादों में हानिकारक रसायनों की मिलावट पर रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। अभी तक सिर्फ खाद्य पदार्थों और दवाओं के नमूने ही प्रयोगशाला में जांच के लिए आते हैं लेकिन अब कॉस्मेटिक उत्पादों के नमूने भी जांचे जाएंगे।

भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रो.आलोक धावन कहते हैं कि ब्रांडेड कंपनियों के मिलते-जुलते नाम से बाजार में बहुत सस्ते दाम पर कॉस्मेटिक उत्पाद बिक रहे हैं। व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने और आम लोग सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में धोखा खा जाते हैं।

अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कॉस्मेटिक उत्पादों में कई रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों में हानिकारक रसायनों के मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। सस्ते के चक्कर में लोग नेल पालिश, लिपिस्टिक व फेशियल क्रीम खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। बलरामपुर अस्पताल के स्किन (त्वचा) रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएच उस्मानी कहते हैं कि ब्राइडल मेकअप का चलन शादी में बहुत बढ़ा है, मगर इसमें सावधानी बरतें। मिलावटी कॉस्मेटिक से चेहरा खराब हो जाता है। इरीटेंट डर्मेटाइटिस (त्वचा रोग) में चेहरे पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। दवा करने पर यह लाल चकत्ते तो सही हो जाते हैं लेकिन चेहरा काला हो जाता है। ऐसे में तमाम मरीज ओपीडी में आते हैं। फिलहाल इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि इससे एलर्जी व अन्य त्वचा रोग के साथ-साथ कैंसर तक होने का खतरा होता है।

अब चीनी टैबलेट से हो रही है भ्रूण लिंग की जांच

संतोष शुक्ल, मेरठ

मेरठ में भ्रूण लिंग जांच करने वाली चीनी डिवाइस। (सौजन्य - स्वास्थ्य विभाग)

लिंग जांच का रैकेट चलाने वाले चीनी टैबलेट के जरिए गर्भ में ताक- झांक की जा रही है। इसे मोबाइल से कनेक्ट कर भ्रूण का लिंग पता कर लिया जाता है। थाईलैंड से मंगाई गई यह डिवाइस रोजाना छह हजार रुपये किराये पर उपलब्ध है। इस हथकंडे पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं।

कोख के कातिलों ने निकाला तोड़ : एक जुलाई, 2017 से उप्र में चल रही मुखबिर योजना के तहत मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने 11 केंद्रों पर लिंग जांच के रैकेट पकड़े। लिंगानुपात को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हुई तो कोख के कातिलों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। दलालों ने अपने तार थाईलैंड और चीन तक जोड़ लिए। स्वास्थ्य विभाग ने हाल में मेरठ में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर चार ऐसे चीनी टैबलेट्स को जब्त किया, जिससे गर्भवती के भ्रूण की जांच बैठे-बैठे की जा सकती है। इस टैबलेट से मोबाइल को जोड़कर भ्रूण को स्क्रीन पर देख लिया जाता है।

छह हजार रुपये किराये पर उपलब्ध : यह तरीका इतना शातिराना है कि व्यक्ति बात करते-करते महिला की जांच कर सकता है और किसी को इसका संदेह तक न होगा। विभागीय अधिकारियों ने माना कि मेरठ में आधा दर्जन से ज्यादा रैकेट सक्रिय हैं। इस टैबलेट को रोजाना छह हजार रुपये किराए पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला को जांच केंद्र तक आने की जरूरत नहीं है। एजेंट गर्भवती महिला का बीपी नापने के बहाने घर पहुंचकर लिंग जांच कर रहे हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया कि पिछले एक साल में टीम ने मिथ्या ग्राहकों की मदद से 11 केंद्रों पर लिंग जांच पकड़ी। अल्ट्रासाउंड केंद्रों में गुपचुप पहुंचकर पैसे जब्त करते हुए स्टिंग आपरेशन के दौरान फिगर प्रिंट का प्रमाण जुटाया जाता है। अब दलाल स्टिंग से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फीस जमा कर वैधानिक तरीके से जांच कराते हैं। इससे नकद का कोई लेनदेन ही नहीं होता। महिला रिपोर्ट लेकर घर चली जाती है। डाक्टर शाम तक फोन पर दलाल को लिंग की जानकारी दे देता है। उधर, दलाल तीन दिन बाद डाक्टर को पैसा पहुंचा देता है। ऐसे में जांच टीम कोई नकदी नहीं पकड़ पाती है।

चीनी टैबलेट को मोबाइल से जोड़कर मिनटभर में भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा रहा है। इसे पैंट के पॉकेट में रखकर व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है। मेरठ में यह टैबलेट किराये पर उपलब्ध है। उधर, स्टिंग से बचने के लिए दलालों ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों में नकदी का लेन-देन बंद कर दिया है। लिंग की जानकारी शाम तक फोन पर दे दी जाती है।

- डॉ. प्रवीण गौतम, प्रभारी, पीसीपीएनडीटी सेल

उम्मीद

ओखलकांडा व भीमताल में बनेंगे 17 नए एरोमा कलस्टर, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 900 टन पत्तियों का उत्पादन

नैनीताल में महकेगा तेजपात, बढ़ेगा रोजगार

सतेंद्र डंडरियाल, हल्द्वानी

सरोवर नगरी के साथ ही नैनीताल प्रदेश में तेजपात उत्पादन के मामले में मुख्य उत्पादक क्षेत्र बन रहा है। जिले के सात विकासखंडों में 3759 कृषक 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तेजपात की खेती कर रहे हैं। मसाला उद्योग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले तेजपात उत्पादन में किसानों की रुचि को देखते हुए अब भीमताल व ओखलकांडा क्षेत्र में 17 एरोमा कलस्टर विकसित किए जाएंगे, जिसमें 786 कृषकों की 183 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को तेजपात की खेती से आच्छादित करने के लिए चयन किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में तेजपात उत्पादन का एक बाजार तैयार होगा। जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

यहां बनेंगे 17 एरोमा कलस्टर : विकासखंड भीमताल के ग्राम मंगोली, भेवा, नलनी, जलालगांव, एवं खमारी, सूर्यागांव, दोगड़ा, जंतवाल गांव, चोपड़ा, भल्यूटी, बडैत, हैड़ाखान, स्यूड़ा और ओखलकांडा ब्लाक के भदरेठा, मटेला, पुटपुड़ी, अडगांव तल्ला, साल, भनपोखरा, डालकन्या, देवली, भद्रकोट एवं तुषराड सहित अन्य गांवों में 17 एरोमा कलस्टर विकसित किए जाएंगे।

जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित होंगे किसान : एरोमा कलस्टरों में चयनित कृषकों को जैविक खेती करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ कर दिए गए हैं। योजना के तहत सगंध पौधा केंद्र कृषकों को जैविक खाद एंव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट पिट एवं स्प्रे मशीन निशुल्क वितरित होंगी। तेजपात की जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद की विशिष्ट पहचान स्थापित होगी, जिससे उत्पादकों को इसका मूल्य भी अधिक मिलेगा।

क्या है उपयोग : तेजपात की पत्ती व छाल दोनों का उपयोग किया जाता है। पत्तियों की सबसे अधिक खपत मसाला उद्योग में होती है। पत्तियों को सीधे मसाले के रूप में प्रयोग होता है और पत्तियों से मिलने वाले सुगंधित तेल का भी सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होता है।

प्रतिवर्ष 30 क्विंटल पत्तियों का उत्पादन: पौधरोपण करने के पांच साल बाद तेजपात की फसल मिलनी शुरू हो जाती है। एक हेक्टेयर में ही प्रतिवर्ष तकरीबन 30 क्विंटल पत्तियों का उत्पादन होता है। जिससे किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.50 लाख की आय होती है।

प्रदेश में उत्पादन : प्रदेश में लगभग 6200 किसान तेजपात उत्पादन से जुड़े हैं। जिसमें 365 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तेजपात की खेती की जा रही है। जिससे 900 टन पत्तियों का उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है।

जिले में 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तेजपात की हो रही खेती। प्रतीकात्मक

सगंध पौध केंद्र (कैप) ने परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत नैनीताल के भीमताल व ओखलकांडा ब्लाक के गांवों का चयन किया है। उत्तराखंड में उत्पादित तेजपात अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण अन्य राज्यों के तेजपात से भिन्न है। जिसकी अन्य राज्यों में भी मांग है।

- नृपेंद्र चौहान, प्रभारी वैज्ञानिक, सगंध पौधा केंद्र, देहरादून

तेजपात की खेती के फायदे

- एक बार रोपाई के बाद लगभग 30-40 वर्षों तक फसल की प्राप्ति
- बहुवर्षीय होने के कारण प्रति वर्ष रोपाई से छुटकारा
- खरपतवार की समस्या नहीं
- बाजार में निरंतर मांग से अच्छे दाम
- बाउंड्री, खेत की मेड़ों, बागों तथा पहाड़ी ढलानों में होने वाली फसल
- तेजपात एक सदाबहार वृक्ष है, जो मृदाक्षरण रोकने व पर्यावरण संरक्षण में सहायक है।

मौसम विशेष

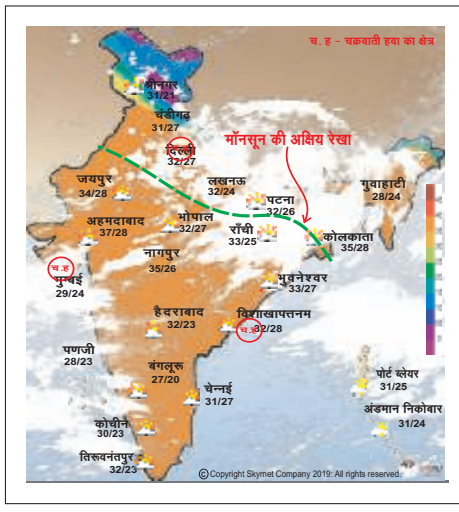

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/24/व	अहमदाबाद	31/26/व
कोलकाता	33/27/व	बड़ौदा	32/26/व
चेन्नई	32/23/व	नागपुर	30/25/व
हैदराबाद	30/23/व	इन्दौर	32/24/व
बंगलूरू	28/20/आंबा	रांची	30/25/व
त्रिवेन्द्रम	32/24/आंबा	पटना	33/25/व
गुवाहाटी	30/25/व	जमशेदपुर	32/27/आंबा
गंगटोक	16/08/व	पुणे	23/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 25 जुलाई 2019
आजकल
14
www.jagran.com

दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ने ब्रिटेन में लिया जन्म

1978 में आज ही विश्व के पहले टेस्ट-ट्यूब बेबी ने ब्रिटेन में जन्म लिया। इन-विट्रो-फर्टिलाइजेशन या आइवीएफ इलाज के माध्यम से लुई ब्राउन नाम की यह टेस्ट ट्यूब बेबी आधी रात के बाद पैदा हुई थी। बच्ची का वजन ढाई किग्रा था। इसके बाद ब्रिटेन में करीब पांच हजार लोगों ने इस इलाज को अपनाया।

अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली महिला बनीं स्वेतलाना

1984 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्सकाया अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली महिला बनीं। 3 घंटे, 35 मिनट तक अपने स्पेस स्टेशन से बाहर इन्होंने वेल्डिंग का काम किया। 1982 में अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी महिला का खिताब भी इन्हीं के पास है।

जाने-माने शिकारी और पर्यावरणविद् थे जिम कॉर्बेट

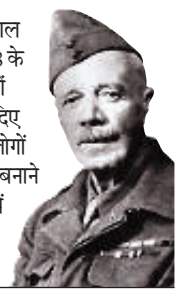

ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ। वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे। 1907 से 1938 के बीच कुमाऊं और गढ़वाल के गांवों में नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का आतंक था। उन्हें उस समय नरभक्षी बाघों का शिकार करने के आदेश दिए जाते थे। उन्होंने जिस पहले नरभक्षी बाघ का शिकार किया था, वह 436 लोगों को मार चुका था। इसके बाद बाघों के संरक्षण के लिए एक नेशनल रिजर्व बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई और फिर 1957 में इस पार्क को उन्हीं के सम्मान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दे दिया गया। 19 अप्रैल, 1955 को दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

घर में छापे नोट से पहुंची खरीदने ऑडी

बर्लिन, एजेंसी : महंगी गाड़ियों से चलने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक महिला ने घर में ही नकली नोट छाप लिए। बेधड़क निकल पड़ी पसंदीदा ऑडी खरीदने। मामला जर्मनी का है। 20 साल की महिला ने घर में लगे सामान्य प्रिंटर से 15 हजार यूरो के नकली नोट छापे और ऑडी का मनपसंद ए 3 2013 मॉडल खरीदने डीलर के पास गई। आसानी से पहचाने जा सकने वाले नकली नोटों को पूरे आत्मविश्वास के साथ डीलर के सामने रखा। पहले तो डीलर ने समझा कि महिला मजाक कर रही है। लेकिन महिला के अड़े रहने पर उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी में नकली नोट चलाने के पहले अपराध के लिए न्यूनतम तीन महीने की सजा है जबकि नकली नोट चलाने वाले पेशेवरों के लिए यह सजा दो साल तक हो सकती है।

शोध अनुसंधान

धीमी चाल भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत

बढ़ती उम्र के साथ चलने की धीमी पड़ रही चाल को नजरअंदाज नहीं करें। यह भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों को आने वाले आठ साल में चलने-फिरने में असमर्थता का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रति एक नए अध्ययन में आगाह किया गया है। यह अध्ययन अमेरिकन जेरीएट्रिक्स सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बुजुर्गों के चलने-फिरने की गति पर कई सालों तक गौर किया गया। यह अध्ययन 70 से 79 साल की उम्र के प्रतिभागियों के एक समूह पर किया गया था। इन लोगों को चलने या चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अध्ययन में इन्हें विभिन्न और चुनौतीपूर्ण रास्तों पर चलने को कहा गया और समय-समय पर इनके चलने की क्षमता का आकलन किया गया। समय के साथ इनके चलने की क्षमता में गिरावट पाई गई। आठ साल के बाद इन प्रतिभागियों में से आधे से ज्यादा में चलने-फिरने में असमर्थता पाई गई। -एएनआइ

सिगरेट छोड़ने के 30 साल बाद भी धमनी रोग का खतरा

सिगरेट पीने वालों के साथ ही इसको तौबा कर चुके लोग भी सचेत हो जाएं। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि स्मोकिंग छोड़ने के 30 साल बाद भी धमनी से जुड़े पेरीफेरल आर्टरी डिजीज (पीएडी) का खतरा रहता है। इस बीमारी के चलते धमनी संकरी हो जाती है। इससे शरीर के अंगों में रक्त के प्रवाह में कमी आ जाती है। अमेरिका के जांस हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं के अनुसार, रक्त का संचार कम होना दर्द का कारण बनता है और जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। उन्होंने हृदय रोग और स्ट्रोक की तुलना में स्मोकिंग और पेरीफेरल आर्टरी डिजीज के बीच ज्यादा गहरा जुड़ाव भी पाया। यह निष्कर्ष 13,355 प्रतिभागियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इन पर करीब 26 साल तक गौर किया गया था। इन प्रतिभागियों में 4,185 लोग ऐसे थे, जो सालों पहले ही स्मोकिंग को तौबा कर चुके थे। -प्रेट्र

हाथ में चांद, पांव तले जलवायु परिवर्तन

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- चांद पर पहुंचने की होड़ में पृथ्वी को कर रहे नजरअंदाज
- जलवायु परिवर्तन को नहीं माना जा रहा गंभीर समस्या

जलवायु परिवर्तन को लेकर अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं हम। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन : करीब 50 साल पहले 16 जुलाई, 1969 को किसी धरती वासी ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की इस सफलता के बाद कई देश चांद पर पहुंचने की होड़ में लग गए। कई के प्रयास असफल हुए, लेकिन रूस और चीन चांद पर अपना यान उतारने में सफल हुए। अब भारत भी चंद्रयान-2 के जरिये चांद की जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ गया है। इन सब से साबित होता है कि इंसान यदि ठान ले और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करे तो वह कोई भी मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने, दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढ़ने और नई तकनीक विकसित करने की रेस में हम शायद अपनी धरती को ही भूल गए हैं। हमने चांद को तो अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन पृथ्वी की समस्याएं कहीं दब गई हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी कई समस्याओं के सिर उठाने के कारण आज धरती का अस्तित्व ही खतरे में है, लेकिन न तो हम इसे असल समस्या मान रहे हैं न ही इसे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।

1961 में नासा ने चंद्रमा पर मानव भेजे जाने के मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। इस मिशन को लेकर अमेरिका के तात्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने कहा था, 'हमने चांद को चुना है और इसलिए चुना है, क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल है। इस लक्ष्य को पाकर हम अपनी क्षमता और ऊर्जा का पता लगा सकेंगे।' केनेडी ने जब चंद्रमा पर पहुंचने के मिशन को अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताया तो उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि 'चंद्रमा का अस्तित्व है या नहीं'। हालांकि जलवायु परिवर्तन के मामले में इसका उल्टा है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर नहीं है गंभीरता : वर्तमान में दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन सबके विपरीत प्रभाव भी हमारी आंखों के सामने हैं। बाढ़, सूखा, तूफान, आगजनी सुनामी जैसी आपदाएं विकराल रूप ले रही हैं। इसके बावजूद कई बार जलवायु परिवर्तन की समस्या को फर्जी बता दिया जाता है। कई देश इससे निपटने के लिए गंभीर कदम उठाने को तैयार ही नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मत है। इसलिए उन्होंने अमेरिका को 2015 के पेरिस समझौते से भी अलग कर दिया है। इस समझौते के तहत 195 देशों ने पृथ्वी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का संकल्प लिया था।

क्या किसी भीषण त्रासदी का है इंतजार? : जलवायु परिवर्तन को गंभीर समस्या मानने के लिए क्या हम किसी भीषण त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? हिमनदों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी होने और उससे कई द्वीपीय देशों के जलमग्न हो जाने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है, लेकिन हम शायद तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे जब तक कि कोई देश या शहर सच में पानी में नहीं डूब जाता है।

एक सेब में 10 करोड़ बैक्टीरिया

स्पेक्ट्रम

- ऑस्ट्रिया के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने

अध्ययन में परंपरिक सेब की तुलना में जैविक सेब को बेहतर बताया गया है। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : सेहत के लिए सेब को बहुत अच्छा बताया जाता है। कहा भी जाता है कि एक सेब रोज खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक नवीन अध्ययन में इससे जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि फाइबर और विटामिन के अलावा एक सेब में 10 करोड़ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। अब ये बैक्टीरिया सेहत के लिए अच्छे होते हैं या बुरे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेब को किस तरह उगाया गया है।

फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए इस अध्ययन में जैविक (आर्गेनिक) सेब को बेहतर बताया गया है। अध्ययन के मुताबिक, जैविक सेब एक अधिक विविध और संतुलित जीवाणु समुदाय को पोषित करते हैं, जो उन्हें पारंपरिक सेब की तुलना में स्वस्थ और स्वादिष्ट बना सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं।

ऑस्ट्रिया स्थित ग्राज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर गेब्रियल बर्ग कहते हैं, 'ये सभी बैक्टीरिया, कवक और वायरस जो हम खाते हैं, वे जाकर हमारे पेट में इकट्ठा हो जाते हैं। खाने को पकाने की वजह से इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। इसलिए कच्ची सब्जियां और फल गट माइक्रोब्स (आंत रोगाणुओं) का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।' हम अच्छे फलों का चुनाव कर सकें, इसके लिए शोधकर्ताओं के दल ने दुनिया के एक सबसे पसंदीदा फल यानी सेब के माइक्रोब्स का विश्लेषण किया। इसके आधार पर बर्ग कहते हैं, 'सेब का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे नवीन अध्ययन से पता चला है कि इनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया की जानकारी अभी कम ही है।'

बर्ग कहते हैं, 'औसतन एक 240 ग्राम के सेब में 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया उसके बीज में पाए जाते हैं।' शोधकर्ताओं ने अध्ययन में यह भी पाया कि सेहत के लिए जैविक सेब ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत तरह के और संतुलित रूप में बैक्टीरिया पाएं जाते हैं जो कि उन्हें पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले सेब से ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं।

एचआइवी के इलाज की जगी उम्मीद

आविष्कार ▶ वैज्ञानिकों ने विकसित की माचिस की तीली के आकार की डिवाइस

शरीर में प्रत्यारोपण के बाद एक साल तक नहीं लेनी पड़ेगी कोई अन्य दवा

नई डिवाइस से दवा के ओवरडोज का खतरा भी कम हो जाएगा। प्रतीकात्मक

पेरिस, एएफपी : दुनियाभर के वैज्ञानिक एचआइवी की रोकथाम और उसके बेहतर इलाज की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। वे ऐसे उपचार तलाश रहे हैं, जिनसे एचआइवी मरीजों को आसानी से ठीक किया जा सके। अब इस दिशा में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने माचिस की तीली के आकार की एक ऐसी वैक्सीन युक्त डिवाइस विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिसे शरीर में प्रत्यारोपित करने के बाद एक साल तक एचआइवी के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इस डिवाइस का सफल परीक्षण कर यह दावा किया है। इस डिवाइस ने एचआइवी के इलाज की उम्मीद भी जगाई है। इसे उन मरीजों के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है, जो अभी तक गोलियों और टीकों पर निर्भर हैं।

मेक्सिको सिटी में आयोजित हुए 10वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय एड्स सोसाइटी सम्मेलन में शोधकर्ताओं ने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल के निष्कर्षों से पता चलता है कि इस डिवाइस के मदद से एचआइवी को फैलने से रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं ने जानकारी दी कि इस डिवाइस में एमके-8591 नामक एक मॉलीक्यूल (अणु) का उपयोग किया गया है, जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध एचआइवी प्रतिरोधी दवाओं के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा प्रभावी है।

शरीर में धीरे-धीरे दवा का रिसाव करती है यह डिवाइस : ग्लोबल क्लीनिकल डेवलपमेंट फॉर वायरोलॉजी के निदेशक माइक रॉबर्टसन के मुताबिक, यह डिवाइस शरीर में एक निश्चित मात्रा में धीरे-धीरे दवा का रिसाव करती है, ताकि संक्रमण का खतरा लंबे समय तक कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई बार दवा की ज्यादा मात्रा (ओवरडोज) से शरीर में कई तरह का संक्रमण फैल जाता है, लेकिन नई डिवाइस से संक्रमण का जोखिम कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एचआइवी के मरीजों को इससे बचने के लिए हर रोज दवा की एक गोली लेनी पड़ती है, लेकिन इस डिवाइस के प्रत्यारोपण के बाद एक साल तक किसी भी दवा को लेने की जरूरत नहीं होगी।

यूएन की रिपोर्ट में यह आया सामने : इस महीने संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि दुनियाभर में एड्स से होने वाली मौतों में 2010 के बाद से एक तिहाई गिरावट दर्ज की गई है। 2018 में लगभग 7,70,000 लोगों की मौत एड्स के कारण हुई थी। साथ ही रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व सहित कुछ क्षेत्रों में संक्रमण की दर में वृद्धि दर्ज की गई, जो चिंता का विषय है।

इनमें सबसे ज्यादा खतरा : रॉबर्टसन ने कहा कि प्रत्यारोपण और महीने भर की दवा की खुराक में लगभग एक समान ही संघटक मौजूद हैं, जो एड्स के पीड़ितों को ज्यादा विकल्प प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो लोग एड्स के कारण सबसे अधिक जोखिम में हैं, वे अलग-अलग समुदायों के हैं। अमेरिका और यूरोप में गे समुदाय के लोगों में नए संक्रमणों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन वैश्विक रूप से सर्वाधिक संक्रमण की दर अफ्रीका की महिलाओं में देखने को मिली है।

गोलियों और इंजेक्शन पर निर्भर मरीजों के लिए एक और विकल्प

अंतरराष्ट्रीय एड्स सोसाइटी के अध्यक्ष एंटोन पॉजनिएक के मुताबिक, प्रत्यारोपण संक्रमण से बचाव के लिए भविष्य में उन लोगों के लिए भी एक और विकल्प है जो अब तक गोलियों और इंजेक्शन का प्रयोग करते रहे हैं। इस डिवाइस का परीक्षण दूसरे चरण में केन्या, रवांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के वयस्कों में किया गया। अब तीसरे चरण के परीक्षण की तैयारियां की जा रही हैं। ग्लोबल एचआइवी वैक्सीन एंटरप्राइज के डायरेक्टर रोजर टैटॉड ने कहा कि यह नई डिवाइस एचआइवी के मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है। संभव है कि शोधकर्ता इस पर और अधिक प्रयोग करके इसे इतना बेहतर तैयार कर लें कि एचआइवी का उपचार आसानी से हो सके।

बच सकती है ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर!

ग्लेशियरों को पिघलने से बचाने के लिए वैज्ञानिक खोज रहे हैं रास्ता। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रक्रिया का पता लगाने का दावा किया है, जिसकी मदद से ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जर्नल नेचर कम्यूनिकेशंस में प्रकाशित इस अध्ययन में दावा किया गया है कि इसकी मदद से वैज्ञानिक समुदाय एक बेहतर मॉडल तैयार कर सकता है, जिससे ग्रीनलैंड की कम होती बर्फ को बचाया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक बड़ी वैश्विक समस्या है और इसी का परिणाम है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा (यूएसएफ) के प्रोफेसर टिम डिक्सन के मुताबिक, ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए एक मॉडल तैयार करना बड़ी चुनौती है। एक चीज जिससे हम अंजान हैं, वो यह है कि भविष्य में समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ेगा और ग्रीनलैंड की बर्फ कितनी तेजी से पिघलेगी।

इन चीजों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2016 में एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने उस वर्ष की गर्मियों में एक नया राडार सिस्टम लगाया, ताकि ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा जा सके। शोधकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने अपने इस अध्ययन में ऐसी बहुत सी जानकारियां एकत्र कीं, जिनके आधार पर ग्लेशियरों के पिघलने के कारणों और उनकी दर का पता चल सका। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनके इस अध्ययन की मदद से भविष्य में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को पिघलने से रोकने में मदद मिल सकती है।

लाल सागर में अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम

मध्य-पूर्व के महत्वपूर्ण देश जॉर्डन के अकाबा शहर में अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है। लाल सागर में बन रहे इस म्यूजियम के लिए टैंक, बख्तरबंद वाहन, एंबुलेंस और लड़ाकू हेलिकॉप्टर समेत करीब 20 सैन्य वाहन सागर की तलहटी में उतारे गए। हालांकि यह सब सैन्य सेवा से हटाए जा चुके हैं। म्यूजियम साइट बनाने वाली अकाबा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ने बताया कि सागर में उतारने से पहले इन सैन्य उपकरणों के सभी हानिकारक तत्व हटा दिए गए थे। इस म्यूजियम का उद्देश्य अकाबा डाइविंग रिजॉर्ट के लिए पर्यटकों को लुभाना है। उत्तरी लाल सागर अपने कोरल रीफ के लिए डाइविंग करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय स्थल है। रायटर

स्क्रीन शॉट

अब जैक्लिन ने लांच किया अपना यू-ट्यूब चैनल

बीते दिनों आलिया भट्ट ने अपना यू-ट्यूब चैनल लांच किया था। अब उनके नक्शे कदम पर श्रीलंकाई सुंदरी जैक्लिन फर्नांडीज भी चलती दिख रही हैं। उन्होंने भी अपना यू-ट्यूब चैनल लांच कर दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए यू-ट्यूब चैनल की जानकारी दी। अभिनेत्री के लाइव होते ही कमेंट सेक्शन में मैसेज का सैलाब उमड़ पड़ा। चैनल पर जारी किए गए पहले वीडियो में जैक्लिन के अब तक के सफर को दिखाया गया है, जिसमें अभिनेत्री के बचपन की झलक के साथ-साथ उनके परिवार से परिचय, उनका पहला रैंप वॉक, वह पल जब वह मिस श्रीलंका बनी थीं, पहले ऑडिशन समेत कई चीजों को शामिल किया गया है। वीडियो के लाइव होने के कुछ ही समय में सब्सक्राइबर की संख्या तेजी से बढ़ती नजर आई। जैक्लिन के यूट्यूब चैनल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वह न केवल सुंदरता और फैशन को कवर करेंगी बल्कि खुश रहने, डर पर काबू पाने, अपने सपनों को जीने, ट्रैवल और फिटनेस जैसी चीजों को भी कवर करेंगी। अभिनय की बात करें तो वह वेब शो 'मिसेज सीरियल किलर' के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, फिल्म 'किक 2' में एक बार फिर सलमान खान के साथ नजर आएंगी। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्देशित और निर्मित 'किक 2' इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी।

युवाओं की कहानियों पर दो और वेब सीरीज की तैयारी में गोल्डी

युवाओं पर आधारित वेब सीरीज 'रिजेक्ट्स' से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहे फिल्म निर्माता और निर्देशक गोल्डी बहल को ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी रास आया है। 'रिजेक्ट्स' के बाद वह दो और वेब सीरीज के निर्माण में जुट गए हैं। गोल्डी युवा लेखक नवनील चक्रवर्ती के उपन्यास 'मैरी मी स्ट्रेंजर' पर इसी नाम से वेब सीरीज बना रहे हैं। इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और शो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। यह शो किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा, यह अभी तक तय नहीं है। नवनील चक्रवर्ती का उपन्यास 'मैरी मी स्ट्रेंजर' बेस्टसेलर का खिताब पा चुकी 'स्ट्रेंजर त्रयी' के तीन उपन्यासों का पहला भाग है। इसके अलावा, गोल्डी प्रसिद्ध इजरायली शो 'स्टाइलिस्ट' का वेब सीरीज के तौर पर हिंदी में रीमेक करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने कॉपीराइट संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही शूटिंग भी शुरू करेंगे। खास बात यह है कि गोल्डी के ये दोनों शो भी युवाओं की जीवनशैली पर आधारित होंगे। इस बारे में बात करते हुए गोल्डी बहल ने कहा, 'हम जल्द ही दो और वेब सीरीज लाने वाले हैं, जो युवाओं की जीवनशैली पर आधारित होंगी।

तलाशी राह

16 हजार से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों की पड़ताल कर भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित किया जहरीले रसायनों का डाटाबेस

मानव शरीर पर रसायनों का प्रभाव जानना होगा आसान

चेन्नई स्थित गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने डाटाबेस तैयार किया है। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : पर्यावरण या फिर दैनिक जीवन से जुड़े उत्पादों के जरिये हर दिन हमारा संपर्क ऐसे रसायनों से होता है, जिनमें से कई सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इस तरह के रसायन उपभोक्ता उत्पादों से लेकर कीटनाशकों, सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं, बिजली की फिटिंग से जुड़े सामान, प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत विभिन्न चीजों में पाए जाते हैं। अब भारतीय शोधकर्ताओं ने ऐसे रसायनों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया है। इससे इन रसायनों के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना आसान होगा।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, कई हानिकारक रसायन मानव शरीर में हार्मोन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे शारीरिक विकास, चयापचय, प्रजनन, प्रतिरक्षा और व्यवहार पर विपरीत असर पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ऐसे रसायनों को स्वास्थ्य से जुड़ा प्रमुख उभरता खतरा बताया है। इस खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हार्मोंस के तंत्र को प्रभावित करने वाले ये रसायन पर्यावरण में मौजूद जहरीले रसायनों का सिर्फ एक उप-समूह हैं।

यह डाटाबेस रसायनों की कोई आम सूची नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य पर रसायनों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित शोधों के आधार पर तैयार की गई एक विस्तृत सूची है। इनमें से अधिकतर शोधों में रसायनों का परीक्षण मनुष्य के अलावा अन्य जीवों पर भी किया गया है। चेन्नई स्थित गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने यह डाटाबेस विकसित किया है।

इस तरह किया विकसित : इस डाटाबेस को विकसित करने के दौरान अंतःस्रावी अवरोधक रसायनों से जुड़े 16 हजार से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों की पड़ताल की गई है। इस अध्ययन में मनुष्य के हार्मोन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले 686 रसायनों के बारे में शोधकर्ताओं को पता चला है। इनके संदर्भ 1796 शोध पत्रों में पाए गए हैं, जो रसायनों के कारण हार्मोंस में होने वाले बदलावों की पुष्टि करते हैं। DEDuCTनामक इस डाटाबेस का पहला संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है, जिसे निःशुल्क देखा जा सकता है।

यह मिलेगी जानकारी : कौन-सा हार्मोन अवरोधक रसायन, किस मात्रा में मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसकी जानकारी इस डाटाबेस में मिल सकती है। इसके साथ ही, यह भी पता लगाया जा सकता है कि अध्ययनों में रसायन का परीक्षण मनुष्य या फिर किसी अन्य जीव पर किया गया है। रसायनों की मात्रा की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई रसायनों की बेहद कम मात्रा से भी शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इस डाटाबेस से किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, भौतिक रासायनिक गुण और रसायनों के आणविक विवरणक प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्ययन दल का नेतृत्व कर रहे, गणितीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता अरिजित सामल ने बताया, 'हमने विभिन्न शोध पत्रों में प्रकाशित प्रायोगिक प्रमाण के आधार पर अंतःस्रावी अवरोधक रसायनों की पहचान की है, और उनकी खुराक की जानकारी के साथ-साथ उनके प्रतिकूल प्रभावों का संकलन किया है। यह जानकारी इन रसायनों द्वारा अंतःस्रावी व्यवधान के तंत्र को समझने की दिशा में विष विज्ञान अनुसंधान में उपयोगी हो सकती है।'

लिंग आधारित भेदभाव समाप्त होना चाहिए : तापसी

आमतौर पर बॉलीवुड में पुरुष अभिनेता को हीरो माना जाता है। लेकिन हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपना मुकाम हासिल कर चुकीं अभिनेत्री तापसी पन्नू का कहना है कि मेरा लक्ष्य लिंग आधारित स्टीरियोटाइप परंपरा को खत्म करना है और मैं इस दिशा में धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा रही हूं।

31 वर्षीय अभिनेत्री ने यह भी कहा, 'यदि दर्शक और फिल्म इंडस्टी महिला प्रधान फिल्मों को स्वीकार करें, तो इससे पुरुष एवं महिला कलाकारों के बीच का अंतर दूर हो सकता है और बॉक्स ऑफिस पर ऐसी फिल्मों को सफलता मिल सकती है।' उन्होंने कहा, 'मेरे विचार से हीरो का कोई लिंग नहीं होता है और मैं इसी बात को साबित करने का प्रयास कर रही हूं। हमने कई वर्षों से अपने दर्शकों को यही बताया है कि हीरो लिंग आधारित होता है और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। अब इसमें बदलाव एक रात में नहीं किया जा सकता है और यह धीरे-धीरे ही संभव है। इसमें सभी महिला कलाकारों की ओर से समर्पण की भावना की जरूरत होगी, जो इसमें बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं।' तापसी ने अपनी पिछली फिल्म 'गेम ओवर' का उदाहरण देते हुए बताया कि यह फिल्म भले ही 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित होगी, इसलिए दूसरे लोग भी भविष्य में जोखिम उठाएंगे।